YSR-NB/11.00/1A

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

MR. CHAIRMAN: Question No. 361.

प्रश्न संख्या 361

श्री राजनीति प्रसाद : सभापति जी, मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत नाराज़ कर दिया है। प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है - No. मैं यह जानना चाहता हूं whether the Minister thinks that teeth are not part of our body. इसमें अगर बीमारी है, तो क्या इसका CGHS के अंतर्गत इलाज कराना संभव नहीं है? मेरा प्रश्न वही है, मैं उसी का सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद : जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह part of body है, तो क्यों नहीं यह CGHS में count होगा? जहां तक आपने यह कहा है कि हम AIIMS के रेट्स के आधार पर उसका reimbursement करेंगे, तो AIIMS के रेट्स तो 200 रुपए, 250 रुपए हैं। अगर ये cavities भरेंगे या दांत में कुछ प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करेंगे, तो उसमें बहुत पैसा लगता है और आपने जो रेट्स निर्धारित किए हैं, उनसे कैसे काम चलेगा, यह मेरा प्रश्न है।

श्री दिनेश त्रिवेदी : सभापति जी, प्रश्न यह है कि डेंटल चिकित्सा का reimbursement होता है या नहीं और इसके उत्तर में हमने कहा है कि हां, इसका reimbursement होता है, मगर उसमें रेट की कुछ लिमिट है, कुछ सीमा है और सीमा यही है कि CGHS का एक निर्धारित रेट होता है, यदि वह रेट AIIMS में नहीं पाया जाता है या उसका कोई रेफरेंस प्वाइंट नहीं होता है, तो फिर हम लोग उसके लिए एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन होगा यह कि आपका रेट, एक टैक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी कि इसका क्या रेट होना चाहिए और वह चिकित्सा, कॉस्मेटिक चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। एक चिकित्सा होती है 'just to look good' और दूसरी होती है 'necessity' के लिए। इसलिए जहां

तक CGHS का सवाल है, वह 'necessity' का सवाल है, हम उसी के तहत रेट डिसाइड करते हैं, मगर उसका reimbursement जरूर होता है।

श्री राजनीति प्रसाद : सभापति जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल यह है कि आपने इसमें बच्चों को भी शामिल किया है, अगर बच्चे का दांत टेढ़ा-मेढ़ा है, दांत निकला हुआ है और अगर उसका इलाज हो सकता है, उसको सीधा किया जा सकता है, तो क्या बच्चे को अच्छा दिखने का कोई right नहीं है? दांत ऐसा निकला रहेगा, उधर निकला रहेगा, तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने बच्चे को उसमें जोड़ा है कि बच्चे को भी वही सुविधा मिलेगी, तो इसका इलाज क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या खराबी है? सबके दांत खूबसूरत होने चाहिए, सबके दांत आपकी तरह तो नहीं हैं, काफी लोगों के दांत गड़बड़ होते हैं, इधर-उधर होते हैं, इसलिए अगर बच्चे का दांत टेढ़ा-मेढ़ा है, तो उसको CGHS के अंतर्गत ठीक कराने में दिक्कत क्या है, यह मेरा सवाल है।

श्री दिनेश त्रिवेदी : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि एक कहावत है कि - "हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और।" दिखाने वाले जो दांत होते हैं ... (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आदमी के दांतों के साथ हाथी कहां से आ गया ... (व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, the thing is, if teeth are required for your body function..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt. (Interruptions) Please don't interrupt.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, if the House has lost humour, then it is very sad. Humour is life and teeth are also required to show your 'Binaca smile.' In all seriousness, Sir, there are two functions of teeth. I don't have to really explain those things. Everybody knows it. One is essential part which is required for your function of life, in terms of eating food. The other, which is not functional, is not required.

(Contd. By VKK/1B)

Q. No.361 (Contd.)

SHRI DINESH TRIVEDI (CONTD.): And I have not decided this. The Technical Committee, which knows more about the technicalities, has decided this. So, the answer still remains the same that whether they are children or grown-ups, CGHS does provide for reimbursement. Here, I must tell you, the problem is, yes, the AIIMS rates are very, very low. There were only ten procedures. Now, we have included 55 new procedures and for these 55 new procedures, we have just sent out the tenders. Very shortly, the tenders will come. So, in all, instead of only ten procedures, we will have 66 procedures. In these 66 procedures, I am sure, most of the requirements as far as the dental care is concerned will come into being.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी टीथ वगैरह के बारे में बताया गया है, उसी तरह से आई लेंस की कीमत भी "एम्स" वगैरह में बहुत कम लगाई गई है, क्या इन सबको दोबारा review करने की कोशिश करेंगे? यह बात ठीक है कि CGHS बहुत अच्छा काम रहा है, लेकिन यह कुछ ही प्रदेशों में है, जैसे हिमाचल प्रदेश में CGHS की सुविधा नहीं है। जब कि वहां इतने ex-servicemen रहते हैं। क्या वहां CGHS खोली जाएगी, ताकि जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको भी इसकी सुविधा मिल सके?

SHRI DINESH TRIVEDI: Mr. Chairman, Sir, there is a continuous process of review. So, there is no particular reason to review a particular thing at this point in time. Sir, review or addition is an on-going process.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, मैंने दूसरा सवाल हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा था, उसका जवाब नहीं आया ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: No, no. One question please.

डा. सी. पी. ठाकुर : सर, यह जो बच्चों का irregular teeth का प्रोब्लेम है, यह इतना कॉमन हो गया है कि इसको disease में लेना चाहिए। चूंकि हमारा chewing habit बदल गया है, soft चीज खाते-खाते खाने का habit बदल गया है, इसलिए हमारा jaw छोटा हो गया है। आज सभी बच्चों को teeth में कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस पर कोई Technical Committee वगैरह बनाकर इसको consider किया जाए?

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, the hon. Member is not only a doctor but was also the ex-Health Minister, and we would welcome his suggestions to improve the entire dental care.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में CGHS के चार जोन हैं, जिनमें मात्र दो डेंटिस्ट उपलब्ध हैं, जब कि इसके अंतर्गत 90 डिस्पेंसरीज हैं। क्या दो डेंटिस्ट चार जोन के सभी patient को attend कर पाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि क्या डेंटिस्टों की संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है?

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, at the moment, there are no such schemes. But, if there is a particular place where the hon. Member feels that there are more patients than doctors, then, we are always open to such suggestions and comments, and we certainly would like to look into the matter.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, चार जोन में दो ही डेंटिस्ट हैं ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आपका सवाल हो गया है।

(समाप्त)

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति महोदय, आजादी के बाद हिन्दुस्तान में रुरल डेवलपेंट के लिए काफी काम हुए, क्योंकि 70 फीसदी आबादी गांव से ताल्लुक रखती है। इस वक्त "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के तहत इतना बड़ा काम हो रहा है, इसमें लगभग चार करोड़ से ज्यादा households आते हैं। इसमें जो important components हैं, वे स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे रुरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास हैं। अब जो माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं, वह बहुत अच्छी सोच है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ coordinate करें। (1c/MP पर जारी)

MP-MKS/1C/11.10

श्रीमती मोहसिना किदवई (क्रमागत) : उसको भी लेकर जितनी rural development की स्कीमें चल रही हैं, उनमें से जितनी भी देहात से ताल्लुक रखती हैं, चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, बालवाड़ी हो, आंगनवाड़ी हो, school buildings हों, उन सबको इसमें लिया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे duplication भी रुकेगा और काम भी अच्छा होगा, लेकिन इसमें जो दो-तीन बहुत important components हैं, एक तो cooperation of the State Governments, coordination, cooperation on monitoring, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस स्कीम के तहत कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने expansion मांगा और आपने नरेगा के तहत कुछ फील्ड्ज़ में उनको expand करने की इजाज़त भी दी है। इस वक्त दुनिया में हमारा वाहिद मुल्क है, जहां रूरल रीकंस्ट्रक्शन मिशन इतने ज़ोरदार तरीके से काम कर रहा है और सबसे बड़ी स्कीम हमारे देश में है। महोदय, इतनी बड़ी स्कीम के लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और बहुत मज़बूती के साथ monitoring की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उसके लिए इनकी मिनिस्ट्री का क्या प्लान है?

محترمہ محسنہ قدوائی : سبھا پتی مہودے، آزادی کے بعد ہندوستان میں رورل ڈیولپمنٹ کے لئے کافی کام ہوئے، کیوں کہ 70 فیصدی آبادی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت "راشٹریہ گرامین روزگار گارنٹی یوجنا" کے تحت اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس میں لگ بھگ چار کروڑ سے زیادہ ہاؤس-ہولڈس آتے ہیں۔ اس میں جو important components ہیں، وہ اسٹیٹ گوورنمنٹس اور ہمارے رورل ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہیں۔ اب جو مائنّے منتری جی سوچ رہے ہیں، وہ بہت اچھی سوچ ہے کہ دوسری منسٹریز کے ساتھہ کو-آرڈنیٹ کریں۔ اس کو بھی لے کر جتنی رورل ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں چل رہی ہیں، ان میں سے جتنی بھی دیہات سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ پردھان منتری سڑک یوجنا ہو، بالواڑی ہو، آنگن واڑی ہو، اسکول بلڈنگس

ہوں، ان سب کو اس میں لیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے duplication بھی رہے گا اور کام بھی اچھا ہوگا، لیکن

Q. No. 362 (Contd.)

اس میں جو دو-تین بہت important components ہیں، ایک cooperation of the State Governments, coordination, cooperation on monitoring, تو میں مانّئے منتری جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس اسکیم کے تحت کچھ اسٹیٹ گوورنمنٹس نے expansion مانگا اور آپ نے نریگا کے تحت کچھ فیلڈز میں ان کو expand کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہمارا واحد ملک ہے، جہاں رورل ری-کنسٹرکشن مشن اتنے زوردار طریقے سے کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی اسکیم ہمارے دیش میں ہے۔ مہودے، اتنی بڑی اسکیم کے لئے کو-آرڈنیشن، کو-آپریشن اور بہت مضبوطی کے ساتھ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے میں مانّئے منتری جی سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے لئے ان کی منسٹری کا کیا پلان ہے؟

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस स्कीम को लागू करने में सहयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसको address करने के लिए भारत सरकार ने उनको कुछ निर्देश दिया है कि लोकपाल का concept अपने स्टेट्स में

लागू करें और सारे स्टेट्स से हमने रिक्वेस्ट की है कि लोकपाल के जो नियम हमने बनाए हैं, उनको ठीक ढंग से लागू करें।

जहां तक UCs हम लेते हैं, उसमें भी हमने उनसे कहा है कि वहां पर हमें पूरी जानकारी दें कि fund utilisation किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वहां implementation में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं। हमने MIS develop किया है, इस MIS के माध्यम से हम जानकारी लेकर उनको समय-समय पर directions देने का काम कर रहे हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स को समय-समय पर यह निर्देश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस स्कीम को ठीक ढंग से लागू करने के लिए पंचायत को ज्यादा activate करें। इस Act में यह प्रोविज़न किया गया है कि वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति और ज़िला परिषद को स्वयं अपनी योजना बनानी है और योजना बनाकर उसको लागू करना है। इसलिए हम सरकारों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि नरेगा के माध्यम से लागू करने के लिए जो Panchayat Act में प्रोविज़न किए गए हैं, उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करें और स्टेट गवर्नमेंट्स खुद अपना redressal mechanism develop करें। सोशल ऑडिट का concept

हमने लागू किया है और पंचायतों को अधिकार दिया है कि सोशल ऑडिट करें। इस ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के कोऑपरेशन के साथ इस योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित कर सकें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि जो अखबारात में आता है और आपके बयानात भी आते हैं कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा खर्च नहीं कर रही हैं और बड़े ताज्जुब की

Q. No. 362 (Contd.)

बात है कि वे स्टेट्स, जहां गरीबी बहुत है, जैसे बिहार, यू.पी., वहां सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है। आपने तीन साल में आपने बहुत काम किया है, लेकिन आपने कोई evaluation कराया है? तीन साल के अंदर आपको क्या कमियां नज़र आईं? जैसे आपका जो फंड जाता है, उसमें administration पर कितना खर्च होता है और wages पर कितना खर्च होता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, जिनको evaluate करना चाहिए। मेरा सवाल एक और है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 50 परसेंट महिलाएं इसमें भाग लेती हैं और उनको wages दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अब 4 करोड़ से ज्यादा households इसमें हैं। दूसरी तरफ आपके Self Help Groups भी काम कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर काम में बहुत potentiality है, काम किया जा सकता है, तो ये जो हमारी 50 परसेंट महिलाएं काम कर रही हैं और जो Self Help Groups हैं, इनको बहुत ही gradually wage employment से self employment की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस सिलसिले में आपकी कोई प्लानिंग है कि इस wage employment को self employment में बदल दिया जाए?

محترمہ محسنہ قدوائی : سر، میرا دوسرا سپلیمنٹری کوئشچن یہ ہے کہ جو اخبارات میں آتا ہے اور آپ کے بیانات بھی آتے ہیں کہ بہت سی اسٹیٹ گوورنمنٹس پیسہ خرچ نہیں کر رہی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ اسٹیٹس، جہاں غریبی بہت ہے، جیسے بہار، یو۔پی۔، وہاں سب سے کم پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ نے تین سال میں آپ کے بہت کام کیا ہے، لیکن آپ نے کوئی evaluation کرایا ہے؟ تین سال کے اندر آپ کو کیا کمیاں نظر آئیں؟ جیسے آپ کا جو فنڈ جاتا ہے، اس میں administration پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور wages پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جن کو evaluate کرنا چاہئے۔ میرا سوال ایک اور ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری 50 فیصد مہیلائیں اس میں بھاگ لیتی ہیں اور ان کو wages دئے جاتے ہیں۔ میں مانّئے منتری جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اب 4 کروڑ سے زیادہ ہاؤس-ہولڈ اس میں ہیں۔ دوسری طرف آپ کے Self Help Groups بھی کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کرکام میں بہت potentiality employment کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں مانّئے منتری جی سے

جاننا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی پلاننگ ہے کہ اس wage employment کو self employment میں بدل دیا جائے۔

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, इस Act के Objective में यह बात लिखी हुई है कि हम यह assure कर रहे हैं कि उनको unskilled manual work के लिए 100 days का काम देंगे। इसलिए जहां तक यह बात है कि उनको skill के साथ या wage employment के साथ जोड़ें, इस

Q. No. 362 (Contd.)

Act की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस demand-driven scheme में हमने यह प्रोविज़न किया है कि हम assure करते हैं कि 100 days का manual work आपको देंगे। अब उनको आकर काम लेना है, पंचायत में application देनी है, उसके बाद हम काम देते हैं। इसलिए हम इसको wage के साथ तभी लिंक कर सकते हैं, जब काम करने वाले लोग इसके साथ आएं, लेकिन सभापति महोदय, एक बात बिल्कुल सही है कि 2008-09 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, केवल मात्र 14 परसेंट ऐसे लोग हैं, जो 100 days का काम कर रहे हैं। इसका मतलब 15 करोड़ लोग eligible हैं, उसमें से 14 परसेंट लोग काम कर रहे हैं। यह इस बात को indicate करता है कि हमारे पास रूरल इलाके में 14 परसेंट लोग ही manual work में काम करना चाहते हैं। (1D/GS पर क्रमशः)

-MP-GS-TMV/1D/11.15

श्री सी0पी0 जोशी (क्रमागत) : बाकी लोग मैन्युअल वर्क में काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए gradualy इस मैन्युअल वर्क को unskilled के अंदर हम include करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसको करेंगे। अभी हम इसको ठीक ढंग से इवैल्युएट कर रहे हैं। जितना हमने स्कोप बढ़ाया है, उतना in-put लेने के बाद हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।

SHRI M. RAMA JOIS: Mr. Chairman, Sir, as a result of want of employment and sufficient income, and basic amenities people from many villages are migrating to the urban areas. It is adversely affecting agriculture and also sustenance and development of village industries. What steps are being taken to prevent migration of the people from villages to urban areas?

SHRI C. P. JOSHI: The Scheme has already given them opportunities for not moving from the rural areas to the urban areas. So, this is the Scheme where these people are not going to the urban areas. They are staying in the rural areas. In fact, we are addressing the question which you have asked.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I want to know from the hon. Minister this. The Ministry, the Government, is committed to implementing daily wages of Rs.100. We raised this question last time also. We didn't receive any reply. This is a specific question. There are other problems. I know that in the case of West Bengal Government there is a due of Rs.700 crores. The Ministry has not released that. But the specific question is this. When will this daily wages of Rs.100 be implemented?

Q. No. 362 (Contd.)

SHRI C.P. JOSHI: Sir, we have already issued instructions. From 1st April we have introduced it and they will be eligible for Rs.100. That notification has already been issued. (Interruptions)... It is from 1st April, 2009. (Interruptions)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए।

SHRI C. P. JOSHI: Sir, we have already issued the notification saying that they will be paid from 1st April, 2009. Rupees Hundred will be given to all those States who have recommended Rs.100. There are a few States which have not recommended up to Rs.100. One of the States is West Bengal. They have not requested for Rs.100. (Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, that is very wrong. You have not released the earlier request from West Bengal Government. If you recall, in January, they have made a request. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please, you can't ask supplementaries like this. (Interruptions)... Mrs. Karat, please resume your seat. (Interruptions)... This is not your question. (Interruptions)... This is not your question. (Interruptions)... Mrs. Karat, I am sorry. (Interruptions)... I am sorry that there will be no interventions when supplementaries are being asked. (Interruptions)...

SHRI C. P. JOSHI: They want to pay Rs.87. We are ready to pay Rs.100. (Interruptions)... Therefore, we are saying it. (Interruptions)... Till today the West Bengal Government did not demand Rs.100. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Mrs. Karat, this is not your question. (Interruptions)...

SHRI C. P. JOSHI: Till today the West Bengal Government demanded only Rs.87. We are ready to pay Rs.100. (Interruptions)... You are not paying Rs.100. That is the issue. (Interruptions)...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: That was earlier. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: If the answer is incorrect, there are procedures for pointing out that. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल : धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो scope of work खुदाई से और कौन-कौन क्षेत्रों में चला गया है ? इसके scope of work का विवरण इसमें विस्तार नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि एक जवाहर रोजगार योजना होती थी, जो राजीव गांधी जी के जमाने में लांच की गई थी और वह बहुत सफल रही थी। वह जवाहर रोजगार योजना कहां पर है, "नरेगा" की वजह से उसकी कहीं पर चर्चा नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जवाहर रोजगार योजना का विलय "नरेगा" में कर दिया गया है या यह योजना अभी है ? अगर है, तो कितना पैसा जवाहर रोजगार योजना के लिए स्वीकृत होता है ?

श्री सी0पी0 जोशी : सभापति महोदय, यह अलग से प्रश्न है। फिर भी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि नेशनल रूरल एम्पलाईमेंट स्कीम के अंतर्गत वह योजना समाहित हो गई है।

(समाप्त)

-TMV-GS/1D

प्रश्न संख्या - 363

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि M/s Balaji Bullion Bazar and M/s Balaji Bullion Corporation of Zaveri Bazar, Mumbai branch of the Union Bank of India में कैश ट्रांजेक्शन होते रहे और फिर आरबीआई ने वहां पर ऑब्जर्व किया कि वहां सरटेन वीकनेसिस हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क M/s Balaji Bullion Bazar and M/s Balaji Bullion Corporation of Zaveri Bazar में इन्होंने अकाउंट खोला। आपकी आरबीआई की गाइड लाइन्स हैं कि अगर किसी भी एकाउंट में, कहीं दस लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है..।

(1ई पर जारी)

VK-LP/1E/11.20

श्री एस.एस.अहलुवालिया (क्रमागत) : ..तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। हो सकता है कि उसमें कैटेगिरी हो कि डिफरेंट-डिफरेंट बिजनेस में आगे लिख देना कि इनकी कैश ट्रांजेक्शन होती है। हो सकता है कि जो बुलियन का बिजनेस करते हो, उनमें हैवी ट्रांजेक्शन होती है, वह भी रिमार्क बैंक वाले देते होंगे, परंतु आर.बी.आई. ने इसको कब पकड़ा? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ई.डी. ने जो इन्वेस्टिगेशन झारखंड में शुरू हुई थी, उससे वे जब मुंबई पहुंचे, तब पकड़ा या आर.बी.आई. के कहने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ई.डी. ने कार्यवाही शुरू की?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this is a regular practice. Whenever certain transactions are beyond threshold level, beyond Rs. 10 lakhs, as the hon. Member has rightly pointed out, then they are to report. There are three types of reports, that is, Cash transactions Reports, Suspicious Transactions Reports and if, sometimes, it comes to their knowledge that these particular transactions may lead to some sort of terrorist activity, then they are to report. This is a regular practice as

per Section 12 of the Prevention of Money Laundering Act which was passed by this House and the other House in 2002. As per the provisions of this Act, this is an obligation of banks and financial institutions. Each and every bank reports it to the Financial Intelligence Unit of India which is administered by the Taxation Department, the Revenue Department of the Government of India. In these cases also those reports were made. It was, obviously, as the hon. Member has correctly pointed out, done after the investigation was initiated by the Income Tax Department. In the course of investigation, certain information comes and they act on that information. So, they took these actions. The Reserve Bank of India's findings, which are the defects, are of technical nature. It is not that the bank concerned did not report. The Reserve Bank of India has issued guidelines, master guidelines and other guidelines. So it is the job and responsibility of the Reserve Bank of India, in the course of inspection, to see whether those instructions issued in the Master Circulars are being complied with and whenever it is found that they are not complied with, appropriate measure are being taken.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, the Minister is informing the House that the FIU acts on the basis of CTRs, STRs and CCRs. My point is the RBI is the custodian of 'KYC'. There is a Master Guideline to all the banks on "Know Your Customer'. That is to stop the terrorist account, the smuggler's account and the hawala account, and everything. The ED was aware. They were well aware that the same group, the Balaji Group of Co., in the name of Balaji Universal Trade, were already behind

the hawala trade, $ 110 million hawala trade, with a cartel based in Dubai. Despite that these accounts were opened. From 2006 to 2008, around Rs. 640 crores were deposited in the two accounts. Through the KYC, why wasn't it detected by the RBI and the FIU?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, KYC is a totally different concept. KYC is not an investigating agency. KYC is a norm which the bank has to follow, 'Know Your Customer'. That is all. (Interruptions).

(Followed by 1F)

RG/AKG/11.25/1F

SHRI S.S. AHLUWALIA: If I am blacklisted, then, how can I open an account?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am answering the supplementary. If you have more information and if you want to take the role of replying to the supplementaries, you are free to do so.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, आप नाराज मत होइए।

श्री प्रणब मुखर्जी : नाराज होने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि 'Know Your Customer'. Political parties, sometimes, issue a circular, 'Know Your Congressmen'. As a Congressman, I have issued such a circular. Therefore, it is a normal banking practice that when banks enter into financial transactions, they should know the customers; they should know whether entering into financial transactions with the customer is safe or not. The KYC is not an investigating agency. The investigating agencies, here, are the Enforcement Directorate, Income Tax Department, CBI, I.B., Narcotics Division, etc. So many Series of investigative agencies are there. As I have mentioned, under Section 12

of the Prevention of the Money Laundering Act, certain applications have been entrusted to the banks stating that if they notice certain transactions which are being done beyond the threshold level, -- it may happen on one occasion, or, it may happen repeatedly; there may be recurrences --, they should report to the Intelligence Unit of the Income-Tax Department. Thereafter, they will disseminate the information to the various authorities, that is, the investigative agencies.

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Bhushan Tiwari...(Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is not so simple...(Interruptions) My point is simple...

MR. CHAIRMAN: Your supplementary is over...(Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: If somebody's name is on alert, then, how can he open his account?

MR. CHAIRMAN: Please,...(Interruptions) अहलुवालिया जी, आपका सवाल खत्म हो गया।

श्री बृजभूषण तिवारी : सभापति महोदय, इतनी बड़ी राशि बैंक के खातों में जमा की गई और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आयकर विभाग की जाँच के बाद ही आरबीआई हरकत में आई। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसा Prevention of Money Laundering Act, 2002 में यह विधान है कि FIU की रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी दी जानी चाहिए, तो यूबीआई ने सरकार और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसकी सूचना रुपए जमा होने के कितने समय बाद दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, रुपए कितने थे और उसकी अद्यतन स्थिति (update), आज तक उसकी क्या प्रगति हुई है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is not possible to disclose the entire stages of investigation on the floor of the House. The

investigation is still on. But this is the normal practice, and these agencies are being informed by the intelligence unit about the information which has been disseminated, which it has received from the concerned banks and financial institutions. These agencies are the Directorate of Enforcement, CBDT, Central Board of Excise and Customs, Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, Ministry of Company Affairs, Central Bureau of Investigation (CBI), RBI, State Governments, Securities and Exchange Board of India (SEBI), and the Insurance Regulatory and Development Authority of India. Therefore, this dissemination of information takes place. In this particular case, the investigation process is still going on, and in the interest of the investigation to take its logical conclusion, it will not be proper to discuss all these things, though it will be discussed in the court after the investigation is completed.

(Followed by 1J)

1g/11.30/ks-sch

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मुझे अनुभव है कि बैंक में जब कैश इतनी बड़ी मात्रा में आता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। ऐसे में केवल खबर ही नहीं करनी होती है और केवल बैंक मैनेजर को सस्पैंड करके ही यह कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती है। जब इतनी बड़ी राशि आती है, तब डेली वह अपने हैड ऑफिस को या जहां पर वह ब्रांच कैश सब्मिट करती है, वहां रिपोर्ट देती है। एक ब्रांच से अगर 50 लाख रुपये सप्ताह वहां जमा हो रहे हैं और अचानक करोड़ों करोड़ रुपये आने लगें, तो large cash transactions are traced at all levels.

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए

श्री प्रकाश जावडेकर: मेरा सवाल यह है कि केवल बैंक मैनेजर को दोषी करार देना बहुत अपर्याप्त है। इसके लिए बैंक के हर लैवल पर, यानी Divisional level पर या Assistance Manager level पर, जहां इस सबकी पूरी रिपोर्ट होती है, वहां पर आज तक कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की गई है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, suspension is a step to take further action; suspension is not a dispensation of the entire procedure. The immediate person who was involved in it -- and the hon. Member is right that certain levels of transactions are not only to be reported to the Intelligence unit, but are to be reported as per the bank's normal practice to their higher authorities. And there were certain deficiencies. That is why, when it was found in investigation that, *prima facie,* this officer may be involved -- he was the then Branch Manager; presently he is in a higher position -- he was suspended because of certain deficiencies that occurred at that point of time. And after the investigation by the branch -- this investigation is different from that of the Income Tax -- as to what were the lapses, as per the Reserve Bank's findings, appropriate action would be taken.

श्री अमर सिंह: धन्यवाद, सभापति महोदय। इस बारे में मैं जरा हट कर एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण में, जिसमें मीडिया के द्वारा कैश के जमा करने और निकालने का विस्तृत विवरण आया है, इसमें हमने Union Bank of India की एक विज्ञप्ति की देखी है। इस विज्ञप्ति में उन्होंने सारे ट्रांज़ैक्शन को सही ठहराया है। क्या यह सच है? अगर ट्रांज़ैक्शन सही है, तो भ्रष्टाचार क्या सिर्फ मीडिया में ही है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, what appears in the media, only media persons can explain, not me. I am here to explain the action of the Government. As to the question whether the transaction is genuine,

or fake, whether it is of suspicious nature, whether it is linked with certain other criminal activities, unless the entire process of investigation is over, it is not possible for me to give any indication.

DR. K. MALAISAMY: Sir, in the reply, the hon. Minister has conceded that the RBI has observed certain weaknesses in the implementation of the Prevention of Money Laundering Act guidelines and certain suspicious transactions. So, as it is, the hon. Minister has conceded that there are certain weaknesses in the RBI guidelines. In such a situation, have you thought of any foolproof measures to pinpoint such of those weaknesses and correct the system?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this is a constant exercise. Those who try to take advantage of the deficiencies and weaknesses, surely try to find out some weakness. Whenever these weaknesses are found out, those are being rectified. After all, it is known to the hon. Member and to everybody in the House that offences like counterfeiting of coins, counterfeiting of notes and other such financial irregularities are as ancient as civilization; it is universal, all over the world. Therefore, whenever these deficiencies are found out -- we shall be dealing with that subject even in the next Question -- corrective steps are taken. That is why, periodical inspections by the RBI and other authorities are taking place regularly.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Question No. 364.

(Followed by tdb/1h)

Q. No. 364

DR. N. JANARDHANA REDDY: Sir, I don't know where the fault lies. Sir, the question was asked whether the Reserve Bank of India appointed committee has recently stated that the Central Bank should upgrade security features on currency notes. This is about the appointment of a committee. The answer is, "No, Sir." But, in reply to part (c) and (d), it is stated, "A Committee has been set up to review the acquisition procedure relating to security features..." So, the answer is contradictory.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, there is nothing contradictory in it. The Reserve Bank did not appoint the committee. I appointed the Committee. I am not the Reserve Bank. These are the two different entities. The Government appointed a committee. ...(Interruptions)...

DR. N. JANARDHANA REDDY: Sir, what will be the size of counterfeit currency that is in circulation in India?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is difficult to quantify the exact amount of fake currency in circulation. It is anybody's guess, as and when it is found out. Now, the currency notes in circulation right now is 48.9 billion pieces. One billion is equal to 100 crores. Therefore, one can understand the magnitude of it. Some estimation of the Reserve Bank -- it is estimation, not an assessment -- is that 0.001 per cent of this volume of currency may be fake currencies. But, there is no quantified and authentic information about the fake currencies in circulation. It is because if we know that, then, we will not allow that to be in the

currency. It will be immediately seized. But, this may be an estimation; it may be like that.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, with profound respect to the hon. Finance Minister, I would like to say that this is a sensitive question, but the highly innocuous nature of reply has a little surprised me. The hon. Minister will appreciate that regardless of 0.001 per cent of the component of fake currency, today fake currency is the order of the day in the country, particularly in the border areas with Nepal, in the North-East and with Pakistan. We have also seen a lot of terrorist organisations and their front-men abusing this whole system for all this. In this connection, you have said that the last upgradation was in the year 2005, and the next will take place in 2011-12. Then, what will be there in the interregnum? What competent and forthright steps have been taken in view of the alarming rise in the repeated occurrence of fake currency in all parts of the country? This is part (a). And, part (b), have you any information about the linkage of terrorists in promotion of this kind of insidious activity in the country?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am not an alarmist, and I cannot afford to be an alarmist. No Finance Minister can afford to be an alarmist. Therefore, the situation is not that alarming. Yes, more and more cases are being detected. The detection of more and more cases speaks of the vigilance and enhancement of the improvement of the security arrangements also. There is no denying of the fact that there are two types of activities related to the fake currency. One is those who do it individually or group of individuals for making profit. They indulge in

counterfeiting of currency. And that has its own impact on the economy, which is bad itself. But, much more dangerous is, when attempts are being made to destabilise the economy of a country by injecting massive doses of fake currencies. It is done with the objective of destabilising the economy of a country. That type of inimical activities are much more dangerous and serious. Keeping both aspects in view, we are making time to time revisions. The hon. Member has expressed his displeasure as to why there is such a long gap in it.

(Contd. by 1j-kgg)

kgg/1j/11.40

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): Please remember, in a country of 120 crore people, you will find 10-15 crores of people who are still not monetised in this country. Still, the barter system prevails over there. Therefore, with regard to frequent changes of the currencies, I would like to say that it is not a small country; here, there should be some sort of stability of the currencies. If I were to agree with your prophecy that it is a huge number, that it is destabilising our economy, I would have responded to you differently. But, I do not agree with it. Yes, it is a matter of concern, but for that we need not press the panic button.

DR. JANARDHAN WAGHMARE: Sir, there are rackets across the country, and even in the neighbouring countries like Nepal and China. These rackets are involved in printing fake Indian currencies, jeopardising our economy. Has the Government tried to trace these rackets? Has the Government taken any action against them?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, Sir, this is a factor and we are aware of it; we are taking action. Some of them have been arrested and due legal action has been taken against them. This is a constant exercise.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, in Hyderabad, there is a lot of currency being circulated from Pakistan. Everyday, the news of it is appearing. I would like to know whether the Minister knows this situation in Hyderabad and through what measures the Government would like to stop the circulation of currencies.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: All steps to prevent the circulation of fake currencies are being taken in every part of the country. As and when these are brought to our notice, we take appropriate action. (Ends)

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM OMAN

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from Oman, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency, Dr. Yahya Bin Mahfoodh Bin Salim Al Mantre, Chairman of the State Council in the Sultanate of Oman.

On behalf of the Member of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country.

We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Oman. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Oman. (Ends)

श्री रवि शंकर प्रसाद : सभापति महोदय, राज्य मंत्री बहुत सक्षम हैं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि पेट्रोलियम के संबंध में कभी-कभार केन्द्रीय मंत्री जी भी जवाब दिया करें। ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let us go ahead with the supplementary question.

SHRI RAJKUMAR DHOOT: Sir, has India entered into any contracts with foreign countries for assured and firm supplies of petroleum products during possible or future war so that operations of defence forces are not hampered during the war? If not, the reasons therefor.

SHRI JITIN PRASADA: Mr. Chairman, Sir, as far as entering into contracts with specific countries in situations like war, there is no such provision as of now. But, there are enough reserves within the country for certain contingencies which could be war, natural calamities, sudden escalation in prices of crude oil, etc. In those circumstances, there are enough reserves and the Government has taken a decision to build strategic reserves and we have a Special Purpose Vehicle, by the name Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, which is involved in building storage capacities specifically in Vishakhapatnam, Mangalore and Padur.

(Contd. by kls/1k)

KLS/1K-11.45

SHRI JITIN PRASADA (CONTD): About five million metric tonnes of strategic crude oil will be met through this.

SHRI RAJKUMAR DHOOT: Sir, my second supplementary is that there were some fire incidents in Jaipur and other cities destroying huge stocks of petroleum products. I would like to know the quantity and value of products lost in these incidents and the extent of damage

caused to the installations. What steps have been taken to make up the loss and also to prevent the recurrence of such incidents?

SHRI MURLI DEORA: Sir, the hon. Member is right.

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मुरली देवरा : आप जब सवाल पूछेंगे तो जवाब बता देंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मंत्री जी, हम आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब थे।

SHRI MURLI DEORA: Sir, recently in Jaipur, there was an incident fire in which Indian Oil Corporation's tanks were burnt. It was very difficult task for the people. We had...(Interruptions)... You made me really nervous, I accept this. ...(Interruptions)... Nearly 150 crore of rupees worth of material was burnt and about 70 to 80 crore of rupees will be spent to reconstruct that thing. The steps are being taken to see how best we can prevent such incidents of fire. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Four of your employees died. ...(Interruptions)... **:** मंत्री जी, यह भी तो बोलिए

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, the hon. Minister in his reply has stated that the Government is not creating a buffer stock of petroleum products, but the public sector oil marketing companies are creating the buffer stocks of the petroleum products. At the same, it is mentioned in the reply that the Government is, however, setting up a strategic crude oil reserve of 5 million metric tonnes in three places, namely, Visakhapatnam, Mangalore and Padur. I would like to know in Visakhapatnam under what name they are creating this capacity. You have also said that it will be increased from 1 MMT to 1.3 MMT and it will be completed by 2012 positively. I would like to know what is the

total capacity the Government is going to create and whether it is being done by the IOC or HPCL or whether the Government is directly doing it. What is the cost that will be incurred on increasing this from 1 MMT to 1.3 MMT?

SHRI MURLI DEORA: Sir, the name of the company is Indian Strategic Petroleum Reserve Limited. It is owned by all the three oil companies, namely, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum and one more.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I would like to know from the hon. Minister about this buffer stock of crude oil. The idea itself of storage is very good keeping in view the future requirements. But I would like to know from him whether we have any special arrangements of storage of these articles and whether it is possible to have the proper arrangements and whether we have so far done it. If so, to what extent can we have this storage?

SHRI JITIN PRASAD: Sir, as far as storage is concerned, these are underground *carbons*, which are specifically meant for storing of crude oil in case of emergency, as I just mentioned earlier. But on the other hand, there are two aspects to it, one is the crude oil storage and the other is the products such as petroleum, diesel, kerosene, etc. which also need to be stored in case of emergencies and those are stored in oil depots, refineries, bottling plants, etc. So, there are two kinds of storages. This one is especially a strategic reserve, which is specifically made for those calamities such as natural calamities, war, or escalation in prices. At the moment, I must inform the House that the international norm is 90 days of import of crude oil storage capacity. This is the

storage capacity which one country should have. In India at the moment, without these reserves in place and without these carbons in place, we still have 74 days worth of import of crude oil as storage capacity for meeting the requirements of this country.

(Contd by 1L/SSS)

NB/SSS/1L/11.50

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 5 मिलियन मीट्रिक टन का रिज़र्व बनाने की सूचना इस सदन को दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का assessment किया है कि देश में सेना, सुरक्षा बलों, उद्योगों, परिवहन और निजी जनता के उपयोग में प्रति माह कितने पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, खपत होती है और आने वाले वर्षों में यह खपत कितनी और बढ़ेगी तथा इस आधार पर आपका जो 5 मिलियन मीट्रिक टन का strategic reserve है, आपत्ति काल की स्थिति में आपके पास कितने दिनों का रिज़र्व मौजूद होगा, कितने दिनों तक आप इस रिज़र्व से अपने देश का काम चला सकेंगे, क्या इस बात का कोई assessment किया गया है, यदि हां, तो कृपा करके बताने का कष्ट करें।

श्री जितिन प्रसाद : सभापति जी, जहां तक consumption का सवाल है, भारत में 2009-2010 में 140 मिलियन मीट्रिक टन तेल का consumption हुआ और जहां तक इस strategic reserve का सवाल है, मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ द्वारा जो मानक रखा गया है, उसमें यही कहा गया है कि आपके पास 90 दिनों के स्टोरेज का प्रावधान होना चाहिए। भारत के पास आज की तारीख में 74 दिनों के स्टोरेज की कैपेसिटी है और जो रिज़र्व बनेंगे - 3.3 मिलियन मीट्रिक टन स्टोरेज की कैपेसिटी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज़ के पास है तथा भारत सरकार, ISPRL के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन के रिज़र्व बना रही है, इन दोनों को मिलाकर 8.3 मिलियन मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास हो जाएगी, जो 2011-2012 में 74 दिनों के रिज़र्व के बराबर हो जाएगा। अब 90 दिनों के लक्ष्य तक पहुंचने का जो गैप बाकी है, उसकी तरफ

बढ़ा जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो 90 दिनों का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, चाहे वह डिफेंस का हो, चाहे public consumption का हो, सभी के लिए यही मानक है और उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए।

MR. CHAIRMAN: One question only please. Please do not interrupt.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति जी, मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस बात का कोई assessment आपने करवाया है, इसके पहले कोई जांच या पड़ताल आपने करवाई है और उसके क्या परिणाम आए है और उस आधार पर आप कितने दिनों तक चला सकेंगे? इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि कोई जांच-पड़ताल हुई है या नहीं, हुई है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री जितिन प्रसाद : सभापति जी, जहां तक जांच-पड़ताल का सवाल है, इसके लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि आपको 90 दिनों का रिज़र्व रखना है, वरना त्रासदी तो कभी भी हो सकती है और 90 दिन क्या, आपके पास 9 दिन का भी रिज़र्व नहीं होगा, मगर इंटरनेशनल नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए हम 90 दिनों के रिज़र्व का इंतज़ाम कर रहे हैं, वरना कभी भी कोई भी त्रासदी आ सकती है और जब तक आप उसे face न करें, तब तक उसका सर्वे नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(समाप्त)

MR. BHARATKUMAR RAUT: Hon. Chairman, Sir, I am really surprised by the answer that has been given by the hon. Minister. On the one hand, the Government and the Chairman of NACIL keep saying that one reason for NACIL going in red is because it is over-employed. On the other hand, you are transferring the services of something else to this Airline. Fine, you are into good labour practice. Once you have transferred their services to Indian Airlines from Alliance Airlines, then, is it not the duty of NACIL and the Government to ensure that their allowances and the service conditions remain the same on par with the Indian Airlines? They were the same way. They try the same way but their allowances are different. How does the Government explain this?

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I am very happy that the hon. Member is also representing a large section of the employees' interest in Air India and he comes from my State. So I know the kind of interest he has been taking. All I would like to state here is, Sir, that in the case of Alliance Air staff, Alliance Air has gradually been coming down in terms of fleet strength because, as we all know, we have a reduced role of Alliance Air and a larger role for Air India, both domestic and international.

(Contd. by NBR/1M)

-SSS/NBR-VNK/1M/11.55.

SHRI PRAFUL PATEL (CONTD.): This staffs were, of course, employed by the erstwhile Alliance Air and they would have, otherwise, been terminated, because they were on the Fixed Term Employment Agreement. It all depends on the number of hours one flies. It is based

on that, one will get emoluments and one will have a fixed term. There were two options. One is either to terminate their services, or, in the larger interest, redeploy them. As you have rightly said, some representations did come from employees saying why they should lose their job since they have worked for a considerable number of days. That is why, in the larger interest, I think, we should all appreciate, we have given them the similar arrangement to continue while they work with Air India. So, I think, there is no reason to ask them to appear for interview, because the terms and conditions for employment in NACIL mandates them to go through fresh interview and other process and there is also a possibility that since many people are over-aged or due to other reasons they may not be able to get employment again. So, I think, it is a fair arrangement keeping the employees interest in mind.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, many-a-time, half truth is worse than the complete untruth. Anyway, I leave it to the hon. Minister.

Now, the question is, Alliance Air, Indian Airlines, Air India, Air India Express and so many other companies came under one umbrella -- NACIL. When this company was formed and before merger of all these companies into NACIL, an assurance was given that the service conditions, allowance, salary structure, etc., will be uniform. Now, three years have passed, I ask the hon. Minister as to when is he going to bring in common code of service conditions and allowance in the NACIL in which Alliance Air is also a part.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, let me clarify that there is no half truth or anything of that sort. Whatever I have stated is the factual position. I

don't agree with the hon. Member. What I have said is the absolute truth. There is nothing like half truth.

After the merger, one of the long-term objectives is to unify and bring all employees under one service conditions. The idea is, under NACIL, everybody should have a similar treatment. This is an on-going process. Yes; certain things may have been achieved. Time-frames may not have been met. But, at the same time, the objective and the commitment of the Government is to see that the interests of all the employees are not only protected but they all come under a uniform service code.

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, हमने देखा कि सबसे पहले 'वायुदूत' बनी और उसमें खूब बहालियां हुईं। उसके बाद 'वायुदूत' को 'इंडियन एयरलाइंस' में मर्ज किया गया। मर्जर के पहले 'एलाइंस एयर' को 'इंडियन एयरलाइंस' में मर्ज किया गया। फिर 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' बना और उसमें भी खूब बहालियां हुईं। इसके बाद 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' को 'एयर इंडिया' में मर्ज किया गया। जब सब बहालियां हो गईं तो 'एयर इंडिया' और 'इंडियन एयरलाइंस' को मर्ज करके 'एयर इंडिया' बना दिया गया। यह परंपरा रही है। इस प्रकार से आज 30 हजार कर्मचारी हैं और भगवान जाने कैसे सरकार और मंत्री पूरी व्यवस्था को कायम रखेंगे। मेरा एक ही प्रश्न है, वह यह है कि आज 'एयर इंडिया' लगभग पांच से छः हजार करोड़ रुपए के घाटे में है। आज लगभग तीस हजार कर्मचारी हैं। दुनिया-भर में अगर किसी विमानन सेवा को सफल बनाना है, तो औसतन कर्मचारी और जहाज का रेशियो सवा सौ पर एक जहाज होता है। आज भारत में 'एयर इंडिया' के सामने 250 कर्मचारी एक जहाज के सामने है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार क्या सोचती है और किस प्रकार से इस पूरे 'एयर इंडिया' को पुनर्जीवित करेगी, जिसका घाटा आज लगभग सात हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है?

श्री प्रफुल्ल पटेल : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सांसद महोदय मेरे predecessor थे और उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। मैं उनको सिर्फ यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो बहुत सारी बातें की, उनमें हमने थोड़ा सुधार करने का ही काम किया है, क्योंकि 2003-04 में, आपके कार्यकाल में, आप जब मंत्री थे, इस कंपनी को disinvestment के लिए निकाला गया था और उस समय disinvestment के प्रोसेस में निविदा में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जब वे स्वयं छोड़कर चले गए, अरुण शौरी जी भी बैठे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा मुस्कुराते हुए यह कहने में हर्ज नहीं है कि यह काम तभी तमाम हो गया होता, लेकिन तमाम नहीं हुआ और हमारे जिम्मे आया ..(व्यवधान)..

श्री राजीव प्रताप रूडी : श्री अरुण शौरी साहब कह रहे हैं कि आपके दोस्तों के कारण नहीं आया ..(व्यवधान)..

श्री प्रफुल्ल पटेल : वह कोई बात नहीं, आप सहित हमारे सभी मित्र हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि हमने पूरी कोशिश की है कि इस कंपनी को पब्लिक सेक्टर में रखते हुए इसको ठीक से चलाया जाए। Aviation Sector के हालात कुछ विशेष हैं। यह केवल Air India के लिए ही नहीं, निजी कंपनियां भी जो कल तक अच्छी तरह से मुनाफे में चल रही थीं, आज उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए सरकार की निरंतर कोशिश है कि इस सेवा को और कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए हम उपयुक्त उपाय करें।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

(Ends)

-NBR/PK-MP/1N/12.00

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

SHRI G.K. VASAN: Sir, I lay on the Table;

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:

(i) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2008-09, together with the Auditors Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(ii) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(iii) (a) Annual Accounts of the Mumbai Port Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(iv) (a) Annual Administration Report of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Navi Mumbai, for the year 2008-09.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(v) (a) Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Navi Mumbai, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(vi) (a) Annual Administration Report of the Paradip Port Trust, Paradip, Orissa, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(vii) (a) Annual Accounts of the New Mangalore Port Trust (NMPT),

for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(viii) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(ix) (a) Annual Accounts of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(x) (a) Annual Accounts of the Paradip Port Trust (PPT), for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(xi) (a) Annual Administration Report and Accounts of the New Mangalore Port Trust, Mangalore, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xii) (a) Annual Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(xiii) (a) Thirtieth Administration Report and Accounts of the Tuticorin Port Trust, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xiv) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xv) (a) Annual Administrative Report and Accounts of the Cochin Port Trust, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xvi) (a) Annual Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(xvii) (a) Annual Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

(xviii) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2008-09.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xix) (a) Annual Administration Report of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2008-09.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(xx) (a) Annual Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the Annual Accounts and Audit Report.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:ഋ

(a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Dredging Corporation of India Limited (DCI), Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the

comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:ळ

(a) Forty-third Annual Report of the Seamenङs Provident Fund Organisation (SPFO), Mumbai, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Seamenङs Provident Fund Organisation, (SPFO), Mumbai, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Organisation.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:

(1) G.S.R. 836 (E), dated the 23rd November, 2009, publishing the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2009.

(2) G.S.R. 837 (E), dated the 23rd November, 2009, publishing the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2009.

(3) G.S.R. 838 (E), dated the 23rd November, 2009 publishing the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(4) G.S.R. 813 (E), dated the 12th November, 2009, publishing the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Second Amendment) Regulations, 2009.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification F. No. 125, dated the 17th July, 2009, publishing the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 2009, under Section 28 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the SEBI Act, 1992:

(1) No.LAD-NRO/GN/2009-10/20/182131, dated the 6th November, 2009, publishing the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2009.

(2) No.LAD-NRO/GN/2009-10/21/183853, dated the 19th November, 2009, publishing the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009.

IV. A copy (in English and Hindi) of the Annual Report and Accounts of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts, under sub-section (2) of Section 32 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

V. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:ऴ

(a) Fourth Annual Report and Accounts of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

VI. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:ऴ

(i) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Pratichi (India) Trust, Delhi for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Trust.

(c) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) (a) Ninth Annual Report and Accounts of the Pratichi (India) Trust, Delhi for the year 2007-08, together with the Auditor's Report

on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Trust.

(c) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Consolidated Report on the Working of the Public Sector Banks (PSBs) for the year ended on the 31st March, 2009.

(iv) A copy each (in English and Hindi) of the Annual Reports and Accounts of the following Regional Rural Banks for the year 2008-09, together with the Auditorङs Report on the Accounts :ळ

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal;
2. Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa;
3. Arunachal Pradesh Rural Bank, Papum-Pare;
4. Aryavart Gramin Bank, Lucknow;
5. Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia, Uttar Pradesh;
6. Baroda Gujarat Gramin Bank, Bharuch;
7. Baroda Rajasthan Gramin Bank, Ajmer;
8. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli;
9. Bihar Kshetriya Gramin Bank, Munger;
10. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank, Mysore;
11. Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur;
12. Chhattisgarh Gramin Bank, Raipur;
13. Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar;
14. Durg Rajnandgaon Gramin Bank, Rajnandgaon, Chhattisgarh;
15. Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon;
16. Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota;
17. Haryana Gramin Bank, Rohtak;
18. Himachal Gramin Bank, Mandi;
19. Jaipur Thar Gramin Bank, Jaipur;

20. Jammu Rural Bank, Narwal, Jammu;
21. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank, Jhabua, Madhya Pradesh;
22. Jharkhand Gramin Bank, Ranchi;
23. Kalinga Gramya Bank, Cuttack;
24. Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad;
25. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi, Uttar Pradesh;
26. Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri, Uttar Pradesh;
27. Madhya Bihar Gramin Bank, Patna;
28. Madhya Bharat Gramin Bank, Sagar;
29. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank, Jabalpur, Madhya Pradesh;
30. Marathwada Gramin Bank, Nanded;
31. Mewar Aanchalik Gramin Bank, Udaipur;
32. Mizoram Rural Bank, Zarkawt, Aizawl, Mizoram;
33. Nagaland Rural Bank, Kohima, Nagaland;
34. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Haldwani, Nainital;
35. Narmada Malwa Gramin Bank, Indore;
36. Neelachal Gramya Bank, Bhubaneswar;
37. North Malabar Gramin Bank, Kannur, Kerala;
38. Parvatiya Gramin Bank, Chamba;
39. Prathama Bank, Moradabad, Uttar Pradesh;
40. Punjab Gramin Bank, Kapurthala;
41. Purvanchal Gramin Bank, Gorakhpur;
42. Rajasthan Gramin Bank, Alwar;
43. Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh;

44. Sarva U.P. Gramin Bank, Meerut;
45. Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara;
46. Sharda Gramin Bank, Satna;
47. Shreyas Gramin Bank, Aligarh;
48. Sutlej Gramin Bank, Bathinda;
49. Uttaranchal Gramin Bank, Dehradun;
50. Vananchal Gramin Bank, Dumka;
51. Visveshvaraya Grameena Bank, Mandya, Karnataka;
52. Wainganga Krishna Gramin Bank, Solapur;
53. Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank, Chikmagalur;
54. Rewa Sidhi Gramin Bank, Rewa;
55. Baitarani Gramya Bank, Mayurbhanj, Orissa;
56. Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur;
57. Tripura Gramin Bank, Agartala;
58. Meghalaya Rural Bank, Shillong;
59. MGB Gramin Bank, Pali, Marwar, Rajasthan;
60. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank, Vidisha;
61. Maharashtra Godavari, Gramin Bank, Aurangabad;
62. Paschim Banga Gramin Bank, Howrah;
63. Ellaquai Dehati Bank, Srinagar;
64. Saptagiri Grameena Bank, Chittoor;
65. Etawah Kshetriya Gramin Bank, Etawah;
66. Malwa Gramin Bank, Sangrur;
67. Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola;
68. Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati;
69. Utkal Gramya Bank, Bolangir;
70. Manipur Rural Bank, Keisampat, Imphal;
71. Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu, Karbi Anglong,

Assam;

72. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur;
73. Saurashtra Gramin Bank, Rajkot;
74. Rushikulya Gramya Bank, Berhampur;
75. Krishna Grameena Bank, Gulbarga;
76. Triveni Kshetriya Gramin Bank, Orai, Jalaun;
77. Lucknow Kshetriya Gramin Bank, Sitapur;
78. Deccan Grameena Bank, Hyderabad;
79. Pandyan Grama Bank, Virudhunagar, Tamil Nadu;
80. Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry;
81. Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad, West Bengal;
82. Pragathi Gramin Bank, Bellary, Karnataka;
83. South Malabar Gramin Bank, Malappuram, Kerala;
84. Pallavan Grama Bank, Salem;
85. Kamraz Rural Bank, Sopore, Jammu and Kashmir; and
86. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar, West Bengal.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944 together with Explanatory Memoranda on the Notifications:

(1) G.S.R. 576 (E), dated the 17th August, 2009, amending Notification No. G.S.R. 182 (E), dated the 8th March, 2002, to substitute certain entries in the original Notification.

(2) G.S.R. 704 (E), dated the 25th September, 2009, amending Notification No. G.S.R. 474 (E), dated the 26th June, 2001, to substitute certain entries in the original Notification.

(3) G.S.R. 830 (E), dated the 18th November, 2009, exempting handmade biris, matches manufactured in non-mechanised sector and reinforced cement concete pipes assesses from

filing the Annual Installed Capacity Statement.

(4) G.S.R. 772 (E), dated the 21st October, 2009, granting exemption to certain packing materials, plastic bags and printed laminate rolls, etc manufactured by a Small Scale Industry unit, with brand or trade name.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, together with Explanatory Memoranda on the Notifications:-

(1) S.O. 1570 (E), dated the 26th June, 2009, regarding exchange rate of conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(2) S.O. 1603 (E), dated the 30th June, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(3) S.O. 1679 (E), dated the 9th July, 2009, amending the Rules of Determination of Origin of Goods under the Asia-Pacific Trade Agreement (formerly known as the Bangkok Agreement) Rules, 2006.

(4) S.O. 1748 (E), dated the 15th July, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(5) S.O. 1808 (E), dated the 22nd July, 2009, regarding exchange rate of conversion of Swedish Kroner into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(6) S.O. 1857 (E), dated the 29th July, 2009, regarding exchange rate of conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(7) S.O. 1870 (E), dated the 31st July, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(8) S.O. 2123 (E), dated the 13th August, 2009, regarding revision

of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(9) S.O. 2193 (E), dated the 27th August, 2009, regarding exchange rate of conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(10) S.O. 2209 (E), dated the 31st August, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(11) S.O. 2382 (E), dated the 15th September, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(12) S.O. 2460 (E), dated the 25th September, 2009, regarding exchange rate of conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(13) S.O. 2492 (E), dated the 30th September, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(14) S.O. 2622 (E), dated the 15th October, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

(15) S.O. 2667 (E), dated the 22nd October, 2009, regarding exchange rate of conversion of Swedish Kroner into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(16) S.O. 2713 (E), dated the 28th October, 2009, regarding exchange rate of conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(17) S.O. 2734 (E), dated the 30th October, 2009, regarding revision of Tariff Value on Crude Palm Oil, RBD Palm Oil and certain other items based on international prices.

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 816 (E), dated the 12th November, 2009, publishing the Prevention of Money-Laundering

(Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2009, under Section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, together with Explanatory Memorandum on the Notification.

IV. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. S.O. 2958 (E), dated the 20th November, 2009, publishing the Income-tax (Dispute Resolution Panel) Rules, 2009, under Section 296 of the Income-tax Act, 1961, together with Explanatory Memorandum on the Notification.

V. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R.581 (E), dated the 19th August, 2009, publishing the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control or Drug Abuse) Amendment Rules, 2009, under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, together with Explanatory Memorandum on the Notification.

SHRI JITIN PRASADA: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:

(1) G.S.R. 561 (E), dated the 3rd August, 2009, publishing the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2009.

(2) G.S.R. 835 (E), dated the 23rd November, 2009, publishing the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2009.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas Notification No. G.S.R. 149, dated the 18th to 24th October, 2009, publishing the First Statutes of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, under sub-section (2) of Section 40 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007.

III. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Petroleum and

Natural Gas Notification No. G.S.R. 808 (E), dated the 11th November, 2009, publishing the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:ऊ

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Oil Corporation Limited (IOC), Mumbai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(ii) (a) Sixteenth Annual Report and Accounts of the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, I lay on the Table, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare:

(1) G.S.R. 677 (E), dated the 15th September, 2009, restricting the manufacture, sale or distribution of the drug Oseltamivir Phosphate and Zanamivir and preparations based thereon indicated for H1N1 viral influenza (swine flu) in human and for preventing their misuse in public interest.

(2) S.O. 2076 (E), dated the 10th August, 2009, appointing the 10th August, 2009, as the date on which the provisions contained in the Sections of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, 2008, shall come into force.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(ii) (a) Eighteenth Annual Report and Accounts of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Vidyapeeth.

(iii) (a) Annual Report of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Council.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Naturopathy (NIN), Pune, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditorड Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

SHRI ARUN YADAV: Sir, I lay on the Table

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:

(i) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Engineering Projects (India) Limited (EPI), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditors Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(ii) (a) Twenty-eighth Annual Report and Accounts of the National Bicycle Corporation of India Limited (NBCIL), Mumbai, for the year 2008-09, together with the Auditorङs Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) (a) Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Richardson and Cruddas (1972) Limited (R&C), Mumbai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iv) (a) Forty-fifth Annual Report and Accounts of the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(v) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Hindustan Paper Corporation Limited, Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(vi) (a) Forty-fifth Annual Report and Accounts of the Cement Corporation of India Limited (CCI), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:ङ

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRiP), New Delhi,

for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(ii) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Automotive Research Association of India (ARAI), Pune, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Fluid Control Research Institute (FCRI), Palakkad, Kerala, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(Ends)

REPORTS OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA (RAJASTHAN): Sir, I present a copy each of the following reports (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation:

(i) One Hundred and Eighty-fifth Report on the Statutory Orders laid on the Table of the Rajya Sabha during its 217th Session.

(ii) One Hundred and Eighty-sixth Report on the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000.

REPORTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

DR. C.P. THAKUR (BIHAR): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:

(i) Fourth report on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals); and

(ii) Fifth report on the subject Production and Availability of Medicines to deal with Swine Flu of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

REPORT OF THE COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR (ASSAM): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the First Report of the Committee on Empowerment of Women on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twentieth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on the subject "Credit Facilities for Women by Public Sector Banks and NABARD."

STATEMENTS OF THE COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR (ASSAM): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements of the Committee on Empowerment of Women:

(i) Final Action Taken Statement of the Government on the recommendations contained in Chapter -1 of the Seventeenth Report (Fourteenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women on the subject Plight of Indian Women Deserted by NRI Husbands; and

(ii) Final Action Taken Statement of the Government on the recommendations contained in Chapter -1 of the Eighteenth Report (Fourteenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women on the subject "Insurance Schemes of LIC for Women."

STATEMENTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

DR. KARAN SINGH (NCT OF DELHI): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs:

(i) Statement showing action taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the Twenty-second Action Taken Report on the recommendations contained in the Twentieth Report (Fourteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2008-09) of the Ministry of External Affairs; and

(ii) Statement showing action taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the Twenty-third Action Taken Report on the recommendations contained in the Twenty-first Report (Fourteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2008-09) of the Ministry of Overseas Indian Affairs.

(Followed by 1O/PB)

-PK/PB/10/12.05

MOTIONS REGARDING TWELFTH REPORT OF COMMITTEE ON RULES

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I beg to move the following motions:

"That the Twelfth Report of the Committee on Rules presented to the Rajya Sabha on the 14th December, 2009 be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That this House agrees with the recommendations contained in the Twelfth Report of the Committee on Rules, presented to the Rajya Sabha on the 14th December, 2009."

The questions were put and the motions were adopted.

(Ends)

MESSAGES FROM LOK SABHA

(i) The Competition (Amendment) Bill, 2009

(ii) The State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Competition (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2009.

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2009.

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Zero Hour Mentions. Shri M. Venkaiah Naidu. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I want to know why was my Zero Hour Mention not allowed? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can't question that here. ...(Interruptions)... I cannot answer here. ...(Interruptions)... It is the decision of the Chairman. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, is it only because he is *Dalit*? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIMAN: No, no; Mr. Rashtrapal, please don't do that. ...(Interruptions)... Please, no; no; it is not correct. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I must be allowed to ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; please, give it to the Chairman. Once a notice ... ...(Interruptions)... No; no; please; nothing will go on record. Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rashtrapral, please sit down. ...(Interruptions)...Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot ask the Chair the reasons for it. ...(Interruptions)... You should go through the rules. ...(Interruptions)... You should go through the rules. ...(Interruptions)...Mr. Venkaiah Naidu. ...(Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, what is this? ...(Interruptions)...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, in the morning meeting, it was resolved that Shrimati Brinda Karat will ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is coming. There are other Zero Hour Mentions also. ...(Interruptions)... It is coming. Her name is here. ...(Interruptions)... The numbering, first, second, etc., is not important.

*** Not recorded**.

Everybody will get a chance. Yes, Mr. Venkaiah Naidu.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR.

VOILENT SITUATION ARISING AFTER THE DECLARATION OF FORMATION OF SEPARATE STATE OF TELANGANA OUT OF ANDHRA PRADESH.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (KARNATAKA): Sir, I rise to express my anguish on what is happening in the State of Andhra Pradesh. Sir, the Government of India has complicated the entire issue. Now, the State is practically in turmoil; students are on strike; colleges are closed. ...(Interruptions)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: How can you say that the Naxal Movement has ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumantha Rao, see, the Member is speaking; don't disturb the Member. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... Please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU. Sir, more than 130 MLAs seem to have resigned. The Andhra Pradesh Assembly is not able to transact any business. It was adjourned *sine die*. The students are in the streets; suicides are also again taking place in that side. ...(Interruptions)... Earlier, there were suicides. ...(Interruptions)... Sir, the Government seems to be playing with the sensitivities of the people. Sir, it is a fact that the people of Telangana wanted to have a separate State in the year 1969. (Contd. by 1p/SKC)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Contd.): And the people of Andhra Pradesh also wanted a separate State in the year 1972. (Interruptions)

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Under your leadership.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. Hanumantha Rao. (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, at that time I was 23-24 years old and I feel proud when someone says that I was leading the entire agitation. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumantha Rao, how many times should I tell you? (Interruptions) Please, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Government of India has behaved in a most irresponsible and immature manner. This is not expected of a Government that is ruling at the Centre in dealing with such a sensitive situation. You did not take your MLAs into confidence; you did not take your MPs into confidence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over, Mr. Naidu. Please conclude.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Please, give me some more time, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a question of time! It is the Zero Hour. (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is the question of the issue being discussed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude. It is a question of time as well.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is a question of the issue. Leaders of the Ruling Party are making provocative statements. The leaders of the

Ruling Party are going on fast; it is not the Opposition. I do not wish to name the persons because they belong to the other House. They are on fast and then, they are making provocative statements, and...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naidu, if you disturb them, then they would again...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, provocative statements are coming from this side also. I am not ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. (Interruptions) आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, और लोग टाइम पूछते हैं, आप खामोश बैठिए..(व्यवधान)..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Assembly is not able to function; the House is adjourned *sine die*. The students are on strike. The Ruling Party itself is divided, and the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has gone on record saying that even he was not taken into confidence. You don't take the Chief Minister into confidence; you do not take the MLAs into confidence; you do not take the MPs into confidence...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Venkaiah Naidu, please conclude. (Interruptions)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: What is he saying? (Interruptions) He cannot say that. (Interruptions)

SHRI V. HANUMANTHA RAO: We do not have to listen...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: What is this? Do you have the sole right to speak everywhere? (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. (Interruptions) Please sit down. (Interruptions)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: TDP is divided. How does he say...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Subbarami Reddy, please sit down. आप बैठिए...(व्यवधान).. Please sit down. Allow him to speak. (Interruptions) Please conclude, Mr. Venkaiah Naidu.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the BJP is committed for the creation of a separate State; there is no going back on that. Let me make it very clear; we are very clear about it. But, at the same time...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Brinda Karat.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is a very important issue concerning my State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have raised it in the Zero Hour. You have to follow the Zero Hour's rules.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, others must also follow the rules.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I gave you extra time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Is that a concession?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; it is my request.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the entire State is on the boil and the House is not able to discuss the issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have mentioned it. You have given the notice in Zero Hour.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you may bring it to the notice of the Government. I will be happy to have a structured debate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to follow the rules of the Zero Hour.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Agreed, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then why did you give the notice for Zero Hour? You should have given it for some other time. You have given it for Zero Hour and we are allowing it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Minister has made a statement outside the House. As if he is following the rules! And you don't want the House to discuss this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That issue is not before the House.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Why, Sir? Why is it not before the House? In my notice itself it is said...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Your notice may be saying it. But I cannot compel the Minister or the Government to reply to a Zero Hour mention. You had sought permission to raise the matter during Zero Hour. I have allowed it. The time is over. Now, how could I disallow others from raising important issues that they want to? I cannot ask them to take their own time. Then we will be breaking the rules.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am not saying that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sir, I am not saying that the matter that you have raised is not important, but your matter is not the only important matter.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is one of the most important matters. It is a sensitive matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree. That is correct.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we have created three States; but there was no problem at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have said whatever you wanted to say. Please conclude.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the State is on the boil and if I have to keep quiet...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Brinda Karat.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is not fair, Sir. That is why I want the Government to come out with a road map and take the House into confidence. They must come out with a road map to see that the situation is taken care of and crisis averted and the State comes back to normalcy. I would like to know from the..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; if they are not reacting, I cannot say anything.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you must advise the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to follow the rules set by the House.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we must follow the rules. But we must understand the people's aspirations also. This is the Council of States.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. That is why we have allowed you to raise this issue.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, that is why, I demand from the Government, if not today -- Sir, the Minister is here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have the Minister; otherwise, the House would not run!

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, today, and if not today, tomorrow, let them take the House into confidence. Stop the State...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is listening to whatever you are saying. It is for them to react. (Interruptions) Please conclude.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Then come to a conclusion. Bring back normalcy to the State. That is my request.

(Ends)

(Followed by gsp/1q)

-SKC-GSP-AKG-12.15-1Q

RE. REVELATIONS ABOUT THE TERRORIST DAVID HEDLEY'S ANTECEDENTS AND STATUS OF FBI'S COOPERATION WITH THE INDIAN INTELLIGENCE AGENCIES.

SHRIMATI BRINDA KARAT (WEST BENGAL): Sir, in a series of shocking reports emanating in the US, it is revealed that David Headley, who has been charged with conspiracy in the Mumbai terrorist attacks, was an undercover agent working for the US Drug Enforcement Administration, the DEA since 1999. Reports state that David Headley, whose real name was Daood Saleem Gilani was arrested in February, 1997 in New York for conspiring to import heroin into the US. However, since he started cooperating with the DEA, he was released and allowed to travel to Pakistan to conduct undercover surveillance operations on drug gangs in Afghanistan and Pakistan. A drug smuggler was turned into a US agent.

Reports have elaborated how Gilani started making frequent trips between Pakistan and the US since 1999. Even the change of his name from Daood Gilani to David Headley was obviously done to make his travelling easier and was known to the US agencies who were protecting him.

As has been the case with several such American double agents in the past, most famously, Osama Bin Laden, who had started his career as a CIA operative, David Headley too, reportedly, started working for the *Lashkar*. Investigations have revealed that David Headley had made multiple visits to India in 2008. It was on these trips, Sir, that the drug smuggler-turned-US agent-turned *Lashkar* terrorist surveyed sites in our cities, sites in Mumbai, and, reportedly, the information he gathered was considered crucial in the Mumbai 26/11 attacks.

Shockingly enough, he even visited India in April, 2009, after the Mumbai terror attacks. The FBI was evidently aware of David Headley's antecedents and had put him under surveillance well before the Mumbai terror attacks which took place in November, 2008. But why were the Indian intelligence agencies unaware of David Headley's visits to India. Sir, it is our cities, our people, our nation, which was targeted. We want to know: Did the FBI pass on the real time intelligence to the Indian intelligence agencies? That is the crucial question here. Were we informed; is this the type of US cooperation which is being extended to us.

Secondly, why are the Indian investigators being denied access to David Headley, when the FBI was allowed to question Ajmal Kasab who is in Indian custody? Is it because it will expose the under-belly of the US covert operations, which has a record of creating Frankenstein, like Osama Bin Laden. Did our Prime Minister raise the issue when he met the US President in Washington? What steps are being taken by the

Indian Government to ensure that the Indian investigators question David Headley at the earliest?

Sir, these are very crucial issues which have an impact on our national security and we demand that the Government of India clarify these issues. Thank you. (Ends)

SHRI AMAR SINGH (UTTAR PRADESH): Sir, I associate myself with the matter raised by Shrimati Brinda Karat.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the issue raised by Shrimati Brinda Karat.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MATILAL SARKAR (TRIPURA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I also associate myself with this important issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. All of you associate.

(Ends)

RE. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING's O.M. ON DERESERVATION OF VACANT POSTS BELONGING TO SCs, STs AND OBCs AS REPORTED IN THE NEWSPAPER.

SHRI JESUDASU SEELAM (ANDHRA PRADESH): Sir, I rise to express my anguish over the reported O.M. issued by the DoPT on deserving the posts meant for SCs, STs and OBCs after the so-called prolonged vacancy in exceptional cases, and, the idea that the two weeks' time will be given to the SC, ST Commission or the Ministry of Social Justice for responding. Sir, it is very manipulative. I am very sorry to say that we

have been asking the Government to bring forward the Reservation Act so that such manipulative tactics do not take place. Sir, it can be easily manipulated. You are thereby giving rise to such manipulations. I can understand, the SCs and STs not being available here and there, but, Sir, hundred per cent OBCs are available. We have experienced it, Sir. Even in the case of SCs and STs, what are the efforts made by the Government to train them, to search the candidates, or, to advertise the posts. We have reviewed this position. Sir, we are grateful towards the Government for saying that a series of attempts should be made to fill up the backlog but, Sir, it is a backdoor method to delay the legitimate opportunities. We are afraid that it would be highly misused. We would like the Government to immediately withdraw it, otherwise, there is going to be a widespread unrest amongst Dalits, SCs, STs and OBCs across the country. Secondly, Sir, (Interruptions) I have time.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he is very correct.

SHRI JESUDASU SEELAM: Secondly, Sir, Mr. Venkaiah Naidu brought out a very important thing. I don't want people to take...(Interruptions)...

(Followed by sk-1r)

-gsp/SK/1R/12.20

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, don't link it. ..(Interruptions)..

SHRI JESUDASU SEELAM: This is telling us how it can ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ..(Interruptions).. Your subject is ..(Interruptions).. Mr. Seelam, I will not allow. ..(Interruptions).. Nothing will go on record. ..(Interruptions)..

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this issue is a very important issue. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is different. ..(Interruptions)..

SHRI JESUDASU SEELAM: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Venkaiah Naidu has said, you have to raise nothing out of that. ..(Interruptions)..

SHRI JESUDASU SEELAM: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over now. ..(Interruptions).. You have to associate only. ..(Interruptions)..

SHRI B.S. GNANADESIKAN (TAMIL NADU): Sir, I associate. ..(Interruptions)..

MS. SUSHILA TIRIYA (ORISSA): Sir, I associate. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please .(Interruptions). Please ..(Interruptions).

SHRI D. RAJA: Sir, I have given a separate notice. I would like to make a ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. All the three Members have given notice on the same subject. That is why the practice is to associate only.

SHRI D. RAJA (WEST BENGAL): Sir, it is a very serious matter. The Government claims that it is working for inclusive growth. But what the Department is doing is just opposite. I am working on the Committee of Welfare of SCs and STs. I am coming across the reports routinely given by the Government. So insensitive, so irresponsible they are. They said there is no availability of suitable candidates. I do not agree with the

---

*** Not recorded**

Government's understanding. How can you say that there is no availability of suitable candidates? Number two, in the name of public interest, you cannot take decisions which are going against the interests of SCs/STs and OBCs. (Time-bell) Let me finish, Sir. Number three, the Government says that there is ban on recruitment but this ban does not apply to the backlog. Why the Government Department should give such an answer that there is ban on recruitment? All these questions will have to be looked into, and the Government should immediately withdraw this Office Memorandum which deprives the benefits of reservation which have been given to SCs/STs and OBCs. If this Government acts like that, it will have to face the wrath of the people in the coming days.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, I ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You associate. ..(Interruptions).. No, no. I cannot allow it to be discussed here. ..(Interruptions)..

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, I am told that there are nearly 28,671 posts ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just associate Mr. Hanumantha Rao. ..(Interruptions).. They have said whatever they have to say. ..(Interruptions)..

SHRI V. HANUMANTHA RAO: There are 39,728 posts lying vacant for SCs/STs. India has got bundles of human resources with great talent. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumantha Rao, please associate.

SHRI V. HANUMANTHA RAO (ANDHRA PRADESH): Okay, Sir. I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. The Minister wants to react on this.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, this is a major issue. I think the House should debate on this one time. A lot of misinformation is floating. This newspaper story that the hon. Member has referred to is factually quite incorrect. Sir, this kind of OM has existed since 1979. What we are trying to do is, we are trying to further strengthen it. There had been no de-reservation of earmarked vacancies for the last ten years. Why are we doing it today? It was not done quietly; it was not done behind anybody's back. I have a copy of the report. As if it was a secret, it is on the website. It was done only for three reasons. One, creation of a separate national Commission for SCs and STs. As you know, earlier there is one Commission. When we created two different Commissions, different proforma was required. The second reason is replacement of vacancy-based register by post-based register. A decision was taken in 1995 to do that. And, the third reason was, ban on exchange of reservation between SCs and STs which was earlier being done. Now, it is not allowed to be done. It is a progressive step that we have taken. It is an open thing. It is on the website. Nothing has been done secretly. But, unfortunately, the newspaper has chosen to use words like the OM says 'unlocking of quota'. Where have the words 'unlocking of quota' been used? Newspaper is talking about it. It is not a responsible reporting, I am sorry to say. It is an OM which is tendering ..(Interruptions).. This is the Government which has launched a special drive, after we came to power in 2004, where more than 60,000 posts were filled during the drive.

Now, we have launched another drive in 2008, and it is the endeavour of the Government to see that there is no backlog vacancy at all.

SHRI JESUDASU SEELAM: We are ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over now. ..(Interruptions).. No more discussion ..(Interruptions).. No more discussion. ..(Interruptions).. Shri Bharatkumar Raut. ..(Interruptions).. Shri Bharatkumar Raut. ..(Interruptions).. No, no. Please ..(Interruptions).. What is this? ..(Interruptions).. Mr. Seelam, Please. ..(Interruptions).. Okay. ..(Interruptions).. Please. ..(Interruptions).. It is not the Question Hour. ..(Interruptions)..

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: We cannot respond to everything in Zero Hour. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. You give a notice. We will have a full-fledged debate. ..(Interruptions)..

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: It was actually an incorrect report. Let's have a full debate on this..(Interruptions)..

(followed by ysr- 1s)

-SK/YSR-PSV/12.25/1S

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When the Minister is agreeing for a full-scale debate on it, why are you raising it again?

INTELLIGENCE INPUTS ABOUT BANGLADESHI TERRORIST OUTFIT ALLEGEDLY PLANNING ATTACKS ON MUMBAI AND HYDERABAD

SHRI BHARATKUMAR RAUT (MAHARASHTRA): Sir, it is a matter of deep concern that our intelligence agencies have received inputs about renewed activities of Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh. Its activists are

likely to target Mumbai and Hyderabad cities. Sir, I am sure that our intelligence agencies and security forces will take due care and will not allow any plot to disturb civic life not just in these cities but in the entire country. I am hopeful about that. However, here we need to ponder upon the inputs. The Bangladeshis, who have been coming to India illegally for the last so many years, have really created a threat to the internal security of the country. Our erstwhile Chief Minister of Maharashtra, who is now a member of the Union Cabinet, has openly stated that we need to take care of the illegal immigrants from Bangladesh in this country. However, nothing has been done. I come from Mumbai. Let me tell you, Sir, that in Mumbai every day, day after day, and years after years, illegal Bangladeshis are entering the city and settling there. In Mumbai, many vital installations are there, namely, the Bhabha Atomic Energy Centre, oil refineries, oil depots, and international airport. If you see the locations of these installations, you will find huge slums where Bangladeshis are residing. There is no control over them. We don't know what business they do, how they make their living and why they are there. Nobody can control them and nobody can stop them.

Sir, many of these illegal immigrants have been enrolled in the voters' list of the last assembly election. I am not getting into politics. Whatever political purpose it had served I have nothing to say about this now. Because of political reasons or perhaps bureaucratic lethargy, these people have now become voters in India and perhaps tomorrow they will be claiming citizenship and will become 'authorised Indians.' What do we do about it? That is the main problem here. Sir, these

people have to be flushed out. Efforts were made in the past when the Bangladeshis were taken on a train and sent out of the Indian Border. But before our officers came back, these people were back in their slums. The Government should take proper care in this matter. Thank you, Sir.

(Ends)

INDEFINITE STRIKE BY JUTE MILL WORKERS IN WEST BENGAL

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में चटकल के ढाई लाख मजदूरों ने अपने 13 नुकाती माँगों के समर्थन में 14 दिसम्बर से लगातार हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल में 20 यूनियनें शामिल हैं। इनमें CITU, INTUC, BMS, AITUC भी हैं।

सर, यह भी देखिए कि चटकल में कितनी बेइंसाफी होती है कि बाजार में महँगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों को dearness allowance मालिक नहीं दे रहे हैं। कई सालों से उनका dearness allowance बंद है। जो मजदूर रिटायर होते हैं तब उनको ग्रैच्युटी नहीं मिलती है। बहुत-से ऐसे केसेज़ भी देखने में आए हैं कि प्रोविडेंट फंड का पैसा मजदूरों की तनख्वाह से तो काट लेते हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के ऑफिस में वह जमा नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि मजदूर जब रिटायर होते हैं तो उनको अपनी जिन्दगी भर की कमाई का प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं मिलता है।

इसके अलावा इस वक्त यूरोप के तमाम देशों में सिंथेटिक पर पाबंदी लग गई है, क्योंकि वह इको-फ्रेंडली नहीं है, जबकि जूट इको-फ्रेंडली है। इसलिए इंडिया में भी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार इस मामले को कोई अहमियत नहीं दे रही है। मैं यह समझता हूँ कि इस मामले में पश्चिमी बंगाल की सरकार, लेबर डिपार्टमेंट, को जो करना है वह तो कर ही रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्स्टाइल की मिनिस्ट्री को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए...।

(1टी/डी0एस0 पर क्रमश:)

श्री मोहम्मद अमीन (क्रमागत) : ताकि मजदूरों के जो जायज़ मुतालबात हैं, उनका तसफिया हो जाए और जो जूट मिलें बंद हैं, वे फिर से चालू हों, यही मेरा कहना है।

(समाप्त)

جناب محمد امین (مغربی بنگال): سر، میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پشچھمی بنگال میں چٹکل کے ڈھائی لاکھ مزدوروں نے اپنے 13 نکاتی مانگوں کے سمرتھن میں 14 دسمبر سے لگاتار ہڑتال کر دی ہے۔ اس ہڑتال میں 20 یونینیں شامل ہیں۔ ان میں CITU, INTUC, BMS, AITUC شامل ہیں۔

سر، یہ دیکھئے کہ چٹکل میں کتنی بےانصافی ہوتی ہے کہ بازار میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن مزدوروں کو ڈئرنیس الاؤنس، مالک نہیں دے رہے ہیں۔ کئی سالوں سے ان کا ڈئرنیس الاؤنس بند ہے۔ جو مزدور ریٹائر ہوتے ہیں تب ان کو گریجوٹی نہیں ملتی ہے۔ بہت سے ایسے کیسیز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ پرووڈینٹ فنڈ کا پیسہ مزدوروں کی تنخواہ سے تو کاٹ لیتے ہیں، لیکن پرووڈینٹ فنڈ کمشنر کے آفس میں وہ جمع نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی بھر کی کمائی کا پرووڈینٹ فنڈ کا پیسہ بھی نہیں ملتا ہے۔

اس کے علاوہ اس وقت یوروپ کے تمام دیشوں میں سنتھیٹک پر پابندی لگ گئی ہے، کیوں کہ وہ ایکو-فرینڈلی نہیں ہے، جبکہ جوٹ ایکو-فرینڈلی ہے۔ اس لئے انڈیا میں بھی اس پر پابندی لگنی چاہئے، لیکن بھارت سرکار اس معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پشچھمی بنگال کی سرکار، لیبر ڈیپارٹمنٹ، کو جو کرنا ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بھارت سرکار کے ڈیپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل کی منسٹری کو بھی اس میں انٹروین کرنا چاہئے۔

تاکہ مزدوروں کے جو جائز مطالبات ہیں، ان کا تصفیہ ہو جائے اور جو جوٹ ملیں بند ہیں، وہ پھر سے چالو ہوں، یہی میرا کہنا ہے۔ (ختم شد)

श्री उपसभापति : आर.सी. सिंह जी, आप सिर्फ एसोसिएट कीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करता हूँ और साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के intervention से पिछले साल 18 दिनों की हड़ताल के बाद समझौता हुआ था। वह समझौता अब implement नहीं हुआ, जिसके प्रतिवाद में 20 यूनियन एक साथ मिल कर वहाँ पर हड़ताल कर रही हैं। (समय की घंटी) इसलिए मंत्री महोदय इसमें immediately intervene करें और इस समझौते को implement करवाएँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूँ।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करता हूँ।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the Zero Hour mention made by Shri Mohammed Amin.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MATILAL SARKAR (TRIPURA): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

TARINI KANTA ROY (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

(Ends)

RE: DEMAND TO CURB ALLEGED SALE OF MEAT BLENDED WITH COW FLESH IN UTTAR PRADESH AND OTHER STATES OF THE COUNTRY

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, कल रात एक सनसनीखेज खुलासा सहारा चैनल द्वारा हुआ है। उसके अंतर्गत दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मरे हुए पशुओं के मांस को होटलों में ले जाकर खिलाया जा रहा है। उन पशुओं को मारने के लिए माफिया गैंग्स, जो जल्दी ही धन कमा कर करोड़पति बनना चाहते हैं, कई प्रकार के उपाय आजमाते हैं। उनमें से एक यह भी है कि जो पालतू पशु हैं, उनको जहर देकर मारा जाता है, उनको विष देकर मारा जाता है और फिर उनका मांस होटलों में दिया जाता है। जो मांस विक्रेता हैं, उनके यहाँ तक इसे पहुँचाया जाता है। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने भी यह आदेश दिया है कि राजधानी के आसपास के 40 किलो मीटर के क्षेत्र में इस प्रकार पशुओं की चीर-फाड़ नहीं हो सकती, लेकिन उन सब कानूनों, नियमों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। यही नहीं, जो पशु मारे जा रहे हैं या जिन पालतू पशुओं और आवारा पशुओं को विष देकर मारा जाता है, उनमें गाय का मांस भी अलग ..(व्यवधान).. संग्रहित करते हैं। भैंस, गाय और बछड़ों को जहर देकर मारा जाता है और फिर चुपके से, दो नम्बर से मांस विक्रेताओं को गाय का मांस बेचा जाता है और उसे खिलाया जाता है। यह अत्यंत मानवीय संवेदना वाला मामला है। यह धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास है, जो गलत तरीके से यहाँ पर पैदा किया जा रहा है।

माननीय महोदय, इस मामले में दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार मिल कर ऐसी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करे, क्योंकि यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रोकी गयी तो यह प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ेगी, लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाएगी और यह सद्भावना को बिगाड़ने का काम भी करेगी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार इस सारे मामले में मिली हुई है। वहाँ के जो लोग हैं, वे मिले हुए हैं। वहाँ की पुलिस मिली हुई है और पुलिस को राजनेताओं का संरक्षण है। उन्हीं की देखरेख में इस

प्रकार प्रछन्न रूप से गोहत्याएँ हो रही हैं और गौ का मांस होटलों में परोसा जा रहा है। इसको रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली की सरकार को नियंत्रित करें और इस मामले को आप स्वयं देखें।

(समाप्त)

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करती हूँ।

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान) : महोदय, मैं इस विषय के साथ अपने आपको एसोसिएट करता हूँ।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूँ।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : महोदय, मैं इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI BHARATKUMAR RAUT (MAHARASHTRA): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

(Ends)

RE: SPREADING OF BRAIN FEVER IN EASTERN UTTAR PRADESH

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं आपके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली बीमारी, मस्तिष्क ज्वर की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर, पिछले 30 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, बहराइच, गोंडा, आजमगढ़ आदि जिलों में अगस्त से लेकर फरवरी माह तक एक विशेष किस्म का बुखार फैलता है, जिसे मस्तिष्क ज्वर या जापानी बुखार के नाम से जाना जाता है। यह विशेषकर 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में होता है। इससे बच्चों में तेज बुखार, शरीर में ऐंठन होती है और बच्चा कोमा में चला जाता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या बच्चा विकलांग हो जाता है अथवा वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। पिछले 30 वर्षों में इस बीमारी के कारण हजारों जानें गयी हैं। इस वर्ष भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का बहुत भयंकर प्रकोप है।

कल लोक सभा में सरकार ने माना कि इस बीमारी से पूरे देश के अंदर 666 जानें जा चुकी हैं।

(1यू/एकेए पर क्रमश:)

aka-mks/1u/12:35

श्री नन्द किशोर यादव (क्रमागत) : उसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 545 लोग मरे हैं। सर, यह एक सरकारी आंकड़ा है, जबकि मरने वालों की संख्या कई हजारों में है। सर, इस गंभीर बीमारी का अब तक कोई विशिष्ट उपचार नहीं हुआ, न होता है। अभी तक इस बीमारी के वायरस के बारे में भी सरकार या जो अस्पताल हैं, कुछ पता नहीं लगा सके। इस बीमारी का आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में न कोई डाक्टर है, न टीका है, न दवा है। जहां सरकार ने कहा है कि हमने 100 प्रतिशत तक टीकाकरण किया है, वहां भी यह बीमारी भयंकर रूप से फैली है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संबंध में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त टीके की व्यवस्था करे और केन्द्र से डाक्टरों की एक टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश में अविलम्ब भेजने का काम करे। धन्यवाद। (समाप्त)

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इनसे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

(समाप्त)

RE.: SELLING OF RICE BELOW MSP BY FARMERS OF UTTAR PRADESH

प्रो0 राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने धान के लिए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दाना भी धान का खरीदा नहीं जा रहा है। नतीजा यह है कि किसान गरीबी की वजह से मजबूरी में और अपना जीवनयापन करने के लिए 800 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं और यह स्थिति इसलिए और भी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि पिछले वर्ष गवर्नमेंट को जो लेवी लेनी चाहिए थी, राइस मिलों से जो चावल FCI लेती थी, इटावा और मैनपुरी जिले से एक दाना भी नहीं लिया गया। करोड़ों रुपए का चावल गोदामों में भरा हुआ है और सड़ रहा है। किसानों को उस वक्त भी पैसा नहीं मिला ..(व्यवधान)..

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, यह जो मेंशन है, यह असत्य है। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : ये FCI को बोल रहे हैं, आप को नहीं बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अमर सिंह : आप क्या बात कर रहे हैं, राम गोपाल जी सही बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री बृजभूषण तिवारी : करीमपुरी जी, यह आप क्या बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अमर सिंह : असत्य है तो आप सच-सच बोलिए न। ..(व्यवधान).. आपसे मतलब नहीं है। ..(व्यवधान)..

प्रो0 राम गोपाल यादव : केन्द्र सरकार से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप बैठिए। ..(व्यवधान).. आप लोग बैठिए। ..(व्यवधान).. आप सब क्यों खड़े हैं? ..(व्यवधान)..

श्री बृजभूषण तिवारी : सर, ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप बैठिए। राम गोपाल जी बोल रहे हैं, आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं?

प्रो0 राम गोपाल यादव : सर, FCI ने एक दाना भी नहीं खरीदा, इसलिए पिछली बार भी पैसा नहीं मिला और अब मजबूरन 800 रुपए क्विंटल उन्हें धान बेचना पड़ रहा है और इस तरह से एक क्विंटल पर उन्हें 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। आशंका यह है कि जैसे ही किसान के घर से धान निकल जाएगा, व्यापारी के घर पर पहुंच जाएगा, फिर बिचौलिए और व्यापारी दाम बढ़ा देंगे, तब जाकर गवर्नमेंट उसे खरीदेगी और यह जो करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान किसान को हो रहा है, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी।

मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि आपने किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, उसको उसका वह मूल्य दिलाने की व्यवस्था करें और जो चावल रखा हुआ है पिछले वर्ष का, उसको उठवाने के लिए भी इंतजाम करें। (समाप्त)

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इनको एसोसिएट करता हूं।

डा0 सी0पी0 ठाकुर (बिहार) : सर, मैं भी इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

(समाप्त)

MKS-TMV-NB/1W/12.40

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Sir *

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, this is highly objectionable. (Interruptions)... This is highly objectionable. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, please. (Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: *

SHRIMATI BRINDA KARAT: She was a victim of rape. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? (Interruptions)...

श्री अमर सिंह : उपसभापति जी, इसको एक्सपंज कराइए ... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : ये क्या बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, your Zero Hour mention is on "Attempt to Tarnish the Image of Goa by Media". You are saying something which is contentious. (Interruptions)...

श्री अमर सिंह : इसको एक्सपंज कराइए, हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे ... (व्यवधान)

*** Expunged as ordered by the Chair.**

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति जी, इसको एक्सपंज करिए, ये क्या बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अमर सिंह : सर, यह बहुत ज्यादा दुस्साहस है ... (व्यवधान) इसको एक्सपंज कराइए ... (व्यवधान)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, please allow me to complete. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You have not given the text. (Interruptions)... You have given a Zero Hour mention "Attempt to Tarnish the Image of Goa by Media". (Interruptions)... Now, you are talking something which is contentious. (Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: No, Sir. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may say 'no'. (Interruptions)... Mr. Naik, please. (Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इसको आप एक्सपंज कराइए ... (व्यवधान)

श्री अमर सिंह : सर, इसको रिकॉर्ड से निकलवाइए ... (व्यवधान)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I am within my right. (Interruptions)... I will insist on my right. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Mr. Naik. Your request is to make a Zero Hour mention on "Attempt to Tarnish the Image of Goa by Media". (Interruptions)... Why are you raising it? (Interruptions)... This is your Zero Hour mention. (Interruptions)... You should explain now. (Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Please allow me to complete. (Interruptions)... Do you believe in the Constitution of India? (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, now your time is over. Your mention is over. (Interruptions).... I will examine it. If it is unparliamentary and objectionable, we will do the needful. (Interruptions)... Special Mentions. (Interruptions)... That is over. (Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Please allow me. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a question of allowing you. You have not given the text. Now you are saying something which is objectionable. We will have to examine the text., then you will be allowed. (Interruptions)... It is nowhere mentioned about raping and all these things. You are raising something for which the Chair can't take

the responsibility. (Interruptions)... Please. (Interruptions)... We will have to examine it. (Interruptions)... Mr. Naik, you are a senior Member. You are saying something else. What is admitted is "Attempt to Tarnish the Image of Goa by Media". It is about tarnishing the image of Goa in the media. (Interruptions)... But you are saying something else. (Interruptions)... Please, one minute. (Interruptions)... Please give the text of what you want to say and that will be examined, and if necessary ... (Interruptions)... Mr. Naik, I am giving a solution. (Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: A minor girl has been raped. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Brindaji, one minute.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We will not allow this House to be abused. (Interruptions)... It is very highly objectionable. (Interruptions)... Don't justify that. (Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : ये रेप को justify कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है ... (व्यवधान) पुलिस पोलिटिकल दबाव में काम नहीं कर रही है ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please one minute. Mr. Ravi Shankar Prasad, please. (Interruptions)..

श्रीमती माया सिंह : सर, ये justify कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : माया जी, आप बैठिए, मैं खड़ा हूं ... (व्यवधान) Mr. Naik, your Zero Hour mention is "Attempt to Tarnish the Image of Goa by Media". (Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: But he is tarnishing the image... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Brindaji. Now, there is a lot of objections because we have not seen the text. You give the text which will be examined. It will be again allowed if it is according to the rules. This issue is over. (Interruptions)... I am giving you a solution. You give the text which will be examined. (Interruptions)... You give the text. We will examine it. (Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: The words that he used should be expunged. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said that I would examine it and I would expunge it. (Interruptions).. Mr. Naik, you please give the text. I will examine it. If there is nothing objectionable, then, you will be allowed one more chance. (Interruptions)...

(Followed by 1X/VK)

-NB/VNK-VK & RG/1x & 1Y12.45 & 12.50

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, अभी जो बोला गया है, उसको expunge करवाया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I have said. Now because of paucity of time, you have to lay the Special Mentions. Dr. Gyan Prakash Pilania.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, I am not willing to lay it. My submission is, Special Mention has to be mentioned, it has to be read out with your kind permission. All the Members, who are here, have to think about the issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to me. It was decided that we will take up Special Mentions in the evening after the other business is over. But it was told that many of the Members would not be there in the evening. So we took a decision that Special Mentions will be taken

up now on the condition that they will be laid on the Table. Dr. Gyan Prakash Pilania.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, with objection I will carry out your order. This is against the spirit of...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a consensus decision which has been taken in the interest of the House.

SPECIAL MENTIONS

PK/9A

DISMAL SCENARIO OF POOR PUBLIC HEALTH SPENDING

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (RAJASTHAN): A World Health Organisation study of 2007-08 has revealed that India ranks 171 out of the 175 countries in the world in public health spending. This is less than some of the sub-Saharan African countries. In a country of one billion, about 5.2 per cent of the GDP is spent on healthcare. While 4.3 per cent is spent by the private sector, the Government continues to spend only 0.9 per cent on public health. Public health spending as a percentage of GDP is minuscule. Due to this, India is being overly dependent on private sector. With lowest insurance penetration, people are forced to spend out of their resources.

Neighbouring China ranks among the leading developing countries in public health, spending almost six per cent of the GDP. The world spends a total of $4.1 trillion on health. The United States of America spends 16 per cent of GDP on health, Sweden - 13 per cent, OECD - 11 per cent and India only 5.2 per cent.

There is growth in GDP, but there has been no increase in health-care spending. This inadequate public health spending has forced the public to depend on private sector.

India ranks among the top 10 countries for communicable diseases. It is today the world leader in chronic diseases like diabetes, hypertension and coronary artery disease. In India, 900 people die of tuberculosis daily. More than one-third of them are victims of HIV/AIDS.

In view of the above dismal scenario, I would urge the hon. Minister of Health and Family Welfare to take corrective steps.

(Ends)

PB/9B

DEMAND TO TAKE MEASURES TO PREVENT DEATHS OF CHILDREN IN BT. COTTON FIELDS IN GUJARAT

SHRI SANTOSH BAGRODIA (RAJASTHAN): Sir, I rise to commend the attention of this House to tragic deaths of young tribal children including minor girls in the Bt. Cotton fields of Banaskantha and Sabarkantha regions of Gujarat. By one estimate, about 1.5 lakh minor children, majority of whom are from the Dungerpur and Udaipur area of Rajasthan, work in hostile working conditions in these Bt. Cotton fields. Often these children are enticed by the middlemen to migrate to Gujarat without even informing their parents. There have been regular incidents of unnatural deaths of these children. As per reports in most of the cases, the local authorities have not been inclined to ascertain the causes of such unnatural and recurrent deaths. Instead, their effort has been to project these deaths as accidents or snake bites. Considering these circumstances, the parents and local organisations reasonably

suspect trafficking and sexual abuse of these children. While the local NGOs have raised alarm over recurrence of such incidents, it is reported that employers and involved authorities are trying to brush the issue under carpet. I appreciate that National Commission for Women and National Commission of Protection of Child rights have constituted a high-power committee to look into the issue. The Committee should ascertain the culpability of the local authorities and fix the responsibility. I demand that the Report of this Committee be placed before the House along with ATR. The State Government should be asked to take credible steps to stop the exploitation of children in cotton fields.

(Ends)

9c/skc

ILLEGAL TRANSPORTATION OF EXPLOSIVE MATERIALS IN WEST BENGAL, ORISSA AND JHARKHAND

SHRI MOINUL HASSAN (WEST BENGAL): Sir, it is reported that a ship carrying nearly 8000 tonnes of ammonium nitrate, a chemical used for manufacturing explosives, has been held up outside the Haldia Dock Complex after Intelligence reports surfaced that such cargo may have fallen into the hands of Maoists and other insurgent outfits earlier while being transported from the port to a factory in Jharkhand. The ship was bringing cargo from Muuga Port in Estonia. The modus operandi of carrying such explosives in the name of fertilizers is that after discharge of the cargo at the port jetty inside the port, the material is delivered directly to the party which, in turn, stores the material in three-four private godowns outside the port. These private godowns do not have necessary statutory clearances for storage of explosive substances. The

material is then taken to Gomia in Jharkhand in open vehicles (trucks/ dumpers) for manufacture of explosives for further supply to mining companies in the border districts of West Bengal, Orissa and Jharkhand. The material is siphoned off to insurgent groups active in East and West Midnapore and border districts of Jharkhand. Ammonium Nitrate was widely used by extremist groups during blasts in Gujarat, Bangalore, New Delhi and Uttar Pradesh in the recent past. Every day, there is theft and pilferage of various cargos from vehicles going out of the port despite Police deployment. What is worrying us is that the explosive substance is imported by M/s Indian Explosive Limited, which is neither a fertilizer manufacturer nor a fertilizer trader or distributor in India. It is an explosive manufacturer having its plant at Gomia in Jharkhand.

I would, therefore, request that the Government may conduct an inquiry into the illegal transportation of explosive materials in West Bengal, Orissa and Jharkhand States. (Ends)

GSP/9D

DEMAND TO ESTABLISH MORE BRANCHES OF BANKS AND APPOINT MORE EMPLOYEES IN ORDER TO MAKE EASY PAYMENT OF WAGES TO WORKERS INVOLVED IN GOVERNMENT SCHEMES.

SHRI MATILAL SARKAR (TRIPURA): The National Rural Employment Guarantee Act is a landmark legislation of the country and it has given birth to a continuous stream of works to the rural people across the country. Payment of wages is made through banks. Following this system, the procedure is being pursued in other schemes also. For example, the national old age pension is also being paid through banks. It is needless to say that the payment of salary to the employees is also being made in the bank accounts in some States. Thus the banks have become a very useful instrument in rendering services in the social sectors. This is an undeniable reality of the day.

This has to be understood that the banks have had to take this responsibility in addition to its normal business. While appreciating the process adopted as above, some new sets of problems are found to have cropped up, such as, serious shortage of bank staff, many panchayats under only one branch of a bank, bank employees retiring with no increase in strength, lack of understanding between blocks and banks, beneficiaries coming repeatedly for one stroke of payment, etc.

In this practical situation, I urge upon the Government to go deep to look into the problems and justifiably decide to establish more branches of banks, increase the number of employees in the banks, and, strengthen the coordination among the officials of the banks and blocks and people's representatives. Thank you. (Ends)

kgg/9e

NEED TO SOLVE PROBLEMS OF RAILWAY LOCO PILOTS

SHRI SYED AZEEZ PASHA (ANDHRA PRADESH): Sir, the loco pilots (engine drivers) of the Indian Railways is facing several problems since long. The nature of duty, responsibility and the environment of the loco running staff of Indian Railways are totally different from other railway workers. The rules, regulations and instructions pertaining to them too are different. All other railway workers have a scheduled work, a fixed daily duty hours and regular and constant periodical rest in a week. But, for the loco running staff, there is no fixed schedule in regard to their duty according to the timing of train, no fixed duty hours. The Parliamentary Standing Committee on Railway Safety recommended 8-hour duty in the year 2007.

Apart from the daily working hours, the periodic/weekly rest/holidays of the loco pilots is also uncertain. If a loco pilot breaks off at 10 a.m. a day and joins back for duty at 4 p.m. next day, then that is called as availing of periodical rest and if such 30 hours of periodical rest is given for 4 days a month, it is stated that statutory requirement of granting a weekly rest is fulfilled.

Further, the Running Allowance Committee-2002 recommended that trains which run at a speed above 100 kmph should be provided with a co-pilot instead of assistant loco pilot. These recommendations are implemented considering the safety aspect of high speed trains.

Hence, I demand that the Central Government should consider their reasonable demands of the railway loco pilots, i.e., working hours, weekly rest, providing a co-pilot at the earliest.

(Ends)

GS/9F

DEMAND TO ERADICATE THE SYSTEM OF MANUAL SCAVENGING AND PROHIBIT DISCRIMINATION AGAINST MANUAL SCAVANGERS/SAFAI KARAMCHARIES IN THE COUNTRY.

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान) : महोदय, 1976 में नागरिक अधिकारी संरक्षण कानून 1955 में धारा 7-A जोड़ते हुए किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर मैला उठाने के लिए मजबूर करने को अपराध मानते हुए इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। इसके 17 साल बाद 1993 में संसद ने एम्पलायमेंट ऑफ मेनुअल स्कावेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट पारित किया, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से भी मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एस0आर0 संकरन और वेजवाडा विल्सन की अगुआई में सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया कि देश के कई हिस्सों में शुष्क शौचालय की मौजूदगी संविधान की धारा 14, 17, 21 और 23 का उल्लंघन है और यह मानवीय गरिमा के भी खिलाफ है।

मैला ढोने वाले लोगों के पुनर्वास की योजना के नाकाम होने के कारणों पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट रोशनी डालती है। सीएजी ने इस योजना के अपने ही आंकड़ों को गलत बताया है। भले ही सरकार दावा करे कि इसने 2 लाख 68 हजार सफाई कर्मियों को इस प्रथा से मुक्त किया, परन्तु यह संख्या कम नहीं हुई है बल्कि यह बढ़कर 7 लाख 87 हजार तक पहुंच गई है। समस्या यह है कि जिन सफाईकर्मियों को यह

इस पेशे से मुक्त करने की बात करती है, वे वह नहीं हैं जिनका पुनर्वास किया गया है। इसके बजाय योजना के तहत ऐसे लोगों को कर्ज दिए गए जो ज्यादातर वास्तव में इस काम से नहीं जुड़े थे। सबसे भारी चूक तो यह थी कि योजना से उस कानून का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इस पेशे को खत्म करने की बात करता है। कानून बनने के बाद इन 15 सालों में किसी व्यक्ति से मैला ढुलवाने के लिए आज तक एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि संविधान के मुताबिक उन्हें दूसरे नागरिकों की तरह समान रूप से सम्मान मिले और यह न देखा जाए कि उन्होंने किस श्रेणी में जन्म लिया है। लाखों दलित आज भी इससे वंचित हैं।

(समाप्त)

LP/9G

DEMAND TO AMEND THE PLANTATION LABOUR ACT TO PROVIDE MORE AMENITIES TO THE TEA PLANTATION WORKERS IN THE COUNTRY

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चाय उद्योग के संकट एवं चाय श्रमिकों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

महोदय, देश में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 16 लाख है और उन पर आश्रितों की संख्या 65-70 लाख है।

चाय बागानों के श्रमिक आज भी बंधुआ मजदूरों की तरह हैं। उनका अपना कुछ नहीं है। घर और जमीन ही नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी व बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं से भी वे वंचित हैं।

भारत के चाय उत्पादन क्षेत्रों में मजदूरों की कमाई में भले ही भिन्नता हो, परन्तु उनका जीवन स्तर एक जैसा ही है।

महोदय, 1951 का जो प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट है, उसमें संशोधन जरूरी है। पुश्तों से जो बागानों में रह रहे हैं, उनको जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। बागानों में पंचायत तो शुरू हुई, पर जमीन के अधिकार से मजदूर वंचित हैं। इन सब कारणों से मजदूरों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट में संशोधन करते हुए मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। (समाप्त)

AKG/9H

DEMAND FOR ENQUIRY INTO DELAY IN TABLING HINDI VERSION OF LIBERHAN COMMISSION REPORT

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संसद के पटल पर रखी जाने वाली रिपोर्ट्स हिन्दी में भी रखी जाएँ। लिब्रहान रिपोर्ट देरी से रखे

जाने का कारण बताया गया था कि उसका हिन्दी रूपान्तरण उपलब्ध नहीं है एवं वस्तुत: परिस्थितियों के दबाव में केवल अंग्रेजी प्रति ही रखी गई थी। बाद में कुछ दिनों में ही हिन्दी प्रति भी रखी गई। इसका अर्थ है कि चाहने और योजना करने पर दोनों प्रतियाँ साथ-साथ रखी जा सकती थीं। इससे यह झलकता है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन के दायरे में भी आ सकता है। ज्ञातव्य है कि माननीय गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं एवं महामहिम राष्ट्रपति इसके आठ प्रतिवेदनों को स्वीकृति दे चुके हैं।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह मामले की जाँच करे और विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व तय करे एवं सदन को बताए।

(समाप्त)

SK/9J

DEMAND TO BRING LEGISLATION TO GIVE RIGHT TO WORK TO THE CITIZENS OF THE COUNTRY

DR. JANARDHAN WAGHMARE (MAHARASHTRA): Our Constitution has not given right to work to citizens which is necessary to ensure them livelihood. It is under the Directive Principles of State Policy and not under the Fundamental Rights. Right to education so far was under the Directive Principles of State Policy. But it has now been brought under the Fundamental Rights. It has emanated from article 21 which ensures protection of life and personal liberty. If right to education has emanated from article 21, why can't right to work emanate from the same Article? Work is more essential to protect life and personal security. Work is more necessary for livelihood than education. Education certainly enhances the quality of human life, but work is essential for human existence itself. Parliament has passed a legislation which gives right to education to children from 6 to 14 years of age.

Such a law is essential for giving right to work. It will be a very important social security measure. National Rural Employment Guarantee Act is one such historical measure. But poverty alleviation programmes and social security measures are piecemeal in nature. About 260 million people of our country are below the poverty line. About 42 per cent of our children suffer from hunger and malnutrition. Instead of having several piecemeal measures, why should'nt we give right to work to our citizens?

I, therefore, urge upon the Prime Minister to take a stride in that direction.

(Ends)

SCH/9K

DEMAND TO INCLUDE LABOURERS WORKING ON ROADS FOR BENEFITS UNDER VARIOUS SOCIAL SECURITY SCHEMES.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं, जिसमें एक ठेकेदार के अधीन Border Road Organization के लिए जिंगजिंगबार, हिमाचल प्रदेश में सड़क पर कार्य कर रहे करीब 56 मजदूर भारी बर्फबारी के कारण चार दिन तक बर्फ में फंसे रहे। लाहौल घाटी में बर्फबारी के कारण कुछ मजदूरों की मौत हो गई।

महोदय, ये मजदूर भारी बर्फबारी व खराब मौसम में सड़क बनाने या सड़क पर से बर्फ हटाने का कार्य करते हैं। आप इन मजदूरों को कई बार नंगे पैर शून्य डिग्री से भी कम तापमान में कार्य करते हुए देख सकते हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी सड़क के किनारे तिरपाल लगाकर कर दी जाती है। इनके भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बीमा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया जाता है।

महोदय, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत कारखानों में काम करने वाली लेबर के लिए ये तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, किन्तु जो वास्तव में लेबर हैं, वे

बड़ी दयनीय परिस्थितियों में सड़कों पर कार्य कर रहे हैं। किसी अप्रिय घटना के होने पर ठेकेदार उनसे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और सरकार भी उन्हें या उनके परिवार वालों को किसी प्रकार की मदद नहीं देती है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि सरकार सड़कों पर कार्य करने वाले इन मजदूरों के लिए भी कोई कारगर योजना बनाए और इन्हें भी कारखानों में कार्य कर रहे मजदूरों के समान सुरक्षा, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(समाप्त)

YSR/9L

DEMAND TO WITHHOLD SALE OF GOVERNMENT'S STAKE IN DISHERGARH POWER SUPPLY COMPANY LIMITED

SHRI R.C. SINGH (WEST BENGAL): The Government of India has decided to sell its entire stake of 57.76 per cent in Dishergarh Power Supply Company Limited, a Central PSU which runs on PPP mode, to Shreyee Infrastructure and the IPCL. Out of 57.76 per cent shares, the LIC got 30.62 per cent shares, United Insurance Company got 11.36 per cent shares, Oriental Insurance Company got one per cent share, Andrew Yule Company got 7.12 per cent shares, Bengal Coal Company got 4.7 per cent shares and Jharia Coal Company got 3.38 per cent shares. The remaining 32 per cent shares are held by Descon Limited.

I understand that the above sale of Government's share has been made without the approval of the Ministry of Finance and the nodal Ministry. The sale is total violation and against the interests of workers. Nothing has been mentioned or finalised as to what would happen to the workers who are working in Dishergarh Power Supply Company Limited. They have been opposing the sale of Government's stake right from the beginning.

So, I strongly oppose this move and demand the Government to desist itself from selling PSUs which is detriment to the progress and interest of the country. Now the workers' future is in dilemma as they do not have the job security and never know what will happen once the company goes into the private hands. So, I also appeal to the Finance Ministry and the nodal Ministry not to approve of this sale.

(Ends)

VKK/9m

DEMAND TO GIVE CLEARANCE TO KOCHI METRO RAIL PROJECT IN KERALA

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I would like to draw the attention of the House to the long-standing demand of the people of Kerala. The Government of Kerala had submitted a proposal for Kochi Metro Rail Project. It was designed to ease the traffic congestion and reduce pollution. The State Government has allotted a token amount for initial work and has started a project office. The higher level officials have been appointed.

The Urban Development Ministry has included Kochi Metro in its 100 days' flagship programme. The Planning Commission has also given clearance to this project. But, the Central Cabinet has deferred this issue. The act of the Central Government is a serious discrimination to the State of Kerala.

I, therefore, request the hon. Prime Minister of India to intervene in this issue and give clearance to Kochi Metro Rail Project in public sector.

(Ends)

MKS-9N

STRICT IMPLEMENTATION OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM IN AGENCY HILL AREAS OF ANDHRA PRADESH

SHRIMATI T. RATNA BAI (ANDHRA PRADESH): Sir, I would like to draw the kind attention of the august House to the underweight stock supplied, under the Public Distribution System, to the tribals living in the country, especially in Andhra Pradesh. Secondly, the Government of Andhra Pradesh is supplying rice to 113.05 lakh families up to a maximum of 20 kgs. per family. Thirdly, 21 per cent of food grains from Fair Price Shops is not reaching the target group, i.e. 270 kgs. of foodgrains earmarked for each household, per annum, did not reach.

Sir, in the agency areas, there is not only underweight ration available at the PDS counters, but even because of bad condition of roads and lack of storage facilities, some quantity of rice which is not reaching the targeted people is also being diverted. When the less allocation is made, the tribal area is targeted for cutting the quantity, without considering their acute poverty.

Lack of transport subsidy for PDS items in Hilly tracts of tribal areas, particularly in Andhra Pradesh, is the reason for diverting the stocks. Despite huge amounts being spent by the Government on PDS, considerable share of stock is not reaching the target group. Sir, I, therefore, request the concerned Ministers to take data on this for looking into the matter, besides taking all measures to check the malpractices mentioned above.

(Ends)

TMV/9O

REQUEST TO RELEASE AGRICULTURE INSURANCE CLAIMS AMOUNT OF Rs. 356.58 crores TOWARDS CENTRAL GOVERNMENT SHARE

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, the crop insurance claims in respect of Kharif 2008 season were approved by Agriculture Insurance Company of India, New Delhi, for an amount of Rs. 801,20,47,277 to be paid to 7.57 lakh affected farmers.

As per the provisions of the Scheme, Agriculture Insurance Company, the State Government and the Central Government would contribute for settlement of claims. The Agriculture Insurance Company is ready with their share of contribution of Rs. 88.05 crores and the Government of Andhra Pradesh has already issued orders for releasing the State's share of contribution i.e., Rs. 361.44 crores. The disbursements of insurance claims are pending for want of Central share of claims for Rs. 356.58 crores.

The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh had written a letter in this regard to the hon. Minister of Agriculture and requested him to release the amount early so that affected farmers are compensated. In addition, the Government of Andhra Pradesh has suggested certain measures like:

(3) Calculating average yield instead of taking moving average of 3 to 5 past years.

(4) At present, there are indemnity levels of 60 per cent, 80 per cent and 90 per cent for insured crops. There should be only one level of indemnity at 90 per cent.

(5) Post harvest losses on account of cyclone heavy rains should also be covered for a period of 2 weeks from harvesting date.

(6) Premium subsidy to small and marginal farmers which was 50 per cent earlier is being phased out on sunset basis. This should be restored.

I, therefore, urge upon the Government to take immediate necessary measures in releasing the amount for the benefit of farmers. Thank you.

(Ends)

(FOLLOWED BY VK "9P")

PSV/9P

RE: DEMAND TO EXEMPT CO-OPERATIVE BANKS FROM OPERATION OF SECTION 80 P OF INCOME TAX ACT ON THEIR PROFIT

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी(राजस्थान): महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2006 में आयकर कानून में संशोधन करके सहकारी बैंकों के लाभ को भी कर दायरे में ले लिया। उस समय भी इसका विरोध किया गया था किन्तु उसे दरकिनार कर दिया गया। सहकारी बैंक तब से ही उन्हें कर दायरे से मुक्त करने की माँग करते रहे हैं।

सहकारी बैंकों का ढाँचा अन्य बैंकों से अलग होता है। इन बैंकों की हिस्सा पूँजी-धारक ग्राम सहकारी समितियाँ होती हैं, जिन समितियों के अंशधारक किसान होते हैं। जिला सहकारी बैंकों का लाभ मूलत: पूँजी के संवर्द्धन और रिजर्व फण्ड सृजित करने के काम आता है। इससे कृषि साख और सेवाओं को बल मिलता है और ये ग्रामीण विकास की अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि कभी लाभांश वितरित किया जाता है, तो उसका उपयोग ग्राम स्तरीय समितियों के दृढ़ीकरण में होता है। ये समितियाँ खाद, बीज, कीटनाशक, छोटे कृषि उपकरणों आदि के लिए ऋण देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन छोटे और सीमान्त कृषकों को

अपने पैरों पर खड़ा होने में सहयोग करते हैं जिन्हें अन्य बैंक ऋण नहीं देते। इस सारी व्यवस्था में कोई व्यक्ति विशेष लाभान्वित नहीं होता।

सहकारी बैंकों के लाभ पर करारोपण से इस सारी प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। जहाँ सरकार सहकारी आन्दोलन को जीवन का आधार बनाने की बात करती है वहाँ यह प्रतिगामी कदम इसके पूर्णत: विपरीत है। अत: मेरी माँग है कि सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के ऑपरेशन से तत्काल मुक्त किया जाए।

(समाप्त)

VK/9Q

DEMAND TO TAKE SUITABLE MEASURES TO CHECK INCIDENTS OF ACCIDENTS DURING FLIGHTS OF SUKHOI FIGHTER AIRCRAFT

SHRI BHARATKUMAR RAUT (MAHARASHTRA): Sir, it was a sigh of relief to know that the Indian Air Force has resumed to fly Sukhoi fighter aircraft and soon all Sukhois, India's frontline fighter jets, will be back into operation. However, the fact is India witnessed two accidents involving Sukhoi within last eight months. The first accident happened in April and the second on 30th November when the jet crashed at Jaisalmer. This resulted in IAF's decision to ground the entire fleet for thorough check.

Considering that the IAF depends a lot on the Sukhoi, it is not a good sign that the jet has started developing fatal snags. Apart from creating an atmosphere of uncertainty in the minds of the IAF personnel, such accidents also result in loss of human life. The Sukhoi jets were inducted into the IAF in 1996. The IAF has 100-odd such fighter jets and according to plans the total strength is envisaged at 280 in the next few years. In this situation, the Defence Ministry should ensure that all aircraft give trouble free service.

The MiG aircraft with the IAF created havoc in the recent past due to series of crashes resulting in the loss of valuable pilots. They were described "flying coffins" and many pilots were reluctant to operate the MiGs.

We must ensure that similar situation does not arise in the case of Sukhoi. If necessary, the IAF must enter into a comprehensive contract with the Russian manufacturers of Sukhoi and take all-time guarantee of constant check up and servicing. Thank you. (Ends)

RG/9R

DEPLETION OF WATER RESOURCES AND THEIR CONSERVATION THROUGH JUDICIOUS MANAGEMENT

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA (MAHARASHTRA): Sir, depletion of surface and ground water resources, coupled with uncertain monsoon conditions, are diluting our capability to sustain economic growth. NASA's twin GRACE satellites orbiting the earth in formation at a height of 300 miles and roughly 137 miles apart, have revealed that Punjab, Haryana and Rajasthan lost 109 cubic km of water in six years. India's food bowl, with a paddy coverage of 38,061 sq. km, is losing groundwater at the rate of one metre annually. Droughts and floods have played havoc with the standing crops and livestock. Nexus between climate change and the water crisis need holistic comprehension to evolve modalities to combat climate changes, conservation, preservation and management of all water resources.

Delhi University is setting up a UNESCO supported Water Technology and Management Centre. Development of low-cost water

technologies for water treatment and water recycling is indispensable. Our scientists should invent or harness techniques in this direction. During May, 2008 Olympic, China's utilisation of cloud seeding techniques is a practical example for regulating rains. Simultaneously, to create awareness at all levels to save water, stop pollution, reckless cutting of trees and other environmental hazards, detrimental impact of impending earth-warming, etc. are factors calling for immediate solutions.

I, therefore, urge upon the Government to devise policy strategies to avoid a national catastrophe by sustaining existing water resources, adopting innovative water management techniques. For all of us, this should be an article of faith to support and supplement individual efforts like water conservation and its judicious recycling.

(Ends)

9s/ks

STRIKE BY NURSES IN BATRA HOSPITAL IN DELHI

PROF. P. J. KURIEN (KERALA): Sir, nurses working in many of the private hospitals in Delhi are in a very pathetic condition. They are almost like bonded labourers. Neither proper wages are given, nor adequate leave and other facilities. They are forced to work over time without any overtime allowance. These nurses who render such a great service to the society are being totally neglected. There is no proper law or rules to govern their salary and service conditions.

Nurses in Batra Hospital, which is a multi-speciality hospital, have been on strike for about a week now. The management is not prepared

to listen to their genuine grievances. Consequently, patients are also suffering. The Union Government has a responsibility in the matter.

I urge upon the Minister of Health and Family Welfare to intervene immediately to resolve the strike and mitigate the grievances of the striking nurses.

(Ends)

SHRIMATI BRINDA KARAT (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

(Ends)

TDB/9T

MASS GRAVES IN KASHMIR VALLEY

SHRI MOHAMMAD SHAFI (JAMMU & KASHMIR): Sir, International People's Tribunal on Human Rights in its report titled 'Buried Evidence' made public on 2nd December, 2009 in Srinagar, has stated that 2700 graves have been detected in the northern districts of Baramulla, Kupwara and Bandipora in Kashmir Valley burying around 3000 persons. The said report has, besides giving details about parents of disappeared persons, also shown pictures of these graves. During the press conference, the authors of the report stated that during the last 20 years thousands of young men disappeared and thousands have been killed in fake encounters. This issue has been agitating the minds of general public, causing alienation and discontent. Till date no response has come from the Union of India about this serious issue. This is causing a

lot of resentment among the public and image of the country is likely to suffer damage in the international community. As such, an urgent response in this matter from the Government of India is prayed for.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-one minutes past twelve of the clock.

1z/1.50/ks-gs

The House reassembled after lunch at fifty-four minutes past one of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prakash Javadekar to continue on the Appropriation (No.4) Bill, 2009. Your party is left with 25 minutes.

THE APPROPRIATION (NO.4) BILL, 2009 -- (contd.)

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, जिस तरह से कल मैंने शुरू किया, मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा कि हम वित्तीय व्यवस्थापन, financial management of the country की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे चल रहा है, जहां वित्तीय घाटा 6.8 है और खुद वित्त मंत्री जी ने कल पूरक मांगे रखते समय कहा कि 6.8 का घाटा रहेगा। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि यह घाटा आठ परसेंट से कम नहीं होगा। un-budgeted खर्चे और बढ़ेंगे और वह दो परसेंट बोझ और बढ़ेगा। जो स्टेट का घाटा है, वह अगर पकड़ेंगे, तो लगभग वित्तीय घाटा 14 परसेंट का हो जाता है।

(2ए पर जारी)

LP/1.55/2A

श्री प्रकाश जावडेकर (क्रमागत) : यह बहुत खतरनाक चीज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंदी के दौर में यह घाटा भी ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी वे यही कहेंगे कि घाटा ठीक है? अगर घाटा ठीक होता तो हमने FRBM कानून क्यों बनाया होता कि जिसके तहत यह कहा जाता था कि चार परसेंट से अधिक वित्तीय घाटा नहीं होगा और कम करते जाएंगे? यह वित्तीय घाटा आपकी इस वित्तीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। आने वाले दिनों में संकट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इसकी मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं। आज जो महंगाई बढ़ रही है और लोगों को पीस रही है, उसका भी एक कारण इस वित्तीय व्यवस्थापन की असफलता, विफलता का यह प्रमाण है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। यह कोई आसमानी संकट नहीं है, यह सुल्तानी संकट है और उस सुल्तान का नाम, जैसा कि मैंने परसों भी बताया था कि यू.पी.ए. सरकार है और यू.पी.ए. सरकार की वित्तीय नीतियां हैं, जिसके कारण यह हो रहा है। इन्होंने क्या-क्या किया है, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने 2004 में सत्ता में आते ही किसानों से खरीद की मोहलत बड़ी-बड़ी कंपनियों, कारगिल, मोंसेंटो, रिलायंस, अदानी जैसी कंपनियों को दे दी। वे कंपनियां खरीद करती हैं और भंडारण करती हैं। यह मिलियन टन्स का कारोबार है। उसके कारण सरकार के गोदाम में कमी रही और सरकार गरीब को पैंतीस किलो अनाज देने का वादा भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए गरीब भी बाजार में आए। इनकी जो आयात-निर्यात नीति है, वह ऐसी है, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं केवल दो आंकड़े उनके लिए बताऊंगा कि चीनी का भंडार बहुत लबालब भरा है, ऐसा आपके कृषि मंत्री कह रहे थे। उन्होंने चीनी का निर्यात नौ महीने पहले किया। 48 लाख टन चीनी इस देश से 12 रुपए की दर से निर्यात हुई। यह नोट करने की बात है कि 48 लाख टन चीनी 12 रुपए की दर से निर्यात हुई और आज 70 लाख टन 30 रुपए की दर से आयात हो रही है। क्या वित्तीय व्यवस्थापन है? क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? अगर इस तरह से व्यवहार करोगे तो महंगाई भी होगी और वित्तीय घाटा भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं, मैंने परसों भी सवाल पूछा था, वित्त मंत्री जी मुझे जवाब देंगे कि आज जो हमें चालीस रुपए में चीनी मिल रही है, वह पिछले साल की बनी हुई चीनी है, इस साल की आनी अभी

बाकी है, पिछले साल की चीनी का किसान को क्या दाम मिला था? सोलह रुपए मिला था। अगर उसको सोलह रुपए मिले थे, तो बाजार में हमें पच्चीस रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन आज वह चीज चालीस रुपए में मिल रही है, यह पंद्रह रुपए बीच में कहां बढ़े और किसने खाए? इस पर किसका नियंत्रण है? यह चीज दिखाती है कि आपका सरकारी वित्त पर नियंत्रण नहीं है और बाजार पर भी नियंत्रण नहीं है। दाल और तेल का आयात किया गया, लेकिन दाल और तेल का आयात करते समय वह बंदरगाह पर सड़ रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, यह आपका व्यवस्थापन है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरक मांग में पैसा मांगते कि हम सब्सिडी देना चाहते हैं, गरीब को महंगाई से राहत देना चाहते हैं और उसको हर महीने पांच किलो दाल, पांच किलो तेल, पांच किलो शक्कर, दस, पंद्रह किलो गेहूं और दस, पंद्रह किलो चावल कम रेट पर मुहैया कराएंगे, सब्सिडाइज रेट पर कराएंगे, अगर आप इस सब्सिडी के लिए पूरक मांग रखते, तो हम उसका समर्थन कर सकते थे, क्योंकि वह ठीक होता। यह जो महंगाई है, इस महंगाई को काबू करने में आपकी वित्तीय नीति पूरी तरह से विफल रही और यह आपकी वित्तीय नीति की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, इसलिए मैं इसे आज फिर से दोहराना चाहता हूं। यह मंदी का दौर है। मंदी से आप कैसे निपट रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आपको पता है कि मंदी के time में आपने बहुत सारे insentives दिए, लेकिन किसको insentives दिए? ये आपने उद्योगपतियों को दिए, उद्योगों को दिए। जो चालीस लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, उन चालीस लाख मजदूरों को आपने क्या सहायता दी, मैं यह पूछना चाहता हूं?

(AKG/2B पर जारी)

AKG/2B/2.00

श्री प्रकाश जावडेकर (क्रमागत) : आपने उन गरीब मजदूरों को एक पैसे की भी सहायता नहीं की, जिनके जॉब्स गए, जिनकी नौकरियाँ गईं, जिनका काम चला गया, जो बेरोजगार हो गए। जो लोग एक-डेढ़ साल बेरोजगारी में रहे, उनको आपका एक पैसा भी नहीं मिला। अगर आप इसके लिए पूरक मांग रखते, तो हम इसका समर्थन कर सकते थे। कैसा है यह वित्तीय व्यवस्थापन?

आपने नारा "गरीबी हटाओ" का दिया। बहुत पहले दिया, 30-40 साल हो गए, लेकिन आज गरीब की क्या स्थिति है? आपके ही आँकड़े बता रहा हूँ। योजना आयोग कहती है कि देश में 28 फीसदी गरीबी है; तेंदुलकर, जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, तेंदुलकर समिति का सर्वेक्षण है कि यह 40 फीसदी है; ग्रामीण मंत्रालय की सक्सेना समिति ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे 50 फीसदी लोग रह रहे हैं; NSSO के सर्वेक्षण में कहा गया है कि 60 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और आपकी सेनगुप्त कमेटी ने कहा कि 20 रुपए से नीचे कमाने वाले 70 फीसदी लोग हैं। इसलिए गरीबी रेखा के बारे में स्थिति बद से बदतर हो रही है और गरीबों की तादाद बढ़ रही है। यह आपकी वित्तीय संचालन, वित्तीय नीति की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने पूरक मांगों में 135 करोड़ मांगा है कि गरीबी रेखा का एक नया सर्वे करेंगे। नए आँकड़े आएंगे, लेकिन आप यह कब बताएंगे कि गरीबी कब खत्म होगी, लोग गरीबी से बाहर कैसे आएंगे? उनको empower करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन-सी वित्तीय नीति अपना रहे हैं, इसका कोई खुलासा आपने नहीं किया है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है?

दो बड़ी बातें हैं। एक है infrastructure. Infrastructure का मसला है देश की तरक्की से और देश की तरक्की का मापदण्ड होता है आपका सफल वित्तीय संचालन। लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है? मैं केवल बिजली की बात करूँ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में पॉवर सेक्टर में आपने 78 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है। अगर पाँच साल में 78 हजार मेगावाट तैयार करना है, तो हर साल 16 हजार मेगावाट होना चाहिए। सीधा हिसाब है। 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 40 हजार मेगावाट तक जाना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 12 हजार मेगावाट हुआ और 19 हजार मेगावाट का target रखा गया था। कैसे पूरा होगा 78 हजार मेगावाट का लक्ष्य? जब हमने पॉवर मिनिस्ट्री की Consultative Committee में पूछा कि क्या दिक्कत है, तो एक दिक्कत बताई गई, वित्त मंत्री सुन लें, कि पॉवर सेक्टर के reform और पॉवर सेक्टर में बिजली की generation बढ़ाने के लिए निधि की उपलब्धता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की कमी है। अगर infrastructure के लिए पैसे की कमी है, तो आपका क्या वित्तीय संचालन है? अगर वित्तीय व्यवस्थापन ठीक होता, तो infrastructure के लिए पैसे की कमी नहीं होती। हमने infrastructure bond

निकाले थे, हमने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन अगर वित्तीय व्यवस्थापन ठीक होता, तो यह पॉवर सेक्टर आज पैसे के कारण hungry नहीं रहता।

आपने एक दूसरा नारा दिया था कि हर रोज 22 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या प्रत्यक्ष वास्तविकता है? स्थिति ऐसी बदतर है कि 22 किलोमीटर नहीं हो रहा है, हमारे समय जो 11 किलोमीटर का average था, वह 4 किलोमीटर पर आ गया। इसलिए उसमें भी कमी है। अनेक सेक्टर्स हैं, जहाँ bidding के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। कभी-कभी public investment करनी पड़ती है। मंदी के दौर में जब आप public investment करके infrastructure का निर्माण करेंगे, तो वह सुविधा केवल आने वाले समय के लिए नहीं होगी, आप मंदी से भी निबट जाएंगे और उससे ज्यादा काम होगा कि ये सड़कें बनेंगी और infrastructure development से ही देश की तरक्की होगी। लेकिन यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है, जहाँ infrastructure के लिए ही पैसा नहीं है!

आपने disinvestment की बात कही है, कितने proceeds आएंगे, यह बताया है। लेकिन आपने commit किया था कि disinvestment से, विनिवेश से जो पैसा आएगा, वह शिक्षा और health care में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है? वह तो general pool में जा रहा है। यह आपका वित्तीय घाटा कम करने के लिए जा रहा है। मैंने कहीं उसका कोई अलग से earmarking तो देखा नहीं, न उसका अलग एकाउंट है, न कुछ काम है।

(2सी/एससीएच पर जारी)

SCH-KLS/2C/2.05

श्री प्रकाश जावडेकर (क्रमागत): यह कैसा व्यवस्थापन है कि एक तरफ आप विनिवेश भी कर रहे हो, लेकिन उसकी बेसिक ऐफिशिएंसी बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे हो। जो पैसा आ रहा है, वह जनरल पूल में जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ Fiscal Management की विफलता है, फिर supply constraints है, लेकिन मेरा उससे भी बड़ा चार्ज यह है कि you have stopped reforms. सुधारों को आपने ताक पर रख दिया है। आप कौन से सुधार ला रहे हो? आप न वित्तीय प्रणाली में सुधार ला रहे हो, न

कर प्रणाली में सुधार ला रहे हो, न उद्योग की नीति में ला रहे हो, न ही किसी अन्य क्षेत्र में ला रहे हो।

आपको मालूम है कि 90 के दशक में एक बार भारतीय उद्यमियों ने निर्णय किया था और उसके कारण उन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया, जिसको आज तक लोग नमस्कार कर रहे हैं। भारतीय उद्यमियों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि अगर उद्योगों को आजादी दोगे तो वे क्या-क्या कर सकते हैं और उन्होंने उसे सफल बनाकर दिखाया। अब उनको आगे की आजादी चाहिए, क्योंकि उनको अभी और आगे बढ़ना है। हम अपने देश को किससे कंपेयर करेंगे? हमारे पड़ोस में चीन है, लेकिन बार-बार हम यही कहेंगे कि चीन का उदाहरण मत दो, क्योंकि वहां तानाशाही है। मंत्री महोदय, यह सही नहीं है। चीन का उदाहरण इसलिए प्रासंगिक है कि पांच साल में आप जहां 78,000 मैगावाट बिजली निर्माण का लक्ष्य रखते हो और जो आधा भी पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि या आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आपका वित्तीय संचालन ठीक नहीं है। वहीं चीन ने नये सिरे से एक लाख मैगावाट per year बिजली का निर्माण करके दिखाया है और सालों से वह करता आ रहा है। आज जहां हम 1,20,000 मैगावाट पर अटके हुए हैं, वहां वह 8 लाख मैगावाट तक पहुंच गया है। तरक्की का पैमाना यह होता है, इसको कहते हैं Fiscal Management और इसको कहते हैं वित्तीय व्यवस्थापन। इसी के सहारे आज चीन अमरीका के बेल आउट को बेल आउट कर रहा है। चीन से ही तो पैसा गया और उन्होंने अमरीका के सारे बेल आउट plants को ही परचेज़ कर लिया। उनके पास डॉलर का अपार भंडार है। हमारे पास अभी मंदी के दौर में 70-80 बिलियन डॉलर्स की कमी आई, और जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसका उपयोग करने की कितनी बार चर्चा हुई? क्या आपने उसके एक प्रतिशत पैसे का भी उपयोग किया है? आपने उसका उपयोग न इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है और न ही किसी और दूसरी चीज़ के लिए किया है। यह कोई अच्छे वित्तीय व्यवस्थापन का नमूना नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने चुनाव से

पहले ऐसे बहुत सारे खर्च कर दिए, जो untargeted subsidies करके बता दिए गए। आप लोग बहुत * कि हमने किसानों के 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। वित्त मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि आज क्या स्थिति है? यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण जी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: * अच्छा शब्द नहीं है।

श्री प्रकाश जावडेकर: ठीक है, मैं * शब्द वापस ले लेता हूं।

श्री उपसभापति: * शब्द निकाल दीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण जी बैठे हुए हैं और उनको भी यह मालूम है। आज जब 16 दिसम्बर को हम यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं, विदर्भ में इस महीने आज तक की तारीख तक के 15 दिन में 22 किसानों ने आत्महत्या की है। एक साल में 926 लोगों ने आत्महत्या की है। Prime Minster Special Package लाने के बाद और आपके द्वारा कर्ज माफी के बाद हालात यह हैं। आपकी कर्ज माफी लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है। यह ठीक है कि कुछ चंद किसानों के पांच-पांच या दस-दस लाख माफ हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां पर जरूरी था, जिस विदर्भ और तेलंगाना में आत्महत्या को रोकने के लिए यह स्कीम बनाई गई थी, वहां पर आत्महत्याएं बदस्तूर जारी हैं। यह आपकी वित्तीय नीति की विफलता का एक और प्रमाण है और चुनाव फंड आपने ऐसे ही खर्च कर दिया। Populist measure लेने की आड़ में और किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए आपने जो यह सब किया है, इसकी कीमत आज देश को चुकानी पड़ रही है।

*** Expunged as ordered by the Chair.**

दूसरी बात, मैं यह कहता था कि प्राइम मिनिस्टर का पैकेज हो या कर्ज माफी हो, वह सही तरीके से लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका फायदा सबको नहीं मिला। जो जरूरतमंद किसान हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी अर्थव्यवस्था में सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्ज माफ करने की क्षमता थी, लेकिन उस अवसर को आप चूक गए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है।

आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा था कि काले धन को हम 100 दिन में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन क्या हुआ?

2d/PSV पर जारी

-SCH/PSV-SSS/2D/2.10

श्री प्रकाश जावडेकर(क्रमागत): केवल चंद पत्र आपके गए हैं। सरकार बार-बार यह कहती है कि हम स्विट्जरलैंड के साथ नेगोशिएट करेंगे। वहाँ जर्मनी देने को तैयार था, बाकी लोग भी यह जानकारी देने को तैयार थे, लेकिन आप जानकारी लेने को भी उत्सुक नहीं हैं और न ही काला धन वापस लाने को उत्सुक हैं। अपने देश में जो पैसा नए सिरे से आ सकता है और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए बिजली का निर्माण कर सकता है, सड़क का निर्माण कर सकता है तथा सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, उसको आप नहीं ला रहे हैं। यह देश के साथ बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी घोषणाएँ आपने कीं, उन पर भी क्या आपने अमल किया है? आपने अमल नहीं किया है। हर चीज में आप राज्यों को दोष देना चाहते हैं। यह कोई नीति नहीं होती है। आखिर अर्थव्यवस्था का संचालन केन्द्र की प्राथमिकता है। केन्द्र ही उसका संचालन करेगा। लेकिन, केन्द्र क्या कर रहा है, इसके केवल दो-तीन उदाहरण मैं देता हूँ। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है।

एक बात चावल एक्सपोर्ट की है। जब अपने यहाँ चावल कमी है और जब देश चावल की कमी से जूझ रहा है, तब आपके वाणिज्य मंत्रालय ने 2 लाख 25 हजार मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया। उस पर एक बार यहाँ चर्चा भी हुई। तब सरकार के द्वारा यह बताया गया कि इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, ये अफ्रीकन देश थे और 20-21 देशों को हमने मदद के रूप में humanitarian aid किया। इस पर लोगों ने पूछा कि कुछ निजी

कम्पनीज़ को उसमें क्यों इनवॉल्व किया, उन्हें क्यों कंट्रैक्ट्स दिये और यह काम सरकार की एजेंसी द्वारा क्यों नहीं किया गया? तब कहा गया कि सरकारी एजेंसीज़ के द्वारा ही उनको नियुक्त किया गया है। जब पूछा गया कि उसमें टेंडर क्यों नहीं किया गया? उसका कुछ जवाब नहीं है। मैं आज केवल यह बताना चाहता हँ कि आपके कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, आपके पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय को क्या कहा था? उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारे यहाँ जो आज चावल के निर्यात की बात हो रही है और जो चावल भेजा जा रहा है, अपने देश में चावल की कमी है। इसलिए चिदम्बरम साहब ने कहा था कि "Rice Budget shows that we barely meet buffer norms of 52 lakh tons at 54.99 lakh tons." यह उनका अभिप्राय था। फिर कृषि मंत्री ने भी लिखा था कि "Our target was procuring 270 lakhs tones but we got only 262 lakh tones and as such Finance Minister's objections are valid." इसके बावजूद भी जब चावल का निर्यात हुआ तब उससे सरकार का घाटा हुआ और चंद कम्पनियों का फायदा हुआ, जिससे देश का सवा दो लाख मीट्रिक टन चावल बाहर गया। सब आपके नियमों और सिद्धांतों को ताक पर रख कर यह व्यवहार होता रहा। दो-दो मंत्री, जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी यह हुआ। आपको खुलासा करना चाहिए कि अगर इस तरह का व्यवहार होगा, तो इसे क्या वित्तीय व्यवस्थापन कहा जाएगा?

स्पेक्ट्रम का मामला तो आपके सामने है। आपको पूरक माँगें रखने की शायद जरूरत ही न पड़ती, वित्तीय घाटा भी कम होता, अगर इसमें पारदर्शिता से काम होता, क्योंकि इससे सरकार की आय बढ़ती, क्योंकि इसमें अपार सम्भावनाएँ थीं। लेकिन, 60 हजार करोड़ का * में जो लोग व्यस्त रहे और जिन्होंने यह स्पेक्टम घोटाला किया**,** इसके कितने पहलू हैं। सभी पहलुओं की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं एक नया पहलू बताना चाहता हूँ। डिफेंस का जो स्पेक्ट्रम रक्षा विभाग के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, होता है -- प्रणब दा, आप डिफेंस मिनिस्टर रहे थे-- वह एक जरूरत थी, लेकिन डिफेंस पर दबाव बना कर डिफेंस का स्पेक्ट्रम रिलीज करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को बाध्य किया गया। जब उसे बाध्य किया

*** Expunged as ordered by the Chair.**

गया, तब जो प्रॉमिसेज़ रक्षा मंत्रालय को दिए गए थे, उसका पालन भी नहीं हुआ है। केवल होड़ है, किसी भी तरह से स्पेक्ट्रम को पाओ और स्पेक्ट्रम को बेचो, कम कीमत में बेचो और बाकी पैसा जेब में डालो। यह सारा काम चल रहा है। इसी के कारण आज स्पेक्ट्रम का घोटाला जो हुआ, उसमें 60 हजार करोड़ का * सरकार को लगा है। यह दूसरे किसी ने नहीं लगाया है, बल्कि आपके यहाँ बैठे हुए लोगों ने ही लगाया है। इसलिए जब तक यह कम नहीं होता, यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है? यह देश को संचालित करने का तरीका नहीं है।

जैसे मैंने चीनी का उदाहरण दिया, वैसे और भी बहुत-सारे उदाहरण हैं। जो गेहूँ दो साल पहले आयात हुआ, उसमें से 8 लाख टन से ज्यादा आयातित गेहूँ नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य के खाने के लिए ठीक नहीं था। (2ई/डी0एस0 पर क्रमश:)

-SSS/NBR-DS/2E/2.15.

श्री प्रकाश जावडेकर (क्रमागत) : तो इस तरह से अगर आप एक-एक चीज़ पर काम करेंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। आखिर वित्तीय-व्यवस्थापन का क्या मापदंड होता है? अगर अच्छा वित्तीय संचालन होता है तो देश की तरक्की बहुत तरीके से होती है, Social Justice मिलता है, inclusive growth होती है, गरीब को न्याय मिलता है, महँगाई कम होती है और नये सुधारों के साथ, नयी ऊर्जा के साथ आप नये अवसरों को प्राप्त करने की होड़ में आ जाते हैं और दुनिया में हमारा सर ऊँचा होता है। वह वित्तीय-व्यवस्थापन होता है, वह तरक्की होती है और उसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है, मेरा यही कहना है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to stand here to support the Appropriation (No. 4) Bill, 2009. This Bill provides for spending of Rs. 30,942,62,00,000 for defraying expenses during 2009-10 for services of as many as 105 departments which have been mentioned in the Schedule. मुझे आश्चर्य होता है कि यह जो रकम सरकार को देश चलाने के लिए 105 डिपार्टमेंट्स को देने के लिए चाहिए, उसका बीजेपी पूरा- पूरा विरोध कर रही है! आखिर इन्हें सरकार कैसे चलाए? क्या सरकार इन्हें बंद करे? इन्हें कोई

*** Expunged as ordered by the Chair**

पैसा न दे? Sir, 105 departments required money and he is saying that this money should not be given! It is not good. Please keep it in mind.

Sir, we have got successful programmes like NREGA. You view it with a different eye. I would not say that you are viewing this with yellow eyes; but, you are viewing it with saffron eyes. You are opposing the entire Scheme. You have just now opposed the loan-weaver scheme. You have totally opposed this.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I only said that all farmers should be given this.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Please say it, time and again, to the people that you are opposing the loan-weaver scheme. Let the country know that you are opposing the loan-weaver scheme. Sir, we may also agree in finding fault with some system. But, you are totally opposing which is bad.

For better utilisation of money, we also have to take certain steps. We have to revisit the work culture in our departments. The attitude of 'come tomorrow', 'come next month' has to be corrected. Hon. Shri Prithviraj Chavan is sitting here. He is in-charge of the Ministry of Personnel. He can do a lot for the purpose of toning the administration. Even today, Members of Parliament take two months to get reply to a letter! It is the minimum. It, sometimes, go beyond that as well. I suggested, sometime back, for doing some experiment. Let us choose 1,000 replies received by Members of Parliament of both the Houses, give them to an independent Committee and find out that in all these 1,000 replies, which are negative in nature, the work could have been done or not. I am sure, in a minimum 50 per cent of the cases, the

Committee will find that the MPs could have been obliged with a positive answer. But, it does not happen. Some experiment in this matter should be carried out.

Sir, your Appropriation Bill will be passed and nobody is going to challenge it in court. As we all know that Members of Parliament have been given some amount under the MPLADS. Unfortunately, this Scheme is in court now. The MPLADS is presently in the court as it was challenged. The arguments are held. We don't know what would be the fate of this Scheme. Therefore, you should see that such a good Scheme should not at all be challenged in any court of law and, if challenged, it should have been admitted and, after admission, it takes so much of time to pass judgment. That means the sword is hanging on our head. We do not know what is going to be the fate of this Scheme. Hence, I would urge upon the Government that in case the judgment is not favourable, we should be prepared to bring an amendment to the Constitution to safeguard our interests under the MPLADS so that people will not suffer.

(CONTD. BY PK "2F")

-NBR/PK/2F/2.20

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): I would like to say this in advance. In spite of various flaws in administration that we come across, we have got a tremendous list of achievements. I will just mention about the NREGA. The NREGA is a revolutionary scheme, appreciated world over, except some local people. The RTI Act, Sir, gives an applicant a status of an MP or an MLA, because the RTI Act says, " An information which cannot be denied to an MP or an MLA

cannot be denied to an applicant under the RTI Act." So, it gives the status of an MP or MLA to every applicant. This is what the UPA Government has done. We have also enacted the Forest Rights Act. Although the policy and the Act taken together is not going that fast as it should have gone, this is going to be another revolutionary legislation which the UPA Government has enacted.

Sir, the Land Acquisition (Amendment) Act which was stalled last time by our opponents should, again, be brought forward. The Land Acqusition Act contains many wonderful provisions. Today, we are acquiring land, giving compensation to those who lose the land and our job is finished. But in that Act, there is a scheme which provides that in future, before acquiring a land, a thorough assessment will be made of the impact. After the impact report comes, only then the land will be acquired. Secondly, if a person has got a house therein, apart from giving compensation, an alternate plot will be given to that person to build a house. Jobs will be reserved for those whose land is acquired. Jobs will be given on a priority basis. These are the provisions which are contained in the Land Acquisition (Amendment) Act and the policy which was stalled by the Opposition, which we should try to have. Now, solar energy is the future energy of our country and the Government has rightly stressed on the solar energy aspect, so that we become self-sufficient, to a great extent in our energy requirements. Now, since there are various other Departments, I will be touching upon only three, four Departments where the money is going. One is the Department of Civil Aviation. In civil aviation, they have announced a number of airports which includes Mopa airport in Goa. But we say that

existing Dabolim airport should be expanded and upgraded. Sir, you were the Defence Minister. You were kind enough to order Navy to give sufficient land to the civil aviation authorities but despite that, Sir, till today, Navy is creating hurdles in granting land to the civil aviation authorities; as a result of which expansion of Dabolim is not taking place and consequently, the development of Mopa airport has also been stalled. Therefore, Sir, if infrastructure has to be improved, then, these airports which have been announced by the Minister of Civil Aviation will have to develop speedily.

Another aspect I would like to mention relating to my State, Sir, is this. We require some special provisions under article 371 of the Constitution. Since Goa is a small State, we do not have land and people from other countries like Israelis, Russians and our own land sharks come with tonnes of money, buy entire villages and we do know where we stand. Therefore, I in my humble way moved a Private Member Bill , which, officially also, the Goa Government is going to place before the Government, in which we have asked for the amendment of article 371 of the Constitution to provide a provision to empower the Legislature of Goa to regulate the ownership and transfer of land in public interest, on grounds of duration of residential requirement in a State, social and economic needs of a State, environment and public interest, as may be specified by the law. Unless such a Constitutional backing is given to the State, we will not be able to enact any legislation to regulate our land.

(Contd. by 2G/PB)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): We enacted one legislation by amending the Registration Act but it was not assented to by the President of India because earlier there was some judgment of the court, and, therefore, Sir, this has been stalled. I would urge upon you, Sir, to consider this proposal.

Then, Sir, I come to giving Goa the special category status. Many States are asking for it and we are also in queue. Though the other States which are in line are not getting it, but, Sir, you know we missed two Five Year Plans. We became independent in 1961. So, Goa missed two Five Year Plans and we are the sufferers. Therefore, Sir, there is just case that small States like Goa, which was under Portuguese Rule for 450 years -- Goa was under Portuguese Rule for 450 years -- should be given due concession, and, for a limited number of years, we should be considered for providing 'Special Category' status apart from granting a package. We are asking for a package and we request the Central Government to kindly give it. Apart from that, we also request that the 'Special Category' status should be given to Goa.

Then, Sir, there is one more aspect. Presently, we are under AGMU cadre, the cadre of certain States and Union Territories. As a result, the officers of All India Services come to Goa. We call them 'briefcase officers' because they just come with a briefcase. They stay in Delhi. In the weekend, they come to Delhi and then go back to Goa. So, they pay no concentration as far as the welfare of Goa is concerned. They are not interested in giving any useful suggestions to local Government to improvise. They don't follow-up a project till the

target is achieved. So, we don't get good services from them. Therefore, Sir, the Goa Government will be coming for asking a separate All India Services cadre for Goa. It is our constitutional right. We can't be clubbed together. We may be small. That is pending. Moreover, Sir, presently under the AGMU Cadre, what is the strength of Goa? It has only 12 officers. So, there is demand to raise it to, at least, 22 officers, apart from pending the consideration of our separate cadre. So, this should be done as early as possible. Otherwise, we will continue to suffer. Goa is having only 12 officers. I think, Sir, some other States, smaller than us, are having better strength in AGMU cadre than Goa. So, this should be considered. Prithviraj is here. I request him to take a note of this because he is the Minister who is directly concerned with that.

Then, Sir, I come to the Ministry of Information and Broadcasting. Despite the policy of the Government of India to have a full-fledged Doordarshan studio in every capital of the country, we had to struggle very, very hard for it. Though ultimately, we had a building which was recently inaugurated, yet we do not have a full-fledged studio. Forget that, Sir. Nobody would believe that we don't have a news bulletin on our Doordarshan till today, a simple news bulletin which any studio will have at any time in spite of the fact that we organize International Film Festival. The International Film Festival is organized there but the Doordarshan studio does not have a news bulletin. Sir, can anyone image that? The worst part of it, Sir, is that when the building was inaugurated by the former Minister, Shri Anand Sharmaji, he promised -- he was kind enough to promise -- that they will start a news bulletin

soon but today I have come to know -- I got a reply in the Rajya Sabha -- that no proposal for starting a news bulletin is under consideration. This reply was given by Prasar Bharti. The Prasar Bharti is an independent body and the Minister only replies. Sir, Prasar Bharti has gone to that extent that it does not listen to anybody. They don't bother about the Minister or the Ministry, and, Sir, I think, it is time the Prasar Bharti is wound up if they don't respond to the public aspirations.

Then, Sir, there is one other thing as far as my State is concerned. I request that an appellate tribunal under Customs Act be established in Goa which should cover Belgaum, Sindhudurg, Karwar, Dharbar, Hubli and Goa. Around 4000 cases are pending in this region. At present, we have got five Benches in Mumbai, Chennai, Delhi, Bangalore and Kolkata. So you can have an appellate tribunal Bench in Goa which can cover all these areas and can be beneficial to all of us.

Then, Sir, this attitude of merging an independent State into another State should be discouraged. Now, I will give an example. The Post and Telegraph Department does not recognise Goa as an independent State under the Constitution of India. They say it is a district. How can a Department of the Government of India treat a full-fledged State as a district?

(Contd. 2g/SCK)

2h/2.30/skc-vnk

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Contd.): We are treated as a district. Our demand is that Goa should be treated as a State and we should have a full-fledged Circle for the Postal Department as also for the Telephone Department.

Then, Sir, if administration is to be taken to the doorsteps of the Government, e-governance is the only alternative. We are talking of e-governance. We have taken a lot of steps; there is no doubt about it. But till today, effective e-governance is not there. Why cannot officers or the Ministers reply to us through e-mail? Why should a reply come only in two months? Let us say, I send an e-mail in seven or eight days' time -- it is not easy, Sir; it is very difficult; and the information is available only on the website; they give information after information -- they can reply to us within eight days instead of two months. Let them deal with the State Governments through e-mail. Today, they take one month to write a letter, one month to post the letter, and you know what happens thereafter. So, communication with the State Governments should be carried out through e-mail, if administration has to be made effective.

Lastly, Sir, our powers must be restored. We are saying that we are helping others, but our powers have been taken away. Restore our own powers. The other day, the Law Minister had made a statement on the appointment of Judges -- appointments of Judges are made as per decision 'so and so' and read with the advisory opinion of the Judges. So, we do not have any powers to enact legislations for appointment of Judges! Is this law to be continued on some judgement and some advisory opinion? Every action of ours, every legislation, everything, including schemes under MPLAD, is being challenged in the Supreme Court of India. Where do we have the powers? Therefore, Sir, let us have a special Session in order to restore our powers.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mohammed Amin; you have ten minutes.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं दस मिनट के अंदर ही समाप्त कर दूंगा। आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

"बयां की सादगी दिल पर असर अंदाज होती है,

मुफ़स्सिर की सदा में वक्त की आवाज होती है।"

इन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल के तहत 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमाण्ड की है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है और यह समझने की जरूरत है कि इस हुकूमत की financial policy क्या है, Taxation की policy क्या है? इस सिलसिले में मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। पिछले साल बजट स्पीच में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का बिग हाउस और कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में concession दिया गया है। यह concession क्यों दिया गया है? यह concession incentive देने के लिए दिया गया है। इसका हिसाब ऐसा बनता है कि 3.23 परसेंट concession बिग हाउस को दिया गया और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसमें एलपीजी गैस, केरोसिन तेल, आदि चीजें आती हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, वह इससे तीन गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब के मुंह से निवाला छीन कर बड़े लोगों के पेट में घुसा देना। फिर आम आदमी की बात तो बेकार बात हुई न। अगर आम आदमी की बात करके पूंजीपतियों की सेवा करने की नीति अपनाई जाए, तो यह कभी भी सेहतमंद नीति नहीं हो सकती है और इससे देश का कल्याण नहीं होगा। लैण्ड रिफॉर्म की बात भी कहीं नहीं सुनी जाती है। एक जमाना था, जब कि कांग्रेस के बड़े नेता बड़े जोरों से प्रचार करते थे कि जब हम लोगों के हाथ में इक्तिदार आएगा, तो तमाम जमीन किसानों में बांट देंगे। अगर इस काम को अंजाम दिया गया होता, तो हिन्दुस्तान में और किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। मजे से राज चलता और कांग्रेस को लोग दोनों हाथों से समर्थन करते, लेकिन वह सिर्फ कागज पर ही लिखा रह गया। अभी हम लोग पूरे हिन्दुस्तान में देखते हैं, तो आज भी अगर कहीं लैण्ड रिफॉर्म का काम जारी है, तो वह पश्चिमी बंगाल में है।

(2j/MP पर जारी)

श्री मोहम्मद अमीन (क्रमागत) : वहां 40 लाख एकड़ ज़मीन तो बांटी जा चुकी है और जो मुकदमों में ज़मीन फंसी हुई है, वह जब मुकदमों से छूटती है, तो वह भी बांट दी जाती है और यह काम आगे बढ़ रहा है। बाकी किसी जगह लैंड रिफॉर्म की कोई बात सुनी नहीं जाती है।

सर, यह बात आज भी सच है कि अगर गरीबों को राहत पहुंचानी है, अगर उनके हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो उनको ज़मीन देनी होगी, ज़मीन का मालिक बनाना होगा, ताकि वे फसल के मालिक बनें। जब उनके हाथ में पैसा जाएगा, तो उनकी कुव्वते-खरीद बढ़ेगी और जब उनकी कुव्वते-खरीद बढ़ेगी, तो कल-कारखाने बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पूरा देश तरक्की करेगा। जब यह नहीं हो रहा है, तो नतीजा क्या हुआ कि जो कल-कारखाने बने हुए हैं, वे भी बंद होते जा रहे हैं और सरकार के हाथ में जो कारखाने हैं, जो मुनाफे पर चल रहे हैं, उनके बारे में इस साल ऐलान ही कर दिया है कि उसका दस परसेंट disinvestment किया जाएगा। यह तो किसी की समझ में नहीं आता कि यह क्या बात हुई और इससे देश किस तरफ जाएगा?

सर, इसके अलावा मैं समझता हूं कि इस साल तो महंगाई की मार से लोगों की सांस उखड़ गई है। देश की आज़ादी के बाद इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई जब आलू 30 रुपए किलो, प्याज़ 35 रुपए किलो, अरहर की दाल 95 रुपए किलो, इस भाव पर पहुंच गई है। लोग कहते हैं कि दाल-रोटी से गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन जब दाल भी महंगी होगी, रोटी भी महंगी होगी तो किस चीज़ पर गुज़ारा होगा? अब सिर्फ पानी पियो और हवा खाओ, इसके अलावा तो और कुछ रह नहीं गया है। इसलिए अगर सरकार समझती है कि हमको राजगद्दी पर बैठा दिया गया है, अब हम जैसे भी चाहें, चलाएं तो यह बात समझनी चाहिए कि पांच साल तक तो यह चल सकता है, उसके बाद नहीं चलेगा। लोग जब नाराज़ हो जाएंगे, तो वे फिर इनको उधर से उठाकर इधर बैठा देंगे और जिस नीति को, जिस पॉलिसी को वे ठीक समझेंगे, करेंगे।

सर, महंगाई के बारे में जब सरकार यह क्लेम करती है कि everything is well under control, prices are under control, तो इस पर हंसी आती है। इसलिए कि

सरकार में जो मंत्री हैं, पता नहीं वे खुद बाज़ार जाते हैं या नहीं जाते हैं, इनको मालूम भी है या नहीं कि दाम कितने बढ़े हैं। अगर इन्हें यह बात मालूम होती, तो कम से कम यह दावा तो नहीं करते कि कीमतें कंट्रोल में हैं। कीमतें एक साल के अंदर दोगुनी हो गई हैं और लोगों की जो आमदनी है, वह भी बढ़ी नहीं है, घट रही है, job loss हो रहा है, रोज़गार छीने जा रहे हैं, disinvestment हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिर कैसे माना जाए कि आम आदमी के बारे में कोई बात ये लोग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं?

सर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यह हालत है, तो सरकार बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी इज़राइल से कर रही है। आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अखबारों के ज़रिए यही मालूम होता है कि इज़राइल से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से पैसा लेकर इज़राइल फिलीस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। फिलीस्तीनियों को गाज़ा पट्टी में धकेल कर उसको एक बहुत बड़े कैदखाने में तब्दील कर दिया है और इतनी मुसीबत भरी उनकी ज़िंदगी बन गई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब दुनिया को यह मालूम होता है कि उसी इज़राइल से हिंदुस्तान हथियारों की खरीदारी कर रहा है, तो इससे हिंदुस्तान की बड़ी बदनामी होती है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, तो बहुत अच्छा होगा।

सर, प्रकाश जी Spectrum की बात कह ही चुके हैं। अभी WTO की मीटिंग हुई, तो WTO की जो agricultural policy है, उससे हिंदुस्तान के किसान तबाह हो रहे हैं। हर साल लाखों लोग गले में रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जान दे देते हैं, मगर सरकार का उधर ध्यान ही नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में इतने लोग आत्महत्या करके नहीं मरते। इसकी वजह क्या है कि किसानों की फसल जब तैयार होती है, तो सरकार भी नहीं खरीदती और कोई खरीदार नहीं मिलता है। फसल का दाम जब गिर जाता है, तो फसल बिकती है। उसके बाद खरीद के जो बिचौलिए हैं, वे मालदार बन जाते हैं। किसान को जब उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती और महाजन का तकाज़ा शुरू हो जाता है, जब इज्ज़त-आबरू नीलाम होने लगती है, तो गले में रस्सी का फंदा डालकर अपनी जान देने के सिवाय उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है। (2K/GS पर क्रमश:)

GS-SK/2K/2.40

श्री मोहम्मद अमीन (क्रमागत) :यह आम आदमी की बात हुई। किसानों को बचाने के साथ-साथ बाजार की महंगाई का सवाल भी जुड़ा हुआ है। एक मंत्री महोदय ने बयान दिया था कि हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बाजार की महंगाई को कम कर दें। आपके पास जादू की छड़ी है, लेकिन आप उस रास्ते पर कदम नहीं रखते हैं। जादू की छड़ी यही है कि जब फसल तैयार हो तो गांव के लोगों की जरूरतों को छोड़कर के किसानों को मुनासिब दाम देकर सरकार उनकी फसल जैसे- चावल, दाल, तेल, गेहूं, शक्कर तमाम चीजों को खरीद ले और पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के जरिए से पूरे देश के लोगों को कंट्रोल रेट पर सप्लाई करे, बाजार की महंगाई उतर जाएगी। चीन ने इसी रास्ते पर चलकर महंगाई को कंट्रोल किया है। यही इसकी गारंटी है कि चीन में महंगाई नहीं बढ़ती है, लोगों की तनख्वाह बढ़ती है। चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उनसे यह सीखें कि उन्होंने यह कैसे किया है। अगर पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन को मजबूत किया जाए, तो करोड़ों की तादाद में दुकानें खुलेंगी और बहुत लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी, किसानों को बचाया जा सकेगा तथा बाजार की महंगाई भी कम हो जाएगी। मगर इसमें एक बात है। ये क्यों नहीं, उस रास्ते पर जा रहे हैं, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और यही वे लोग हैं जो चुनाव के मौके पर मोटी-मोटी रकमें चुनाव के फंड में देते हैं जिससे चुनाव जीतकर ये लोग राज-गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं। बस यही रुकावट है, वरना बाजार की महंगाई कम करने का रास्ता खुला हुआ है। अगर इस रास्ते पर आप चलें, तो देश का भला हो सकता है। सर, मैं दस मिनट से पहले ही खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं एक शेर आपको सुनना चाहता हूं:-

"वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाता है,
बदले दुश्मन तो निशाना भी बदल जाता है,
जिंदगी अपने तजुर्बे से यही समझाती है,
सांस बदले तो तराना भी बदल जाता है।"

(समाप्त)

جناب محمد امین (مغربی بنگال): مہودے، میں دس منٹ کے اندر ہی سماپت کر دونگا۔ آپ کو گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

بیاں کی سادگی دل پر اثر انداز ہوتی ہے
مفسر کی صدا میں وقت کی آواز ہوتی ہے

انہوں نے ایپروپرئیشن بل کے تحت جو 30 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کی فائننشئل پالیسی کیا ہے، ٹیکسیشن کی پالیسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ پچھلے سال بجٹ اسپیچ میں مانّئے منتری جی نے یہ کہا تھا کہ 4-8 لاکھہ کروڑ روپے کا بگ ہاؤس اور کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیکس میں کنسیشن دیا گیا ہے۔ یہ کنسیشن کیوں دیا گیا ہے؟ یہ کنسیشن انسینٹو دینے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس کا حساب ایسا بنتا ہے کہ 3-23 فیصد کنسیشن بگ ہاؤس کو دیا گیا اور جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہوتا ہے، جس میں ایل۔پی۔جی۔ گیس، کیروسن تیل وغیرہ چیزیں آتی ہیں، جس کا استعمال زیادہ تر غریب لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا، وہ اس سے تین گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب کے منھہ سے نوالہ چھین کر بڑے لوگوں کے پیٹ میں گھسا دینا۔ پھر عام آدمی کی بات تو بیکار بات ہوئی نا۔ اگر عام آدمی کی بات کرکے پونجی۔پتیوں کی سیوا کرنے کی نیتی اپنائی جائے، تو یہ کبھی بھی صحت مند نیتی نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے دیش کا کلیان نہیں ہوگا۔ لینڈ ریفارم کی بات بھی کہیں نہیں سنی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، جب کہ کانگریس کے بڑے نیتا بڑے زوروں سے پرچار کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں کے ہاتھہ میں اقتدار آئے گا، تو تمام زمین کسانوں میں بانٹ دیں گے۔ اگر اس کام کو انجام دیا گیا ہوتا، تو ہندوستان میں اور کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزے سے راج چلتا اور کانگریس کو لوگ دونوں ہاتھوں سے سمرتھن کرتے، لیکن وہ صرف کاغذ پر ہی لکھا رہ گیا۔ ابھی ہم لوگ پورے ہندوستان میں دیکھتے ہیں، تو آج بھی اگر کہیں لینڈ ریفارم کا کام جاری ہے، تو وہ پشچھمی بنگال میں ہے۔ وہاں 40 لاکھہ ایکڑ زمین توبانٹی جا چکی ہے اور جو مقدموں میں زمین پھنسی ہوئی ہے، وہ جب مقدموں سے

چھوٹتی ہے، تو وہ بھی بانٹ دی جاتی ہے اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی کسی جگہ لینڈ ریفارم کی کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے۔

سر، یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر غریبوں کو راحت پہنچانی ہے، اگر ان کے ہاتھ میں پیسہ پہنچانا ہے، تو ان کو زمین دینی ہوگی، زمین کا مالک بنانا ہوگا، تاکہ وہ فصل کے مالک بنیں۔ جب ان کے ہاتھ میں پیسہ جائے گا، تو ان کی قوت خرید بڑھے گی اور جب ان کی قوت خرید بڑھے گی، تو کل کارخانے بنیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، پورا دیش ترقی کرے گا۔ جب یہ نہیں ہو رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ جوکل-کارخانے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں اور سرکار کے ہاتھ میں جو کارخانے ہیں، جو منافع پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اس سال اعلان ہی کر دیا ہے کہ اس کا دس فیصد disinvestment کیا جائے گا۔ یہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہوئی اور اس سے دیش کس طرف جائے گا؟

سر، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال تو مہنگائی کی مار سے لوگوں کی سانس اکھڑ گئی ہے۔ دیش کی آزادی کے بعد اتنی مہنگائی آج تک کبھی نہیں ہوئی جب آلو 30 روپے کلو، پیاز 35 روپے کلو، ارہر کی دال 95 روپے کلو، اس بھاؤ پر پہنچ گئ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دال-روٹی سے گزارہ ہو جائے گا، لیکن جب دال بھی مہنگی ہوگی، روٹی بھی مہنگی ہوگی تو کس چیز پر گزارہ ہوگا؟ اب پانی پیو اور ہوا کھاؤ، اس کے علاوہ تو اور کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اس لئے اگر سرکار سمجھتی ہے کہ ہم کوراج گدّی پر بیٹھا دیا گیا ہے، اب ہم جیسے بھی چاہیں، چلائیں تو یہ بات سمجھنی چاہئے کہ پانچ سال تک تو یہ چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چلے گا۔ لوگ جب ناراض ہو جائیں گے، تو وہ پھر ان کو ادھر سے اٹھاکر ادھر بیٹھا دیں گے اور جس نیتی کو، جس پالیسی کو وہ ٹھیک سمجھیں گے، کریں گے۔

سر مہنگائی کے بارے میں جب سرکار یہ claim کرتی ہے کہ everything is well under control, prices are under control, تو اس پر ہنسی آتی ہے۔ اس لئے کہ سرکار میں جو منتری ہیں، پتہ نہیں وہ خود بازار جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے یا نہیں کہ دام کتنے بڑھے ہیں۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی، تو کم سے کو یہ دعوی تو

نہیں کرتے کہ قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ قیمتیں ایک سال کے اندر دوگنی ہو گئی ہیں اور لوگوں کی جو آمدنی ہے، وہ بھی بڑھی نہیں ہے، گھٹ رہی ہے، job loss ہو رہا ہے، روزگار چھینے جا رہے ہیں، disinvestment ہو رہا ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو پھر کیسے مانا جائے کہ عام آدمی کے بارے میں کوئی بات یہ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟

سر، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حالت ہے، تو سرکار بہت بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری اسرائیل سے کر رہی ہے۔ آنکڑے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اخباروں کے ذریعے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل سے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہندوستان ہے اور ہندوستان سے پیسہ لے کر اسرائیل، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں دھکیل کر اس کو ایک بہت بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے اور اتنی مصیبت بھری ان کی زندگی بن گئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اسی اسرائیل سے ہندوستان ہتھیاروں کی خریداری کر رہا ہے، تو اس سے ہندوستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر سرکار اس پر دھیان دے، تو بہت اچھا ہوگا۔

سر، پرکاش جی spectrum کی بات کہہ ہی چکے ہیں۔ ابھی ڈبلیو۔ٹی۔او۔ کی میٹنگ ہوئی، تو ڈبلیو۔ٹی۔او۔ کی جو ایگریکلچر پالیسی ہے، اس سے ہندوستان کے کسان تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ گلے میں رسّی کا پھندا لگا کر اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر سرکار کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنے لوگ آتما۔ہتیہ کرکے نہیں مرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسانوں کی فصل جب تیار ہوتی ہے، تو سرکار بھی نہیں خریدتی اور کوئی خریدار نہیں ملتا ہے۔ فصل کا دام جب گر جاتا ہے، تو فصل بکتی ہے۔ اس کے بعد خرید کے جو بچولیے ہیں، وہ مالدار بن جاتے ہیں۔ کسان کو جب اس کی فصل کی قیمت نہیں ملتی اور مہاجن کا تقاضہ شروع ہو جاتا ہے، جب عزت و آبرو نیلام ہونے لگتی ہے، تو گلے میں رسّی کا پھندا ڈال کر اپنی جان دینے کے سوائے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ یہ عام آدمی کی بات ہوئی۔ کسانوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ بازار کی مہنگائی کا سوال بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک منتری مہودے نے بیان دیا تھا کہ ہم لوگوں

کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بازار کی مہنگائی کو کم کر دیں۔ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، لیکن آپ اس راستے پر قدم نہیں رکھتے ہیں۔ جادو کی چھڑی یہی ہے کہ جب فصل تیار ہو تو گاؤں کے لوگوں کی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے کسانوں کو مناسب دام دے کر سرکار ان کی فصل جیسے چاول، دال، تیل، گیہوں، شکر تمام چیزوں کو خرید لے اور پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم کے ذریعے سے پورے دیش کے لوگوں کو کنٹرول ریٹ پر سپلائی کرے، بازار کی مہنگائی اتر جائے گی۔ چین نے اسی راستے پر چل کر مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے۔ یہی اس کی گارنٹی ہے کہ چین میں مہنگائی نہیں بڑھتی ہے، لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ ان سے یہ سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا ہے۔ اگر پبلک ڈسٹری بیوشن کو مضبوط کیا جائے، تو کروڑوں کی تعداد میں دکانیں کھلیں گی اور بہت لوگوں کو روزی روٹی ملے گی، کسانوں کو بچایا جا سکے گا اور بازار کی مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ مگر اس میں ایک بات ہے۔ یہ کیوں نہیں، اس راستے پر جا رہے ہیں، جو کروڑپتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا اور یہی وہ لوگ ہیں جو چناؤ کے موقع پر موٹی موٹی رقمیں چناؤ کے فنڈ میں دیتے ہیں جس سے چناؤ جیت کر یہ لوگ راج گدّی پر آکر بیٹھ جاتے ہیں، بس یہی رکاوٹ ہے، ورنہ بازار کی مہنگائی کم کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس راستے پر آپ چلیں، تو دیش کا بھلا ہو سکتا ہے، سر، میں دس منٹ سے پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، لیکن میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں:

وقت کےساتھ زمانہ بھی بدل جاتا ہے
بدلے دشمن تو نشانہ بھی بدل جاتا ہے
زندگی اپنے تجربے سے یہی سمجھاتی ہے
سانس بدلے تو ترانہ بھی بدل جاتا ہے

(ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Mr. Amar Singh, you have ten minutes.

SHRI AMAR SINGH (UTTAR PRADESH): I may take one or half a minute more, Sir. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरे लिए बड़े असमंजस की स्थिति है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी सदन में बैठे हैं, यह हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं और मैं इनका हृदय से आदर करता रहा हूं। इनकी गिनती देश के गिने-चुने राजनेताओं में है, जिन्होंने भारतीय राजनीति के सभी रंग देखे हैं। एक वीरभूमि के मध्यवर्गीय परिवार से आकर अगर इन्होंने गरीब किसान के हल की आहट का अहसास किया है, तो कालांतर में कम्प्युटर की key Board की खन-खनाहट को भी वह बखूबी पहचानते हैं। अगर उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में न्युक्लियर डील का समझौता कराकर के कांग्रेस की डूबती नैया को पार कराया है, तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एक ऐसा नेता, जो नेता अच्छा हो, जिसकी नीति अच्छी हो और जिसकी नीयत भी अच्छी हो, नेता, नीति, नीयत तीनों अच्छी हो। फिर भी, इन्फ्लेशन जारी है, फिर भी, महंगाई हो रही है, फिर भी आम आदमी कराह रहा है, फिर भी, न तेल मिल रहा है, न दाल मिल रही है, फिर भी, धान की कीमतें सरकार हजार रुपया तय करती है और किसान आठ सौ रुपये में निजी आढ़तियों को धान बेचता है। जो शराब का धंधा करते थे, बड़े-बड़े होटल चलाते थे, वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, चाहे वह आईटीसी हो, कारगिल हो, अदानी हो, अम्बानी हो, अब वे किसानों का पेट काटने में भी जुट गए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने "नरेगा" की योजना बनाई, जिन जॉन रेज़ ने माननीय सोनिया गांधी जी के साथ बैठकर इस योजना को बनाया, उन जॉन रेज़ का कहना है कि "नरेगा" सफल नहीं हुई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं "नरेगा" के मंत्री विज्ञान भवन में, एक बड़े युवा नेता जिनको सभी प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं, आप सब भी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी उपस्थिति में मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि "नरेगा" में गड़बड़ियां हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं, अपने इधर बैठे साथियों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत आसान है इल्जाम लगा देना, लगभग 14 साल मुझे इस सदन में हो गए हैं, लेकिन मैंने यहां पर भाषण की रौ को बदलते नहीं देखा है। जब ये

उधर बैठते हैं तो उधर जाकर वही कहते हैं, भाषण वही रहता है, भाषण पर कोई राशन नहीं है, लेकिन राशन पर बहुत भाषण हैं।

(2एल पर जारी)

LP/2.45/2L

श्री अमर सिंह (क्रमागत) : वही गरीबी की बात, वही गुरबत की बात, वही भ्रष्टाचार की बात। मुझे याद है, यहां हमारे दोस्त अरुण शौरी जी नहीं बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त प्रमोद महाजन जी अब नहीं रहे, बहुत प्यारे दोस्त थे, हम उनकी कमी महसूस करते हैं, भले ही वे हमारे विरोधी रहे हैं, जब वे DISINVESTMENT MINISTRY से हटाए गए और जब टाटा और बी.एस.एन.एल. का विनिवेश हुआ तो उसमें बी.एस.एन.एल.में ज्यादा पैसा था और उससे कम दाम में बी.एस.एन.एल का विनिवेश हो गया। जब मैंने सवाल उठाया तो और कोई नहीं टाटा ने मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया, मैं बड़ी मुश्किल से मुकदमा लड़कर टाटा से जीता। मैं कहना चाहता हूं - हम यह तो नहीं कह सकते कि टाटा भ्रष्टाचारी हैं, वे देश के बहुत बड़े कार्पोरेट उद्योग के जनक हैं, हम यह नहीं कह सकते कि अरुण शौरी जी ने कोई गड़बड़ी की होगी, भले ही हम उधर बैठते हों, लेकिन अरुण शौरी जी के बारे में कोई कुछ कहे, उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ कहे, यह सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्णय तो गलत हो गया। डॉ. मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, उनके वित्तमंत्रित्व काल में सबसे बड़ा घोटाला हर्षद मेहता का हुआ, लेकिन किसी ने उन पर इल्जाम नहीं लगाया कि इस घोटाले के पीछे वे हैं। मैंने देखा है कि विरोध करने का एक सामान्य तरीका हो गया है कि विरोध करना है। विरोध सामूहिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और व्यावहारिक होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे आडवाणी जी याद आ रहे हैं, मुझे हमारे स्वर्गीय बहुत प्यारे दोस्त माधव राव सिंधिया जी याद आ रहे हैं, जिनके साथ हमने रात-दिन काम किया। डायरी के पन्नों में उनका नाम पकड़ा गया। जस्टिस वर्मा का हथौड़ा बजा। धवन जी, इसी सदन में, नरसिम्हाराव जी के मंत्रालय से तमाम लोगों को इसी समय त्याग-पत्र देना होगा, की बात हुई। यह हो गया कि पूरी राजनीतिक जमात भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी हुई है। मैं किसी कोड़ा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। आज मैंने प्रश्न काल में पूछा, सौभाग्य से प्रणब दा थे, कोड़ा अपराधियों को जरूर पकड़िए, लेकिन मैं

यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यूनियन बैंक ने, जिसके लिए बड़ा कोलाहल मच रहा है, इस पूरे अकाउंट को सही नहीं ठहराया है? मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अखबार की सुर्खियों से निर्धारित होगा या जज के हथौड़े से निर्धारित होगा? यहां पर कुछ लोग Accountability of Judiciary की बात कह रहे थे। लिब्रहान रिपोर्ट अयोध्या के लिए होती है, लेकिन उस पर टिप्पणी राजनेताओं के लिए आती है। जस्टिस वर्मा राजनेताओं के बारे में टिप्पणी कर देते हैं। यह एक फैशन चल गया है। हम सब, चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, बीच में बैठने वाले लोग हों, चाहे आप लोग हों, कम से कम आप यह देखिए की भ्रष्ट से भ्रष्ट राजनेता अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करता है। अगर वह भ्रष्ट है तो उसकी Accountability है। उसकी Accountability इतनी है कि उसको पांच साल में जनता निकालकर बाहर कर देती है, लेकिन अपनी राजनीति के लिए आप जो उसकी Reputation को चोट पहुंचाते हैं, उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। किसी महिला के चरित्र के बारे में और किसी पुरुष के भ्रष्टाचार के बारे में यह टिप्पणी कर देना बहुत आसान है, लेकिन इस पद्धति में हम देश का, समाज का और व्यक्तित्व का कितना नुकसान करते हैं, यह देखने की बात है। अभी Infrastructure की बात हुई। उसमें कहा गया कि हमारा 78,000 मेगावाट का लक्ष्य है और चीन से तुलना की गई। हमारे एक साथी ने कहा कि चीन से हमारे अच्छे संबंध हैं। अक्साई चीन भारत का अंग नहीं है, अरुणाचल भारत का अंग नहीं है, कश्मीर में पाकिस्तान हस्तक्षेप कर सकता है, भाई साहब, अगर चीन से अच्छे संबंधों में यह हाल है, यदि बुरे होते तो अल्लाह जाने क्या होता। आप चीन के विकास की बात करते हैं, तो चीन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन में कोई PIL नहीं हो सकती है। चीन में एक circular होता है कि प्रणब मुखर्जी साहब को यह सत्ता दे दीजिए, लेकिन कोई मेधा पाटेकर नहीं आएगी, कोई PIL नहीं होगा। खुले आम गांव के गांव खाली हो जाएंगे तो 78,000 नहीं, बल्कि 150,000 मेगावाट की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार में सब अच्छा ही हो रहा है। WTO के बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं प्रणब दा से कहना चाहता हूं कि WTO की Green Box Subsidy बड़ी खतरनाक है। जिस तरह की सब्सिडी पश्चिमी देश अपने किसानों को देते हैं, उस तरह की सब्सिडी वित्त मंत्री की हैसियत से आप नहीं दे सकते हैं। वे सब्सिडी आप

नहीं दे सकते तो अगर अमरीका के दबाव में विश्व स्तर पर बाजार खोल दिया जाएगा तो भारत का किसान मर जाएगा। आप WTO की बात जाने दीजिए, आपने ASIAN COUNTRIES के साथ जो करार किया है, सिंगापुर और छोटे-छोटे देश जो भारत के नजदीक हैं, ASIAN COUNTRIES के करार के कारण ये इतने समुन्नत

हैं - यहां हमारे रवि साहब और तमाम केरल के सांसद बैठे हैं, इनसे पूछिए कि केरल के कॉफी और रबड़ के किसानों का क्या हाल है। उन लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। क्योंकि वे आपके दल के माननीय सदस्य हैं, वे आवाज उठा सकते हैं, लेकिन एक स्तर के बाद वे चुप हो जाएंगे।

(AKG/2M पर जारी)

AKG-VKK/2M/2.50

श्री अमर सिंह (क्रमागत) : मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि Global Hunger Index में भारत का स्थान क्या है? यह जो sensex है, यह sensex देश के समुन्नत विकास का मानक नहीं है, यह देश के 15-20 लोगों के विकास का मानक है। देश के विकास का मानक है नरेगा की योजना। यह योजना बिचौलियों की जेब में नहीं जानी चाहिए, आपने बुंदेलखण्ड के लिए योजना बनाई, पूर्वांचल के लिए योजना बनाई, लेकिन अगर आप इसकी monitoring नहीं करेंगे, तो इस योजना का सारा धन, मैं राजीव जी को उद्धृत कर रहा हूँ, उन्होंने मुम्बई के अधिवेशन में कहा था कि सारा का सारा धन, 90 प्रतिशत धन सिस्टम में प्रत्येक लोग खा जाएंगे, जो नीचे से ऊपर तक हैं।

यहाँ पर defence के बारे में भी लोगों ने चर्चा की। Defence की preparedness कैसे होगी? अभी defence के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि लोग राजनीतिक फैसले लेने से डरते हैं। कल अगर मैं रक्षा मंत्री, मैं नहीं कहता कि मैं बनूँगा, अगर मुझे अवसर मिलेगा, तो मैं हाथ जोड़ूँगा, क्योंकि यह निश्चित है कि हमारे मंत्रित्व काल के बाद हमारे ऊपर सीबीआई की जाँच बैठेगी। जो विरोधी दल आएगा, वह बिठाएगा। अगर आप defence preparedness के लिए कुछ भी करिएगा, अगर आप कोई सौदा करिएगा, तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा। अगर आपका मंत्री होगा, तो ये

लगा देंगे और आपका मंत्री होगा, तो ये लगा देंगे। हम बीच वाले भारत की जनता की तरह पिसते रहेंगे।

मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रस्तावित 30,942 करोड़ के अतिरिक्त खर्च में cash outgo 25,725 करोड़ का है, जो 2009-10 के estimated budget से ज्यादा अलग नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे आपकी नियोजन की क्षमता का एहसास होता है। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में 3,458 करोड़ की food subsidy और 3,000 करोड़ की fertilizer subsidy है। यह अतिरिक्त खर्च सीधा आम आदमी और किसान के हित में है। इसके लिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कालाबाजार में चार-पाँच गुना दाम पर खाद बेची जा रही है, यह किसानों को नहीं मिल रही है, fertilizer subsidy का पूरा का पूरा लाभ कालाबाजारियों और बिचौलियों की जेब में चला गया है। प्रणब दा, खाद्य पदार्थ के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अच्छे नेता, अच्छी नीति, अच्छी नीयत होने के बावजूद इसका लाभ नीचे तक percolate क्यों नहीं हो रहा है? अगर food subsidy का फायदा आम जनता को नहीं मिलता है, तो इसका लाभ मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।

Defence pension और छठे वेतन आयोग के बजट पर बढ़े बोझ से हमारे दल को कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। सरकार की विनिवेश नीति पर मुझे सबसे बड़ी परेशानी इस बात पर थी कि विनिवेश से प्राप्त धन National Investment Fund में जाएगा या नहीं, लेकिन National Investment Fund में 3,139 करोड़ के भुगतान से मुझे काफी खुशी है, पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि National Investment Fund में 3,139 करोड़ की यह राशि जो आपने रखी है, इसका इस्तेमाल वादे के मुताबिक सामाजिक विकास के कामों में, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हो, उनमें करिए। वित्त मंत्री जी, मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी संसदीय स्थाई समिति का अध्यक्ष हूँ और इस रूप में मैंने देखा है कि कई बार जो सचिव आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, वे कहते हैं कि आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। हमारे संविधान में यह लिखा है कि यह welfare State है। जिस तरह से right to freedom of speech है, उसी तरह right to education

है, जिसके लिए कपिल सिब्बल जी बिल ला रहे थे। उसी तरह right to get free health facility भी हमारा एक अंग है। अगर इस राशि का उपयोग हेल्थ में भी थोड़ा बजट बढ़ाने में करेंगे, तो अच्छा होगा।

हमारे दोस्त प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ बैठे हुए हैं। वे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। राजनीति में मेरे कम दोस्त हैं, उनमें से एक ये हैं। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, वे इसे व्यक्तिगत नहीं लेंगे। इनसे मैं पहले अग्रिम क्षमा याचना करते हुए कहना चाहता हूँ कि एयर इंडिया को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं जब भी न्यूयार्क जाता हूँ, आपने न्यूयार्क के लिए बहुत अच्छी एयरलाइन लगाई है, लेकिन अभी किसी ने कहा कि 7 हजार करोड़ का घाटा है, किसी ने कहा कि 5 हजार करोड़ का घाटा है, किसी ने बता दिया कि 15 हजार करोड़ का घाटा है। आपका सौभाग्य है कि आप मंत्री हैं। मैं तो हरदम सड़क पर था, सड़क पर हूँ और सड़क पर रहूँगा। इसलिए सुनी-सुनाई बातें करता हूँ। आँकड़े गलत हों, तो मुझे माफ करिएगा। घाटा 5 हजार करोड़ का हो, 7 हजार करोड़ का हो या 15 हजार करोड़ का हो, लेकिन करोड़ों का घाटा है। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि एयर इंडिया को यह 800 करोड़ की दी हुई सहायता, यह अन्तिम है या दी हुई सहायता का आगाज है, अंजाम अभी और है कि देते रहेंगे, देते रहेंगे, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि चिन्ता यह है कि Emirates हमारे भारत सरकार की aviation policy की वजह से अमीर एयरलाइन हो गई।

(2एन/एससीएच पर जारी)

SCH-MKS/2.55/2N

श्री अमर सिंह (क्रमागत): जो हमारे पॉपुलर रूट्स थे और जिन पॉपुलर रूट्स पर हमको बिज़नेस मिलता था, वहां आज Emirates Airlines के कई जहाज चल रहे हैं। हमारे स्वदेश का जो धंधा है, वह Emirates के अमीरों को इतना मिल गया है कि अब दुबई के क्राइसिज़ के सॉल्यूशन के लिए अबु धाबी के शेख यह कह रहे हैं कि यह Emirates को दे दो और फिर से अमीर हो जाओ। इस तरह आपने Emirates को अमीर बनाया। आप जैट एयरवेज़ के नरेश गोयल या विजय मालया को अमीर बना देते, क्योंकि इनकी गुरबत तो

अभी तक कायम है। अगर ऐसा होता, तब भी हमें एक संतोष रहता कि हमारे स्वदेशी तो बने हैं।

मैं कहूंगा कि आप इन मुद्दों पर अपना पूरा ध्यान दें। मैं अपने इधर के सभी साथियों और उधर के सभी साथियों को हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता में आएं तो देश की चिंता करें, भ्रष्टाचार हटाने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता न ढूंढ़ें और भाषण देने के लिए गरीबों की बात न करें। मुझे शैलेन्द्र का एक गीत याद आता है, जो हम सबके लिए बड़ा सामयिक है, जिसमें मैं भी शामिल हूं -

लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया।
बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है।।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Malaisamy. You have five minutes. ...(Interruptions)... Only five minutes. I will take the help of bell to remind you after four minutes!

DR. K. MALAISAMY (TAMIL NADU): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak on the Appropriation Bill seeking the approval of

Supplementary Expenditure of Rs.33,942.62 crores.

We are familiar with the periodical exercise arguing for getting the approval of the Appropriation Bill and all that. But, this time, I have been stuck with one factor, namely, the huge increase in amount asked for approval. I mean, in earlier years, the amount asked for was much less. This time, it has gone up to the extent of Rs.33,942.62 crores! I am inclined to ask the well-informed, senior hon. Minister to check it up

whether a realistic estimate was made and whether correct calculations were done during the time of presentation of the Budget. Once a Budget is presented, only a marginal different can be there between the Supplementary Grants and all that. But this time, I could see a huge difference in the amount. It can be checked up what are the areas on which the contingency was warranted to increase this kind of thing. Secondly, before I could make my observations, I am happy to note from the Economic Survey Report and other things that even the macro-level global melt-down, the recession etcetera did not have that much effect on India. On the other hand, it has only a marginal effect, according to by the Prime Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission. "It will have an effect on India. But it will have only a marginal effect."-- this is what they have said. As it is, it has not done a great damage as it has done in other countries.

Sir, as far as the general economy of the country is concerned, the performance is better. Number two: the inflation is lower than the earlier year. I mean, the GDP growth is already there; the interest rate also is not that much. Then, the liquidity position and the flow of money in the banking system are quite satisfactory. Above all, the industrial growth and recovery gained momentum; the resource mobilisation is very strong; the service sector growth remains at 8.5 per cent. What I am trying to say is, in the midst of these happy financial features and parameters, I am sorry to observe, there are certain adverse factors also. Sir, as the Finance Minister is very well aware, the fiscal deficit has gone up by leaps and bounds. I mean, it could not have any control. Secondly, the agricultural production has fallen by 19 per cent;

the rainfall has, again, fallen by 23 per cent; the trade is not faring well. On the other hand, the export has declined to 28 per cent; the import has also declined. Above all, -- Sir, I repeat the words "above all" --the price-rise index has risen by leaps and bounds from one week to another. I do not want to elaborate it because the Deputy Chairman will be pointing out that I have only five minutes!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Already, four minutes are over!

(Followed by TMV/2O)

-MKS-TMV-PSV/2O/3.00

DR. K. MALAISAMY: But the only factor is that the major income of a family or an individual goes to food and other consumer items only. This is the way the things are now. I can talk for half an hour to explain that. But I stop with this. These are certain major adverse situations in spite of some happy features. This is there. It is the ground reality. In this connection, I would like to appeal to the hon. Minister to see whether he can sustain the recovery of the economy, whether he can afford to sustain whatever is obtained now continuously. What are your measures and initiatives? This is the first point. Secondly, I would like to know whether you can afford to revive the export which has fallen. Thirdly, there are umpteen areas where you can invent and improve upon the domestic market.

Another important thing is that you have given a huge amount of money for so many schemes. The outlay is so big. We are very happy to see the figures and all that. But what is exactly the outcome? This is where I want to talk for a minute. Whatever the schemes that you

have, your leader, late Rajiv Gandhi, said that out of every rupee, only 15 paise or 16 paise reached the beneficiaries. In other words, 84 paise or 85 paise is spent by way of, or, absorbed by, the delivery mechanism, mostly by bureaucrats and other employees or whatever it is. So, out of one rupee 85 paise or 86 paise go by way of administration and bureaucracy and only 15 paise or 16 paise go to the beneficiaries. What exactly is the fault line? To use my management language, whether there is a system failure or human failure or the failure of both. According to me, there is something basically wrong in our implementation system. Your policy is right. Your idea is good. But your action is bad. That is why whatever you want is not implemented. It is the ground reality.

Coming to the people below the poverty line, there are still 38 crores and out of ten pregnant women, nine women suffer from malnutrition or do not get nutrition. Forty-seven per cent of the children are undernourished. These are some of the areas where the economic situation is bad and there are poor people.

Ultimately, I would like to emphasise that you have got your policy, programmes and other things. You kindly have a re-look at them. What is wrong with our policy? If your policy is right, the benefit should reach the beneficiaries. It does not reach them. You think over what could be done. Thank you. (Ends)

SHRI N. K. SINGH (BIHAR): Thank you, Sir. When the hon. Finance Minister happily cut his birthday cake on his 75th birthday, a landmark event, there are more reasons than merely the manufacturing sector index is looking up. He is one of the rare Finance Ministers who will be

presiding over what can be called "a genuinely 'V' shaped recovery" for India because, I think, all indices appear to be that the recovery will be a sustained and a broad-based recovery. So, unlike other Finance Ministers in the world who bothered about an "L" shaped or "W" shaped or "U" shaped recovery, he will be presiding over, perhaps, a "V" shaped recovery and my congratulations to you, first of all, on that.

Being a Member of Parliament has many advantages, but some disadvantages too. One of the disadvantages is that an ordinary person influentially placed could, perhaps, have the privilege of being part of the pre-Budget consultations of the Finance Minister. The next time the House will discuss the economic situation, it will be the Budget time of the Finance Minister and we don't have the opportunity of giving him our pre-budgetary feedback. One of the disadvantages is, therefore, being a Member of this august House. It is in this light that I have six suggestions to make to the Finance Minister. The first and foremost of them, I think, the Budget will, naturally, unravel a major area of tax reforms. My suggestion to you is that the Direct Tax Code, on which you are having wide-ranging consultations, I still feel, is still burdened with a number of infirmities. Please don't be in a hurry to rush with that Bill. Please try to synchronise the Indirect Tax Code and the Direct Tax Code and if you are in a position to have a comprehensive view of the nature of tax reforms which you would like to have...

(Contd. by 2P/VK)

VK/2P/3.05

SHRI N.K. SINGH (CONTD): ...perhaps, you might consider setting up a bipartisan Tax Commission because taxation is not a partisan issue, to

have a holistic look at the taxation, as a whole, before you begin to rush through ill-prepared, half-baked proposals on tax reforms. Pranab*da* you have enough time to leave behind the Pranab legacy on tax reforms. So there need be no unseemly hurry in being able to push ill-prepared tax proposals when you present the next Budget.

Secondly, when you begin to present the next Budget, one of the things which will trouble you is the stimulus package. How should you sequence and exit from the stimulus package? Monetary first, fiscal first, pick up the kind of liquidity, suck out the liquidity in the system, or perhaps, do away with increased public outlays and the tax base which you have given! My suggestion to you is that go slow. You need to have a mid-point between the acquisition of being too fast and too soon or the other extreme of too late and too little. Find a way on the exit policy of your stimulus package in a manner where the incipient signs of recovery do not get hurt.

My third point is that if you look at the Indian economy as a whole, ironically speaking, the agriculture sector still gives only 16 to 18 per cent of your GDP, but livelihood to, perhaps, 58 to 60 per cent of the people. This is obviously an unsustainable situation. Manufacturing sector, as a whole, in this country has yet to take off and the growth impulse has largely come in the service sector. This is an unsustainable situation. What we like you to consider is how the manufacturing sector can get a genuine boost so that the downstream effects of employment growth in this country can leave behind a significant impact. If there is one lesson, which we can learn from China, is how to foster middle, low level skills which can give large employment creation, find gainful

activity outside agriculture, create virtual circles around manufacturing hubs so that the services and the manufacturing sector growth can grow in tandem. This is something, Mr. Finance Minister, you may like to give some further thought to beyond the recommendations made and some very important recommendations made by the Committee on Competitiveness of the Manufacturing Sector.

My fourth suggestion to you, Sir, is on agriculture. Your colleague, I am sure, will impress upon you that the present spurt in prices is not a short-term phenomenon. This is because there are global factors, there are indigenous factors. So what can you do to improve short-term supply elasticity, improving the shelf life of products, giving a deep chain and cold supply chain, improving rural connectivity, fostering an incentive structure which enables short-term responses to what may be a long-term endemic phenomenon?

My fifth point to you is, the Winter Session of Parliament is about to come to an end. Everybody knows that the Budget Session is primarily a Finance Bill Session and the Winter Session is primarily a Legislative Business Session. Fortunately, you might like to give some thought to a point made by Shri Prakash Javadekar that long pending legislations on important financial matters still remain mired either in the Standing Committees or in some form lie in limbo. The advantage of having a Winter Session for a Legislative Business has been lost by the Government. You will, perhaps, have to consider how in your Budget Session, the Legislative Business of the Government can be blended along with your financial business.

My last point is that at a time when you present our next Budget, please take advantage of three important things. Take advantage of the Mid-Term Review of the Eleventh Plan on the contours of the draft outline of the Twelfth Plan, those making important suggestions. Secondly, take note of the recommendations likely to come before you from the next Finance Commission, whose term of office has been extended by three months. And also take note of some interim recommendations of the Commission on Centre-State Relations. Mr. Finance Minister, fortunately, for you the confluence, the conjuncture and the configuration, seem right**,** do not prevaricate from taking those decisive steps which will decisively, indeed, make our economic recovery process a recovery process which is long-term, V-shaped process with long-term economic growth, inclusive growth, low inflation and high employment. Thank you.

(Ends)

(Followed by 2Q)

AKA/RG/2q/3:10

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं आपके घंटी बजाने से पहले ही बैठ गया था और एक प्वाइंट भूल गया था। सर, मैं बोलना भूल गया था इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए 'ईगॉन' के चेयरमैन के रूप में दादा ने NTPC को प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, वह अभी भी चल रहा है विवाद में, न्यायालय में, शायद सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय ने NTPC के विरुद्ध, मैं 'कोपू' का निर्वाचित सदस्य हूं, इस बात की मुझे चिंता है कि NTPC के विरुद्ध एक affidavit दे दिया है। यह असत्य भी हो सकता है, अखबार की बात हर बार सच नहीं होती। अगर यह सत्य है तो मैं दादा का प्रोटेक्शन आपके माध्यम से चाहूंगा।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Janardhan Waghmare. Not present. Shrimati Vasanthi Stanley.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (TAMIL NADU): Sir, thank you for giving me this opportunity to record my views on the Appropriation Bill (No.4) of 2009-10, for a total amount of Rs.30,942.62 crores, with the details of Supplementary Demands allocated to each Ministry over and above what has already been budgeted and approved by Parliament under the Union Budget in July. An overall view of the Supplementary Bill shows that the huge appropriations are made to the following Departments/heads. They are Pensions (Revenue), which amounts to Rs.4,533 crores, that is, 14.7 per cent of the total Appropriation; Department of Fertilisers, amounting to Rs.3,000 crores, that is 9.7 per cent; Department of Food and Public Distribution, Rs.3,660 crores, to the extent of 11.8 per cent; Defence Pensions, Rs.2,210 crores, to the extent of 7.1 per cent; Financial Services, Rs.1,266 crores, that is, 4 per cent; Department of Disinvestment, -- it carries a lot -- Rs.3,139 crores, that is, 10.1 per cent; Department of Urban Development, Rs.2,225 crores, that is, 6.5 per cent; and Others, amounting to Rs.11,109 crores, that is, 36 per cent. As we see it, the biggest demand is being made for Pensions and Disinvestment. Even when the whole world was trailing behind due to financial crisis, India was able to show a healthy 7.1 per cent GDP growth last year. But, this year, India is also slowly under the clutches of economic slowdown and financial crisis.

When I had the opportunity to register my observations over the Union Budget, I had said, "The Government seems to be counting on assumptions just to keep the fiscal deficit at 6.8 per cent of the GDP.

The deficit is expected to be bridged by collection of increased direct taxes and so on. Without mentioning any specific target for public sector disinvestment, the Finance Minister has estimated to mop up Rs.1,120 crores during the fiscal year. I had also shared my concern that if any of the assumptions does not work out, the fiscal situation will get more precarious." But this is what exactly happened, Sir. Yesterday, the hon. Finance Minister stated in this House that there is a deep decline in indirect tax components and this is expected to be compensated with higher collection of the direct tax components in 2009-10. We, still, have lot of hopes on you, Sir, as a senior, experienced Minister, that you will come out with more plans and will take strict measures to collect the direct taxes, as well as, the left out indirect taxes, and, thereby bridge the gap more effectively and substantially.

I just have got two points more concerning my State, Tamil Nadu. The crop insurance due to the farmers is always shared in the ratio of 50-50 between the States and the Central Government. Due to the recent floods in Tamil Nadu, all the agricultural crops have been ruined. The Government of Tamil Nadu, immediately, compensated this by releasing their share of Rs.300 crores. We have to run from pillar-to-post, from the Finance Department to the Agriculture Ministry and the Agriculture Insurance Company, but the Central Government is yet to give its share of Rs.300 crores. I also observe that only Rs.250 crores have been totally allotted for crop insurance. Leave alone Tamil Nadu, Sir, I request the Finance Minister to allocate more funds under this head and release the Central Government's share of Rs.300 crores

towards crop insurance due for Tamil Nadu, and wipe away the tears of the farmers of Tamil Nadu.

My next concern is about compensation for VAT.

(Continued by 2R)

2r/3.15/ks/NB

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (contd.): I reiterated this when I spoke on the Finance Bill. I again request you to recall, when VAT was introduced and the Government of India was insisting upon the State Governments to introduce it, the previous AIADMK Government was not willing to put itself to this acid test. Then, it was announced by the Central Government that the loss of revenue would be compensated. Hence, under the able leadership of our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. K. Karunanidhi, we had opted to introduce VAT by 2007. We should have been compensated to the extent of 100 per cent for the first year and to the extent of 75 per cent for the second year. We were compensated only to the extent of 75 per cent and 50 per cent respectively. The State Government had prepared the original Statement of Accounts to substantiate their loss of revenue, for compensation. The Central Government has not only not compensated fully but also tends to cross-check the accounts by way of A.G. audit which leads to inordinate delays. The same is the case so far as reduction of the C.S.T. from 4 per cent to 2 per cent is concerned.

Sir, Tamil Nadu is a manufacturing State and we also export to other States. We have incurred a loss in this regard. I request that pending compensation, which is more than Rs.1000 crores, should be released immediately to reinstate our faith and confidence in the Central

Government. Our Chief Minister has taken up a lot of welfare measures. Sir, there is a sonnet by John Milton, 'On His Blindness' in which he says, 'Doth God exact day labour, light denied'. When he is blind, he is asking the God how He is expecting him to do all the work when he has denied him the daylight, that is, the eyesight. In the same way, I would like to ask the Central Government, if funds are not coming, then, how can we carry out our welfare measures. So, I request our Finance Minister to release all that is due not only to Tamil Nadu but to all other States. Sir, we are all very small and the Central Government is very big. I hope the Finance Minister will do the needful. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ का जो प्रस्ताव माननीय प्रणब मुखर्जी जी लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं प्रणब बाबू को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो global recession था, उसमें से सबसे पहले उबरकर आने वालों में भारत शामिल है। आज भारत ऐसा पहला देश है, जो इस मुसीबत से काफी हद तक निकल गया है। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर खत्म होने के कगार पर है, तब दुबई जैसे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसी खबरें मिल रही हैं, जिनसे पूरा विश्व चौंक गया है। दुबई जैसा छोटा देश, जहां इतनी कंपनियां हैं, इतना पैसा है, इतनी तरक्की है, इसके बावजूद वह अपने आपको संभाल नहीं पाया, वहीं भारत जैसे विशाल देश के लिए जहां इतनी जनसंख्या है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके बावजूद इस स्थिति से निकालकर ले आना अपने आप में निश्चित रूप से सराहनीय बात है और हम सबको 7 प्रतिशत ग्रोथ की आशा भी बंधी है और 7 प्रतिशत ग्रोथ पर इस समय सरकार काम कर रही है, यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

उपसभापति जी, प्रणब बाबू जो प्रस्ताव लाए हैं, उसमें अगर एक-दो चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारे मित्र अमर सिंह जी ने एयर इंडिया की बात उठाई थी, एयर

इंडिया और कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इन दोनों के घाटे की बात छोड़ दी जाए, तो मोटे तौर पर जो पैसा है, वह जिन कामों के लिए आ रहा है, मेरे ख्याल से वे महत्वपूर्ण और उपयोगी काम हैं। उदाहरण के लिए जैसे नाभिकीय ऊर्जा, यूरेनियम खरीदने के लिए पैसा लिया जा रहा है, यूरेनियम के जरिए बिजली बनानी है, उस तरह के जो हमारे कारखाने हैं, उनके लिए पैसा लिया जा रहा है, धन आवंटित किया जा रहा है, फूड सब्सिडी के लिए दिया जा रहा है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए लिया जा रहा है, कर्ज़ माफी के लिए जो पैसा देना है, उसके लिए इसमें से धन लिया जा रहा है, सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो पेंशन दी जानी है, उसके लिए धन दिया जा रहा है, कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए धन दिया जा रहा है, मेट्रो रेलवे के निर्माण के लिए धन दिया जा रहा है और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स पर धन दिया जा रहा है। ये सारे काम ऐसे हैं, जो इस देश की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं।

2S/VNK पर क्रमश:

-NB/VNK-TDB/2s/3.20

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : इन मदों के खर्च के लिए अगर यह धन की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सबको इन मांगों का समर्थन करना चाहिए। एक बात महंगाई की आई। इसको प्रकाश जावडेकर जी ने उठाया और इस पर सारे लोग बोल गए। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है और महंगाई से सब चिंतित हैं। कांग्रेस अध्यक्षा बहुत चिंतित हैं, वह बराबर सरकार को बोलती रहती हैं कि इसके लिए प्रयास करने चाहिए। सरकार प्रयास भी कर रही है। यह महंगाई ज्यादा food items पर केन्द्रित है। यह essential commodities, जैसे खाने-पीने की चीजें, सब्जियां, आदि पर ज्यादा महंगाई है। इसकी वजह यह है कि खाद्य पदार्थों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। यह कमी या तो आयात के जरिए पूरी हो सकती है या हमें अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार को जितना करना है, वह अपने ढंग से कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी लेनी पड़ेगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को भी इसमें सक्रिय करना पड़ेगा कि जो जमाखोरी वगैरह है, वह उसको भी

रोकने की कोशिश करे। सब्जियों के दाम के लिए प्रधान मंत्री नहीं जिम्मेदार हो सकता है। सब्जियों के दाम के लिए कुछ जिम्मेदारी कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर को और मुख्य मंत्रियों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल स्तर की जितनी चीजें हैं, उन्हें इसको देखना पड़ेगा। पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम कर सकती है कि अगर किसी चीज की कमी है, तो उसको इम्पोर्ट करे। इम्पोर्ट की व्यवस्था को देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम हो सकता है, लेकिन अगर नीचे लेवल पर जमाखोरी हो रही है, तो उधर भी उन लोगों को आगाह करना पड़ेगा, उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो, उससे फ़र्क़ नहीं पड़ता है। एक ऐसा पक्ष जिसमें मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार थोड़ी कमजोर पड़ रही है, वह यह है कि राज्यों पर भी इसकी कुछ जिम्मेदारी डालनी चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं डाल पा रहे हैं।

श्री एन. के. सिंह ने Direct tax और Indirect tax के बारे में बात उठाई है। यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी इस पर लगातार लोगों से सलाह ले रहे हैं। लोगों के recommendations मंगा रहे हैं और Consultative Committee में भी यह काम चल रहा है। लोगों की और सब सांसदों की भी सलाह ली जा रही है। जीएसटी पर काफी अच्छे सुझाव भी आए हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड में काफी अच्छे सुझाव आए हैं। मैं श्री एन. के. सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि इस पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्णय होंगे, ये बहुत लंबे वक्त तक चलने वाले होंगे। अगर कोई ऐसी नीति बनती है, जो कम से कम दस-बीस साल तक काम आए, उस दिशा में हमें ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो। टैक्स सिस्टम में जो जटिलताएं हैं, वे कम हों। टैक्स का जो बेस है, वह बढ़ना चाहिए, नेट बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों पर फोकस होकर उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते जाएं, उन्हें बढ़ाते जाएं, यह ठीक नहीं है, बजाए इसके कि हम नेट में विस्तार करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं किसी खास प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वकीलों का है, जो जिला स्तर पर वकील हैं, वे बुरे हाल में हैं। जो तहसील स्तर पर वकील हैं, वे बुरे हाल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की अंधाधुंध कमाई है, लेकिन individuals के नाम पर सर्विस टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वह कंपनी पर लगता है।

कोई वकील कंपनी बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं, जैसे सालिसीटर फर्म और लॉ फर्म, आदि बनाते हैं। हमारे रवि शंकर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने कंपनी बनाई या नहीं बनाई। वह बुरा मान रहे होंगे। वह मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं, लेकिन यहां तो देश हित में बात करनी है ..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, यह व्यक्तिगत मामला सदन में नहीं उठना चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री अमर सिंह : महोदय, यह साले बहनोई का रिस्ता है ..(व्यवधान).. दोनों ने मिल कर बांट लिया है..(व्यवधान).. इनके दोनों हाथ में लड्डू है ..(व्यवधान).. एक इधर है और एक उधर है..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : प्रणब बाबू से मैं मांग करता हूँ कि रवि शंकर जैसे व्यक्ति पर, भले ही वे रिश्तेदार हों, सर्विस टैक्स लगनी चाहिए..(व्यवधान)..

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, they are not paying service tax because they are not rendering any service. ...(Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल : ऐसे लोगों पर तो सर्विस टैक्स लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी उसमें आते हैं, तो मैं क्या करुं। देश हित की बात करनी चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : पत्रकार पर भी सर्विस टैक्स लगनी चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : पत्रकार तो देते ही हैं ..(व्यवधान)..। उसके लिए तो हम तैयार हैं। इस समय जो स्थिति है, जो इन्होंने ब्योरा दिया है, उसमें indirect tax में 7.5 परसेंट का decline है। मेरा यह मानना है कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट टैक्स पर जोर देकर, वहां पर शक्ति करके, वहां से वसूल कर इस कमी को पूरा किया जाए। यह ठीक नहीं है। Indirect tax को कैसे बढ़ाया जाए, इसके उपाय खोजने चाहिए। मैं यह एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ।

महोदय, लिक्विडिटी को लेकर आज बात हो रही है कि जिस तरह से पांच से छः परसेंट महंगाई दर बढ़ने की बात है, तो शायद रिज़र्व बैंक, मार्केट से लिक्विडिटी को withdraw करे। मुझे नहीं लगता है कि यह करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। आप जिस तरह से recession को खत्म करने में कामयाब हुए हैं,

उसकी एक वजह यह है कि आपने लिक्विडिटी को मार्केट में डाला और उसके असर देखने को मिले।

(2t/MP पर जारी)

MP/2T/3.25

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : अगर उस liquidity को फिर वापस खींचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वह purpose पूरा हो पाएगा, फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए।

सर, केंद्रीय योजनाओं की monitoring एक बहुत important चीज़ है। भारत सरकार विकास योजनाओं के लिए इतना पैसा देती है कि अगर वह सचमुच उपयोग हो, तो गांव सोने के हो जाएं ! आज ये देहात न रहें, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह हमारे गांव हो जाएं, लेकिन समस्या यह है कि वह पैसा वहां लग नहीं पाता है। तो इसलिए साठ साल बाद, अब केंद्र सरकार को कोई न कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और प्रणब बाबू जैसा वित्त मंत्री ही वह बना सकता है कि केंद्र सरकार का पैसा, उसकी direct monitoring Government of India करे, उनकी एजेंसियां करें। अगर सी.बी.आई. लगानी है, तो इन पर लगाओ। ये पांच-पांच सौ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ते घूम रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। भारत सरकार का हज़ारों करोड़ रुपया, जो निचले लैवल पर सफाचट होता है और आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता, गांवों तक पहुंच नहीं पाता, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, ये एजेंसियां वहां काम करें, वहां direct monitoring हो, बजाय इसके कि कुछ individuals को पकड़ते घूमें। अगर हमने वैसा कर लिया, तो हमें उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई Monitoring Department होना चाहिए, जो Government of India के एक-एक पैसे की monitoring करे कि वह सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। आप अपने काम की इतिश्री इससे नहीं समझ लीजिए कि आपने पैसा भेज दिया और राज्य सरकारें चाहे जैसे उसे खर्च करें, चाहे वे उसकी तनख्वाहें बांट दें,

चाहे इधर का पैसा उधर कर दें। किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, Central Government के पैसे की monitoring direct Central Government के हाथ में होनी चाहिए, यह सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए

सर, अब मैं employment के बारे में कहना चाहूंगा कि employment एक बड़ी जबरदस्त समस्या होने जा रहा है, क्योंकि रोज़गार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं। मैं एन.के.सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि manufacturing sector पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चीन ने manufacturing sector के सहारे ही grow किया है। हमारे यहां सर्विस सेक्टर बढ़ता चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन manufacturing sector के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा पैकेज बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ राहत उन्हें ऐसी देनी पड़ेगी कि जब तक इस देश में उद्योग-धंधे नहीं लगेंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी और उन्हें बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए।

सर, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि recession का आखिरी दौर है, नाव बिल्कुल किनारे पहुंच गई है और अब नाव को देखना है कि कहीं डूबने न पाए, इसलिए सरकार को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। अगर एकाध कोई stimulus package की जरूरत पड़े, stimulus package not in terms of money, तो मैं कहता हूं कि अगर पॉलिसी लैवल पर रिलीफ देकर कुछ हो सकता है, तो देना चाहिए, ताकि पूरी तरह हमारा बेड़ा पार हो सके और हम किनारे पहुंच सकें, यही वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा था कि देश के एक senior politician देश के वित्त मंत्री बने हैं, देश के 5th Schedule Area में जो Tribal Area Sub-Plan है, उसके लिए वित्त मंत्री महोदय एक स्पेशल पैकेज या स्पेशल प्लानिंग बनाएंगे, आज के हिंदुस्तान में सबसे दयनीय अवस्था में जो गरीब तबके के शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ रहते हैं, उनके बारे में कोई नई योजना बनाएंगे, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आज़ादी के 62 साल बाद भी जितने Tribal Area Sub-Plan

हिंदुस्तान में हैं, उनमें जो आम जनता रहती है, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़, ओ.बी.सी. और other population, जो लोग भी रहते हैं, वे आज भी economically, educationally, socially, देश की आज़ादी से पहले जैसे थे, आज भी उसी तरीके से रह रहे हैं। आप जब तक उन tribal pockets में जाकर नहीं देखेंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। जैसा आपके आंकड़े बताते हैं, शेड्यूल्ड एरिया को छोड़िए, रूरल इंडिया में झारखंड में 54.2 परसेंट एस.टी. below poverty line हैं ।

(2u/GS पर क्रमश:)

GS-KLS/3.30/2U

श्री मंगल किसन (क्रमागत) : एस0सी0 57.9 परसेंट below poverty line में हैं, ओ0बी0सी0 42.2 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स रूरल एरिया में 37.1 परसेंट below poverty line में रह रहे हैं। उसी हिसाब से अर्बन इंडिया में एस0टी0 41.1 परसेंट below poverty line में हैं, एस0सी0 47.2 परसेंट below poverty line में हैं, ओ0बी0सी0 19.1 परसेंट below poverty line में हैं और जो अदर्स हैं, उनका थोड़ा डेवलेपमेंट हुआ है, 9.2 परसेंट below poverty line हैं।

उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में एस0टी0 75.6 परसेंट below poverty line में हैं, एस0सी0 50.2 परसेंट below poverty line हैं और ओ0बी0सी0 36.9 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स 23.4 परसेंट below poverty line उड़ीसा के रूरल पॉकेट में हैं। उड़ीसा के अर्बन एरिया में एस0टी0 61.8 परसेंट below poverty line हैं, एस0सी0 72.6 परसेंट below poverty line हैं, ओ0बी0सी0 50.2 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स 28.9 परसेंट below poverty line हैं और ऑल इंडिया below poverty line is ..(समय की घंटी)..

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) : हो गया।

श्री मंगल किसन : सर, हम कभी नहीं बोलते हैं। आप दो मिनट का समय और दे दीजिए। ऑल इंडिया एवरेज 27.5 परसेंट below poverty line है। हम लोगों का जो भी सब-प्लान एरिया है, कमोबेश उनकी हालत इसी प्रकार से है। जब हम आजादी के 62 साल के

बाद भी, वहां के लोग जैसे पहले रहते थे, आज भी हम वहां के लोगों को उसी हिसाब से रखेंगे, तो यह देश के लिए और समाज के लिए सबसे दुख की बात है। इसीलिए मैं सब-प्लान एरिया के लिए हाथ जोड़कर माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे नार्थ-ईस्ट के लिए पैकेज बनाया गया है, कम से कम उसी तरह का पैकेज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बाकी बिहार और अन्य राज्यों में जो पाट्र्स एरिया है, उनके लिए स्पेशल प्लानिंग एवं प्रोग्राम बनाने की कृपा करें। ..(समय की घंटी)..

सर, हम आदिवासी लोग जो भाई-बहन हैं, हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है। जैसे फ्लड आने पर, हाउस डैमेज होने पर आप इंदिरा आवास लोगों को देते हैं, कम से कम कुछ नहीं होने से देश में यह जो ट्रायबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको इकट्ठा देने से, जम्बलिंग करके देने से, वे लोग अपने राइट को अवेल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े राज्यों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए इंदिरा आवास देने के लिए स्पेशल प्रॉविजन करने की व्यवस्था की जाए। मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

(2W पर आगे)

SSS/2W/3.35

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Trivedi. Please take only three minutes.

SHRI Y. P. TRIVEDI (MAHARASHTRA): Sir, I am replacing Mr. Waghmare who is not here. But I will take very little time.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Waghmare always sticks to time. He is reputed for that.

SHRI Y. P. TRIVEDI: He has stuck to the time by not remaining present. Sir, first of all, I would like to join the chorus of praise which is bestowed on the Finance Minister. He is such a mature man, such a dignified man with so much resoluteness. It was said about Disraeli that

when he used to move out, people used to look at his composure, people used to look at the confidence on his face and they used to feel that there is total political stability in the country. In the same way, the moment people see the confidence of our Finance Minister; it is so contagious that to a certain extent the economic recovery is due to the composure and the way in which he has behaved himself. I confine myself only to two items because the time at my disposal is very short. The first is the Direct Tax Code which was initially the 1922 Income Tax Act. It lasted for about 40 years and in 1961 the new Income Tax Act was heralded as a measure for simplifying and rationalising the tax structure. It ultimately turned out to be the most complicated piece of legislation. There were explanations which were mounting on provisos, provisos which were mounting on explanations and there was not a single section which could stand by itself. It was always over-lapping another section and very often so many sections used to say, 'not withstanding anything contained in any other part of the Act'. So we would not know which one will stand and which one would go. So, that was a sort of a cobweb. From that we had to come out. So, we have the Direct Tax Code. A lot of confidence is reposed by people, the tax payers, the tax gatherers, the tax advisers. All are looking at the Direct Tax Code and it has to be brought in the Statute Book as early as possible but there are so many infirmities in the Act. One of them is the Minimum Alternative Tax. The Minimum Alternative Tax was conceived as a tax when so many companies used to earn money, earn profits, used to pay dividend but were not paying tax. So, there was a Minimum Alternative Tax. Now, that tax has been brought out in the

Direct Tax Code as a measure that even if the company is making a loss, still it has to pay the tax because now it has to be joined on the gross value of the asset, not on the profitability. This is ununderstandable. The tax on the gross value of assets actually means the wealth tax. It is not an income tax. In spite of the fact that there may not be any income still the tax has to be levied. I think, it is very high time that this code which is coming should be given to the Select Committee. The Select Committee should move to the various centres to find out the voice of the trade associations, the professional bodies and should come out with concrete suggestions and the tax code should come as early as possible. It should not be delayed because the present Act is unworkable. The second point which I would like to urge upon is the plight of Mumbai. Mumbai, as it is said, contributes almost one-third of the Direct and Indirect Taxes of the country. But, still Mumbai has been denied. When I come to Delhi and when I look at the contrast between Mumbai and Delhi, I am pained because Mumbai has no infrastructure. Even sometimes commuting to a distance of about one kilometre or two kilometres it takes half an hour or one hour. The infrastructure is totally ruined. There is no metro. Commutation is so difficult. Housing has gone to a level which is ununderstandable. As I said, in one of the occasions, a square foot of area can fetch as much as Rs. one lakh. That is the plight of housing in Mumbai. I think something should be done. A large part was promised to be given to Mumbai for the purpose of development but it has not come. I think Mumbai is lagging behind. I am afraid Mumbai will become a dying city and as early as possible funds should be earmarked for Delhi, for

Mumbai and some scheme should be evolved to see how these funds are to be utilised in Mumbai.

(Ends)

(Followed by NBR/2X)

AKG/2X/3.40

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर) : सर, सबसे पहले तो मैं जनाब वजीरे ख़ज़ाना को अपनी जमात की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकवाद पेश करता हूँ कि इन्होंने निहायत ही मुश्किल हालात में मुल्क की मइशियत को इस्तेहकाम दिया और जो सारी दुनिया में एक तरह का बोहरान था, अपने मुल्क को उस बोहरान से बचाया। Supplementary Financial Bill, जो इस वक्त एवान के सामने है और जिस पर बहस हो रही है, यह दरअसल जो बजट पास हुआ है, उसमें जो मुख़्तलिफ महकमाजात थे, इखराजात में इजाफा होना, उस इजाफे को पूरा करने के लिए इन्होंने यह बिल लाया है। बजट इजलास के दौरान भी मैंने अपनी रियासत के हवाले से कई मामलात इनकी नोटिस में लाया था। आज भी दो-तीन मामलात, जो निहायत ही अहम हैं, अमन और सलामती के लिहाज से भी और रियासत जम्मू-कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिहाज से भी, मैं इनकी नोटिस में लाना चाहता हूँ।

गुज़िश्ता 15 साल से एक बड़ा मामला मरकज़ी हुकूमत के सामने रहा। वह है रजौरी-पुंछ-बारामूला-कुपवाड़ा और दूसरे सरहदी इलाकों में रहने वाले पहाड़ी लोगों का मामला। उनका यह मुतालबा रहा है और वक्तन फोक्तन जितनी भी हुकूमतें गुजिश्ता 15 वर्ष में बरसरे इक्तिदार यहाँ पर रहीं, उन्होंने एवान में भी और एवान से बाहर भी इस मामले पर हमदर्दाना गौर का वादा किया। मसला है पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले लोगों को दर्द-ए-फरिश्त कबायल के जुमरे में शामिल करना, उनको ST status देना। कई बार इस ऐलान में भी इस मसले पर मुबाहिसे होते रहे। इससे पहले भी जो वजीरे आजम आए हैं, उन्होंने भी इस बारे में हमदर्दाना गौर का यकीन दिलाया और अब भी वजीरे आजम ने इस मसले पर कुछ फैसला करने का यकीन दिलाया। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस ऐवान में यह बात बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ी लोग हमारे सरहद और Line of Actual Control

के आसपास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। अगर एक ही गाँव के एक हिस्से और एक ही तरह के समाजी और इक्तिसादी हालात में रहने वाले लोगों के हिस्से को आप Scheduled Tribe करार दें और समाज के उस दूसरे हिस्से को महरूम रखें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महरूमी का क्या आलम हो सकता है। इसलिए बेचैनी बढ़ रही है, बेचैनी मौजूद है। इसके निहायत ही मनफी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। यह सारा पहाड़ी इलाका है और निहायत ही हस्सास इलाका है अमन, सलामती और दिफा के लिहाज से। मेरी यह गुजारिश होगी कि आप इस मामले पर फैसला करवा दें, ताकि आबादी के एक बड़े हिस्से को जो उनका एक मुतालबा रहा है, उस मुतालबे को पूरा करवा कर इस बेचैनी को दूर करें।

दूसरा एक बड़ा मामला है। 1996 से लेकर 2002 तक मैं खुद अपनी रियासत का वजीरे तालीम भी रहा। उस वक्त एक प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था पॉलिटेक्निक को जदीद बनाने का, वुसअत देने का और उनके मयार को ऊँचा करने का। (समय की घंटी) सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए, सरहदी रियासत के मामलात हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : पाँच मिनट हो गए, मैं क्या करूँ। मैंने तीन मिनट कहा था, आपने पाँच मिनट लिया।

श्री मोहम्मद शफ़ी : सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, मेरी आपसे गुज़ारिश है। (2वाई/एससीएच पर जारी)

-NBR/PK-SCH/2Y/3.45

श्री मोहम्मद शफ़ी (क्रमागत): तब तो वर्ल्ड बैंक ने रुकुमात मंजूर किए और हमने उस प्रोजैक्ट पर अमलावरी भी की। अब भी वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और वह है Ministry of Environment and Forest का Watershed Development Programme. उसके लिए जो तमाम लवाज़मात जरूरी थे, वे मंजूर हो गए हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक से उसके लिए रूकुमात आने हैं, वह अभी तक नहीं आए हैं। इसमें यह बात कही जा रही है कि शायद इस रियासत के स्टेटस पर एक सवालिया निशान फिर दोबारा इस बेंनुलअकवामी सतह पर आ गया है और इसीलिए वर्ल्ड बैंक पैसा मंजूर नहीं कर रहा है। मैं वज़ीरे ख़ज़ाना से गुज़ारिश करूंगा, बहुत सारे अंदेशेहाय उन दूर दराज़ के लोगों के

दिलों में पैदा हो रहे हैं। फोरी तौर पर वह इस पर तवज्जुह दें और जो फंड्स वर्ल्ड बैंक के पास रुके हुए हैं, उनको वह वागज़ात करवाएं ...(व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are other businesses to be taken up.

श्री मोहम्मद शफ़ी: तीसरा बड़ा मामला जो हमने लिया है ...(व्यवधान)।

उपसभाध्यक्ष: शफ़ी जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री मोहम्मद शफ़ी: बस एक बात को और कहने दीजिए। जब गुज़िश्ता बहस हो रही थी, तब भी मुझे बोलने के लिए तीन ही मिनट मिले थे। वह इस रियासत में unemployment का मसला था। मैंने तब भी यह बात कही थी और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं कि unemployment के लिहाज़ से जब तक आप कोई स्पैशल पैकेज नहीं देंगे, तब तक यह खत्म नहीं होगी। रियासत ने तो अपने तौर पर एक स्पैशल पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन वसायल के न होने की वजह से उस पर अभी पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है, उसके लिए भी यह कहा गया है कि अप्रैल तक हम इस पर अमलावरी शुरू करेंगे।

मैंने पिछले बजट इजलास में भी यह बात कही थी और मरकज़ी हुकूमत के जितने भी अदारे हैं, उनसे आज फिर मैं यही गुज़ारिश करूंगा कि आप रियासत के नौजवानों को, वे जिस-जिस काबलियत के हों, इंजीनियर से लेकर बाकी सब तक, उनको एक स्पैशल पैकेज के ज़रिए employment फराम करें ...(व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN : We have to take up other businesses. आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद शफ़ी: उससे ऐतमाद भी बढ़ेगा और जो एक बेचैनी का आलम पांच लाख बेरोज़गार पड़े नौजवानों में हैं ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN: Okay, okay. (Time-bell)

श्री मोहम्मद शफ़ी: उनके दिल में एक इत्मिनान पैदा हो जाएगा। अमन और सलामती को कायम करने के लिए यह पैकेज मरक़जी हुकूमत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। बहरहाल शुक्रिया।

(समाप्त)

**** Pp 508-510 Urdu text of the speech will be issued a supplement.**

جناب محمد شفیع (جموں اور کشمیر) : سر، سب سے پہلے تو میں جناب وزیر خزانہ کو اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی مشکل حالات میں ملک کی معیشت کو استحکام دیا اور جو ساری دنیا میں ایک طرح کا بحران تھا، اپنے ملک کو اس بحران سے بچایا۔ Supplementary Financial Bill, جو اس وقت ایوان کے سامنے ہے اور جس پر بحث ہو رہی ہے، یہ دراصل جو بجٹ پاس ہوا ہے، اس میں جو مختلف محکمہ جات تھے، اخراجات میں اضافہ ہونا، اس اضافے کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے یہ بل لائے ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران بھی میں نے اپنی ریاست کے حوالے سے کئی معاملات، ان کے نوٹس میں لایا تھا۔ آج بھی دو-تین معاملات، جو نہایت اہم ہیں، امن اور سلامتی کے لحاظ سے بھی اور ریاست جموں-کشمیر کی مجموعی ترقی کے لحاظ سے بھی، میں ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں-

گزشتہ 15 سال سے ایک بڑا معاملہ مرکزی حکومت کے سامنے رہا، وہ ہے راجوری-پونچھ-بارہمولہ-کپواڑہ اور دوسرے سرحدی علاقوں میں رہنے والے پہاڑی لوگوں کا معاملہ۔ ان کا یہ مطالبہ رہا ہے اور وقتا فوقتا جتنی بھی حکومتیں گزشتہ 15 سالوں میں برسراقتدار یہاں پر رہیں، انہوں نے ایوان میں بھی اور ایوان سے باہر بھی اس معاملے پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ مسئلہ ہے پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کو درد فرشت قبائل کے زمرے میں شامل کرنا، ان کو ایس۔ٹی۔ اسٹیٹس دینا۔ کئ بار اس اعلان میں بھی اس مسئلے پر مباحثے ہوتے رہے۔ اس سےپہلے بھی جو وزیر اعظم آئے ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں ہمدردانہ غور کا یقین دلایا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھہ اس ایوان میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑی لوگ ہمارے سرحد اور Line of Actual Control کے آس پاس رہتے ہیں، اس کے ساتھہ رہتے ہیں۔ اگر ایک ہی گاؤں کے ایک حصے اور ایک طرح کے سماجی اور اقتصادی حالات میں رہنے والے

** Pp 508-510 Urdu text of the speech.

لوگوں کے حصے کو آپ شیڈول ٹرائب قرار دیں اور سماج کے اس دوسرے حصے کو محروم رکھیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس محرومی کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ اس لئے بے چینی بڑھ رہی ہے، بے چینی موجود ہے۔ اس کے نہایت ہی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور نہایت ہی حسّاس علاقہ ہے امن، سلامتی اور دفاع کے لحاظ سے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس معاملے پر فیصلہ کروا دیں، تاکہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو جو ان کا ایک مطالبہ رہا ہے، اس مطالبے کو پورا کروا کر اس بے چینی کودور کریں۔

دوسرا ایک بڑا معاملہ ہے۔ 1996 سے لے کر 2002 تک میں خود اپنی ریاست کا وزیر تعلیم بھی رہا۔ اس وقت ایک پروجیکٹ منظور کیا تھا پالی ٹیکنک کو جدید بنانے کا، وسعت دینے کا اور ان کے معیار کو اونچا کرنے کا ---(وقت کی گھنٹی)--- سر، دو-تین منٹ دے دیجئے، سرحدی ریاست کے معاملات ہیں۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔کورئن): پانچ منٹ ہو گئے، میں کیا کروں، میں نے تین منٹ کہا تھا آپ نے پانچ منٹ لے لیا۔

جناب محمد شفیع : سر، دو-تین منٹ دے دیجئے، کوئی آسمان نہیں گرے گا، میری آپ سے گزارش ہے۔ تب تو ورلڈ بینک نے رقومات منظور کئے اور ہم نے اس پروجیکٹ پر عمل آوری بھی کی۔ اب بھی ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ منظور ہوا ہے اور وہ ہے Ministry of Environment and Forest کا Watershed Development Programme اس کے لئے جو تمام لوازمات ضروری تھے، وہ منظور ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ورلڈ بینک سے اس کے لئے رقومات آنے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید اس ریاست کے اسٹیٹس پر ایک سوالیہ نشان پھر دوبارہ اس بین الاقوامی سطح پر آ گیا ہے اور اسی لئے ورلڈ بینک پیسہ منظور نہیں کر رہا ہے۔ میں وزیر خزانہ سے گزارش کروں گا، بہت سارے اندیشے ہائے اس دور دراز کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ فوری طور پر وہ اس پر توجہ دیں اور جو فنڈس ورلڈ بینک کے پاس رکے ہوئے ہیں، ان کو وہ ---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are other businesses to be taken up.

جناب محمد شفیع : تیسرا بڑا معاملہ جوہم نے لیا ہے ---(مداخلت)---

اپ سبھا ادھیکش : شفیع جی، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔

جناب محمد شفیع : بس ایک بات کو اور کہنے دیجئے۔ جب گزشتہ بحث ہو رہی تھی، تب بھی مجھے بولنے کے لئے تین ہی منٹ ملے تھے۔ وہ اس ریاست میں ان۔ایمپلائمنٹ کا مسئلہ تھا۔ میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی اسی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ ان۔ایمپلائمنٹ کے لحاظ سے جب تک آپ کوئی اسپیشل پیکیج نہیں دیں گے، تب تک یہ ختم نہیں ہوگی۔ ریاست نے تو اپنے طور پر ایک اسپیشل پیکیج کا اعلان کیا ہے، لیکن وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ابھی پوری طرح سے عمل نہیں ہوا ہے، اس کے لئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپریل تک ہم اس پر عمل آوری شروع کریں گے۔

میں نے پچھلے بجٹ اجلاس میں بھی یہ بات کہی تھی اور مرکزی حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے آج پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ریاست کے نوجوانوں کو، وہ جس جس قابلیت کے ہوں، انجینئر سے لیکر باقی سب تک، ان کو ایک اسپیشل پیکیج کے ذریعے ان۔ایمپلائمنٹ فراہم کریں ---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We have to take up other businesses. آپ سماپت کیجئے۔

جناب محمد شفیع : اس سے اعتماد بھی بڑھے گا اور جو ایک بے چینی کا عالم پانچ لاکھہ بیروزگار پڑے نوجوانوں میں ہیں ---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, Okay. (Time-bell)

جناب محمد شفیع : ان کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لئے یہ پیکیج مرکزی حکومت کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ بہرحال شکریہ۔

(ختم شد)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, first of all, I would like to express my gratitude and appreciation for the observations made by the hon. Members. When we have the opportunity of discussing supplementary demands, it provides us an opportunity to have an overall review of the economy and also to point out whether it is going in the right directions, or, there are certain deviations and deficiencies. Some hon. Members have pointed out; I will just point to that. Some hon. Members have also come out with very constructive and positive suggestions and, in fact, most of them have done so. They have critically analysed various proposals and found the justifications for the demands for supplementaries. The Economic Policy is to be analysed, of course, in the context of political philosophy or economic philosophy of a political party. Nothing wrong or unusual in it, but, at the same time, it will have to be placed in the context of the contemporary ground situation in which the Economic Policies are formulated. It cannot be in abstract and in isolation of the ground reality.

(Contd. by 2Z/PB)

PB/2Z/3.50

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): First of all, if somebody suggests that the economy is going down, what are the criteria, what are the parameters? Sir, on all the four major parameters -- economic growth, tax-GDP ratio, fiscal deficit and debt-GDP ratio -- Indian economy has withstood. When you judge the economy of a country, you cannot judge it in four months, five months or six months or even in one year context. You will have to evaluate the performance of the

economy, at least, over a medium-term policy. If we look at the fiscal deficit, in the five-year period between 1999 and 2004, the fiscal deficit was 5.5 per cent of the GDP. It has been brought down to 3.58 per cent in the next four years. Therefore, the economy is improving; economy is not going down. If you want it year-wise, I also have the year-wise figures but to save the time of the House, I am not quoting that. Now, if we take into account the overall GDP growth, India did never have 8.6 per cent GDP growth over a compact period of five years. You take the entire period of the Plan development from 1951 onwards. During 1951-79, the GDP growth was 3.5 per cent. In the entire 80s, from 1981-1990, it was 5.5 per cent. In the fist half of 90s, it was 5.6 to 5.7 per cent; in the second half of the 90s, it was around 6 per cent and up to 2003-04, it was 6.7 per cent. So, we have achieved a growth rate, over a period of five years, of 8.6 per cent.

Now, if you look at Central Government debt to GDP ratio, year-wise, from 1999 till date, particularly, from 1999 to 2003-04, this five-year period, it was around 63 per cent; some time, it was 63.5 per cent, some time, it was 63 per cent; some time it was 62.2 per cent and now in the last two years, it has been brought down to 60 per cent I am talking of the Central Government's debt-GDP ratio, not the country's economy as a whole because in States, there would be variation, but not much.

Therefore, in all these three major parameters, the Indian economy has done well over a period of last five-six years. Everybody knows, all over the world, that 2008-09 is an extremely difficult year and 2009-10 will also be equally difficult year. The world is still grappling to come out

of the situation, come out of the worst recession since 1930s of the last century. We are not living in isolation. We are not in cocoon. Whatever happens in the world has its own impact. There is no mechanism by which we can insulate ourselves from the adverse impact of the world's development.

(Contd. by 3a/SKC)

3a/3.55/skc

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

SHRI PRANAB MUKHERJEE (Contd.): If our exports go down, any number of speeches here or economic discourses are not going to improve the performance on international trade, when we know that 62 per cent of our exports are destined to North America, Europe and Japan, and if there is not a robust economic recovery and generation of demand, Indian export cannot come to the level of 33, 34 or 35 per cent, which we were having in the pre-meltdown situation. If the manufacturing sector has gone down, naturally, the indirect tax revenues will come down. Somebody said that we have provided a stimulus to help capitalists to the extent of Rs.4,88,000 crores. It is not Rs.4,88,000 crores but Rs.1,86,000 crores, and the entire package is not meant for industrial revival. A substantial part of it was meant for generating demand and to step up the developmental expenditure in one year, between 2008-09 and 2009-10; developmental expenditure has been increased by Rs.40,000 crores, from Rs.2,85,000 crores to Rs.3,25,000 crores, between BE to BE, with the hope and expectation that when demand generation in the advanced economies of the world is not taking place, let us make efforts to generate demand internally. And, that

strategy has paid off. As we have noticed, in the first quarter, our GDP grew by 6.1 per cent during April, May and June. Then, in the second quarter of July, August and September, it was 7.9 per cent; taken together in the first two quarters, in the first half of the year, it is seven per cent. And what was the performance immediately before this in the previous two quarters? It was 5.7 and 5.8 per cent of GDP. Therefore, it is slowly moving. It is not that everything is absolutely perfect; nobody claims that. No growing economy can be perfect. There will be deficiencies. There will be shortcomings. And we shall have to try to overcome these deficiencies and shortcomings.

On economic issues, there will be different perceptions; there is no doubt about that. In a multi-party system, in a multi-party democracy, there will be divergence of views. But, over the years, we have been able to bring some sort of convergence. As it was pointed out, when you introduced economic reforms in the early '90s, I had the privilege of being in the Government even at that time. And at that time, I was a Member of this House. Sitting in this House, I witnessed how the different perceptions were placed. But when a major political party came to power, they not only accepted that policy, but in their own way, they gave a momentum to it. I do agree, and that would be the continuity. The other day, when I was replying to the discussion on disinvestment, most humbly and respectfully I had pointed out that from 1991, there had been three formations till date.

(Contd. by gsp/3b)

GSP-AKA-3B-4.00

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): Congress was there. Congress is now along with other partners. From 1991 to 1996, the Congress Party ruled this country alone. From 2004 till date, it is heading a coalition, and, before that, there were two terms of NDA. In between, there were elections, and, prior to that, there was another combination consisting of certain other political parties, supported by us and also supported by the Left, and, they also ruled. But, disinvestment continued from 1991 onwards. It has been pointed out; I do agree -- the other day, I was quoted -- and, I do believe that the disinvestment proceeds should not be used to meet the normal revenue consumption expenditure. It should be used as we are disposing of capital assets, part of it; it should be used for creation of additional capital assets. There is no doubt about it. What is the concept of the NIF, the National Investment Fund? The amount will not be deposited in the Consolidated Fund. What I have stated in the Supplementary Demands is an exception.

In the other House, while replying to the debate, I said, again, we will go back, from the 1st of April, 2012 to deposit in the NIF. Main corpus will remain intact and the income earned out of the corpus will be used for the social sectors, and, three social sectors have been identified. One social sector is 'Health', another social sector is 'Education', and, the third social sector is 'Employment Generation'. These are the projects; these are the targeted social sectors where some investment will be made. But the fund has been operated recently. Up to now only 1800 crore of rupees have come, and, from

there, the corpus which was created, in the first year, we got about 84 crore of rupees, and, in the second year, we got about 250 crore of rupees, with the corpus remaining intact. Each investment -- which I have indicated in the supplementary, both on the receipt side and on the debit side -- that we are to take in is by making an exception. Because of the extraordinary situations, I have to burst the ceiling of the normal fiscal prudence. I myself admitted in the Budget that 6.8 per cent fiscal deficit is not sustainable. We cannot sustain it. Then, we shall have to go back to the situation of 1991, when to borrow a few hundred million dollars, we had to pledge our gold to the Bank of England. I do not want to have that situation. Therefore, the fiscal prudence must be maintained. Sir, 6.8 per cent fiscal deficit cannot be maintained, and, that is why, I have indicated, in my Budget speech itself, that very soon, I would like to come back to the normal fiscal prudence. I have also indicated that the fiscal deficit in the year 2010-11 will be 5.5 per cent, and, in the year 2011-12, it will be 4 per cent, and, thereafter, we shall have to come back to 3 per cent. Because of the intensity of the meltdown, it will take some time, and, in the Indian economy, it will not be less than two to three years. That is why, I have taken this much time.

I come to the third point, and, I want to say something in response to some very valuable suggestions. For instance, on the consultation with the MPs, what I am going to do is that I am going to have the meeting of the Consultative Committee attached to the Finance Ministry, and, in that pre-Budget meeting of the Consultative Committee,

I will not speak, I will invite the Members to give their suggestions on what according to them should be incorporated in the Budget proposals.

(Contd. by sk-3c)

-gsp/SK/3C/4.05

SHRI PRANAB MUKHERJEE (Contd.): I am going to start this exercise from now, apart from the various other groups which we are meeting. I have introduced the system of having interaction with the State Finance Ministers. In fact, I will start meeting with them. From the 15th of January, I will have the meeting with the State Finance Ministers and thereafter with other various groups, economists, industrialists, trade-unions, farmers' interests, etc. So, I will have them.

Now, another important suggestion has come about the direct taxes and the GST. I have stated earlier, and I am repeating it, I am with an open mind. I want major tax reforms. But I am not in a hurry to do something that instead of doing good, it will make the situation worse. I want improvement. I want to do something better than what we have today. Therefore, to replace the existing Income Tax Act which, as has been correctly pointed out in 1922, in 1961 and thereafter so many amendments have taken place that the original shape of the Income Tax Act has been modified so much that sometimes we lost the alphabets and go on adding to it. Therefore, it should be a new code. It will not be the amendment to the 1961 Act. It will be the new code and it would incorporate certain important segments. We are having interactions with various stake-holders. Definitely, after it is introduced, it will be the job of the House to decide how it will respond to it and I will have that.

Mr. Rajeev Shukla raised one issue, a very pertinent one, as I mentioned in my introductory observations that though there would be 25,000 crores of rupees, 30,000 crore rupees I have projected. But as I have explained, 5,000 crore rupees is net savings and 0.73 crores are technical supplementary. So, the net cash outgo would be 25,000 crore rupees. But still, I am not worried over it because there will be some savings in certain other heads. But as the supplementary demands are not from those heads, I could not square it out. I had to spend but in other heads, there will be some savings. So, the net outgo, I am hoping, as a result of the first supplementary, would be zero. I explained yesterday on which heads we have had it.

Certain other important issues have been raised. Mr. Malaisamy raised the question that where you have such a hefty 25,725 crores of rupees as supplementary demands. It is true that sometimes the supplementary demands have been 1 per cent, 1.5 per cent or 2 per cent per cent. This time it is 2.5 per cent of the total Budget. It is a little more. But it is not absolutely exceptional because in the previous first supplementary Budget, it was more than 1,00,000 crore rupees, 1,05,613 crore rupees. So, compared to 1,05,613 crore rupees, my first supplementary is much less; it is 25,000 crore rupees. So, sometimes it has been 5 per cent; sometimes it has been 6 per cent. It has been depending on the situation. And, it is not correct that we did not make the realistic assessments. Please remember that in our Budget-making systems, it will have to be estimated because when I will arrive at the final figure and present to you on the last working day of February, the figures which will be available to me, the actual figures, would be

relating to the month of December, at best, relating to the month of January. I have to estimate the figures for the two months of the current financial year -- what would be the revenue receipt; what would be revenue expenditure; what would be capital receipt; what would be capital expenditure; all will have to be estimated on pro rata basis that is up to December or January I have received so much. So, in the month of February, in the month of March, I expect to have it.

(continued by 3c- ysr)

-SK/YSR/4.10/3D

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): It will be estimated. Therefore, there will always be a grey area. That is why, in our Budget document, we always give Budget Estimates and Revised Estimates. When the actuals are available for one year, in one document you will find actual B.E. and R.E. We have these inherent handicaps and we have to cope with it. But the system has been accepted.

I will give you just one example of it. It has been raised by Shri Amar while speaking on the Air India. It is true that everybody has this doubt whether this package of Rs.800 crore is one-time go, or, whether it will be continuing. What is actual loss? Loss is substantial. But this package of Rs.800 crore came after the recommendations of a Group of Ministers which was set up to look into the health of the Air India. The Group of Ministers while analysing the package arrived at a decision that this much amount might be given to them. But it could not be anticipated when I presented the Budget on 6th of July, because all these developments took place later on. Similar is the case in certain other areas. For instance, import of fertilizers, urea. For instance,

pension for defence personnel. I have to enhance it substantially, because after the Pay Commission's Report, there were various anomaly committees at the level of officials. There were some costs. One major thing took place. We have made some substantial improvement in the pension of our *jawans,* the Personnel Below Officer Rank (PBOR). Then we made improvement in the pension scheme. But that was after the presentation of the Budget. So, these types of expenses were unanticipated. Those things which were unanticipated we have indicated here.

I think I have covered most of the points raised by the hon. Members. On some of the important suggestions, which you have made, I would not like to respond right now. But, surely, I would like to incorporate some of them in the Budget Speech. When the Budget proposals will be unfurled to you, you yourself will come to know which of your suggestions I am accepting. This is the normal practice adopted by a Finance Minister and every time he does it.

Shri Amar has raised two important points. On one general point, I agree with him. I think everybody should agree with us that we should show a little bit restraint on believing whatever appears in the print media or in the electronic media, and we need not indulge in character assassination through the media. Whatever deficiency it may have, we don't have any other alternative forum. The court is there. Whoever is found guilty in the court, he should be treated as guilty. But prior to that, there should not be a trial by the media and, at least, Parliament need not necessarily be agitating on media trial. This is a good point. I think it would be helpful to us if we can try to follow it.

The issue of the WTO has been raised by a number of hon. Members. But this is one of the areas where we are adhering to our interests. We are not going to give concession to Non-Agricultural Market Access (NAMA), which is in the vocabulary of WTO, unless our concerns on agriculture are addressed and the high subsidy, which the industrialised developed countries are giving to their farmers, is reduced. We are not going to give them access to NAMA. That is the reason why the DOHA Round of talks has not proceeded further. Therefore, it is not correct to say that our farmers are having these problems because of the WTO. Farmers have problems. There is no doubt about it. What we have done is this. In the last four or five years, you just see how much Minimum Support Price we have increased.

(Contd. By VKK/3E)

-YSR/VKK/3e/4.15

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): Price is an important issue. If I do not respond to price, everybody will say that he has escaped it. But, is it not a fact that one of the reasons of rise in prices of essential commodities is the cost-push element? If I determine the price of one quintal of sugarcane at Rs.200 with 8.5 per cent recovery, then, you yourself can calculate and come out with what would be the price of one kilogram of sugar. We determine the procurement price of one quintal. The Government is going in for substantial procurement, to the extent of 30 to 33 per cent of the total production and is determining the benchmark and the prices. Now, it is Rs.1000 per quintal on which we procure. If we procure at Rs.950+Rs.50 bonus, that is, Rs.1000 per quintal, then, what would be the price of one kilogram of rice?

Therefore, there is a cost-push element. Nobody is denying that it is causing sufferings to the people, particularly disorganised and weaker sections of the people. How to address this issue? Addressing this issue is not that you would not enhance the procurement price. Procurement prices have to be enhanced and farmers have to be encouraged. Farmers are to be given more and more remunerative prices so that they have the incentive of producing more and, at the same time, help in a situation where there is a shortfall. In respect of pulses, there is a shortfall. The other day, while intervening in the debate, I pointed out that even in early 1990s, we tried with our agricultural scientists to make a breakthrough in the production of pulses that could not prove successful. So, pulses are in short supply of more than four million tonnes and very few countries produce pulses like Turkey, Myanmar, Argentina and some other countries. And, we are importing. If you simply apply your common sense, you will find out the answer that if the international prices were not higher, our traders would have easily imported. The Government is importing. Forget about the Government's inefficiency, the so-called inefficiency of the public sector, why the private traders are not importing? There is no duty. It is under OGL. There is no forward trading. These are banned items in forward trading. Therefore, these are the issues which are pushing up the prices. But, we shall have to address it. It is not to pass on the blame. It is just to accept the ground reality. Shri Mohammed Amin was suggesting that all the things should be distributed through Public Distribution System. Fine! Ideologically and theoretically, it sounds nice. But, we are not able to distribute only 10 to 14 items through PDS. Not a single State

Government is in a position to do that. No Central Government can do it, to carry on with PDS in 6,00,000 villages and a few thousand towns. It is primarily the responsibility of the State Governments and they will have to do it. We can assist them. We can provide them the materials. Yesterday, I had the meeting of the Empowered Group of Ministers on Food Items. Food prices are going up. But, the offtake, which we are providing to the States, is much less. When we are offering them in terms of 1000 tonnes, they are picking up in terms of 100 tonnes. Therefore, these issues are to be addressed and it is not to pass on the responsibility or the buck. We shall have to do it collectively and we are doing it. But, I, myself, have expressed my concern that the prices are a major area of concern and we shall have to address it. We are doing it. Nobody has said that it is not a matter of concern. Nobody says that price is all right. It is not all right because convergence between WPI and CPI is not taking place for a very long period of time. But, we cannot merely solve these issues by indulging in rhetoric. For that, corrective economic steps have to be taken and I can assure the hon. Members that whatever steps are needed, we will take those steps.

(Contd. by MKS/3f)

MKS-GS/4.20/3F

SHRI PRANAB MUKHERJEE (CONTD.): And I am quite confident that Indian economy has started recovering and it will recover because we have the resilience and we have confidence in our workers, in our farmers and in the people of this country. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

**** Pp 525 onwards will be issued as a supplement.**

THE JHARKHAND APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2009
AND
THE JHARKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I move:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

> That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, the 2009-10 Budget of the State of Jharkhand received the assent of the President on 22nd July, 2009 and the date of the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2009 is 20th October, 2009. The matter for consideration, today, is the Supplementary Budget for 2009-10 and the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001. The Jharkhand Supplementary Budget amounting to Rs.1,074.03 crores provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the moneys required to meet the supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the grants made by the Lok Sabha for expenditure of the Government of Jharkhand for the financial year 2009-10.

Let me also brief the hon. Members about the background of the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill. Since the Parliament was not in session and circumstances existed, which rendered it necessary for temporary enhancement of the ceiling of the Jharkhand Contingency Fund from Rs.150 crores to Rs.500 crores for the financial year 2009-10 to carry out drought relief works in the State which has affected all the 24 districts of the State. The Cabinet had recommended to the President to promulgate the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2009 on the 20th October, 2009.

(Ends)

The questions were proposed.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : उपसभापति जी, झारखंड सरकार की जो पूरक अनुदान मांगों की और Contingency Fund रिलेटिड बात माननीय मंत्री जी ने उठाई है और यह कहा है कि इस राशि को डेढ़ सौ करोड़ से बढ़ाकर पांच सौ करोड़ कर दिया जाए। माननीय उपसभापति जी, मैं कुछ दुविधा में हूं कि इस पर क्या बोला जाए। चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। .. (व्यवधान).. 25 तारीख को आ जाएगा। .. (व्यवधान).. अच्छा, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि कब आएगा। हम तो 23 तारीख कह रहे थे, आप 25 तारीख कह रही हैं। .. (व्यवधान)..

श्री उपसभापति : सुश्री मैबल रिबैलो जी, आप उनको बोलने दीजिए, हैल्प होगी । ...(Interruptions)... If you go on interrupting, it will become a problem. I request him not to interrupt him.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति जी, .. (व्यवधान)..

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : एक मिनट, एक मिनट। .. (व्यवधान).. यह इनकी आदत है।.. (व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं because the time of the House will be wasted.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति जी, हमारी सम्मानीय सदस्या मध्य प्रदेश से झारखंड आई हैं। माइग्रेशन के बाद आदमी को समझने में वक्त लगता है और उत्साह भी आता है। मैं उनके उत्साह का सम्मान करता हूं। वह झारखंड में कब तक रहेंगी, यह पता नहीं है।.. (व्यवधान)..

(3जी पर आगे)

LP/4.25/3G

श्री उपसभापति : आप लोग जरा खामोश रहिए..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब एक नई सरकार आने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी, तो यह supplementary Demand, Contingency Fund, Consolidated Fund आदि किसलिए हैं? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको सही सुना है, तो अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने टिप्पणी की कि अकाल के लिए यह व्यवस्था करनी है और यही बात आपके इस लिखित वक्तव्य में भी है। यहां पर आपकी सरकार है। झारखंड में फरवरी में राष्ट्रपति शासन है, संभवत: 18 या 19 से, मुझे exact date याद नहीं है। उसके बीच में झारखंड में Budget पास करने का हम लोगों को मौका मिला था, तारिक भाई आप भी बोले थे, मुझे याद है मैंने भी उसमें शिरकत की थी। अगर भारत सरकार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत झारखंड की व्यवस्था कर रही है, तो क्या आपका कोई आकलन नहीं होता है, यह हम जानना चाहेंगे? यह बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमने इसी हाउस में और उस हाउस में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आपके झारखंड के बजट को पारित किया, जो संवैधानिक आवश्यकता है कि वहां राष्ट्रपति शासन है, अगर भारत सरकार झारखंड का शासन चला रही है, तो किस बात का आकलन है कि आपके पास अकाल की जानकारी नहीं है? उसके लिए खर्चे की जानकारी नहीं है, उसके लिए आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है? आज जब चुनाव का नतीजा दस दिन बाद आने वाला है तो आप कह रहे हैं कि हमको पांच सौ करोड़ रुपए चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मैं यह बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह तर्क बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, ..(व्यवधान)..आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हमें झारखंड के लिए दूसरा दर्द होता है। मैं बिहार से आता हूं, झारखंड

हमारे बिहार का ही था। झारखंड नया राज्य बने, इसमें हम सबकी सहमति थी। वहां हमारे जो वनवासी, आदिवासी बंधु हैं, उनकी मांग वर्षों से थी कि उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, उनकी आशा मजबूत होनी चाहिए.(व्यवधान)..

श्री तारिक अनवर : लेकिन आज ही आपके मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि झारखंड और बिहार को एक होना चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप बैठिए। उपसभापति जी, आज मुझे यह पीड़ा होती है, वहां हम भी शासन में थे, हमारा बहुमत भी था, बहुमत कम रहा तो हमें कुछ लोगों को सहयोग देना पड़ा। मुझे यह स्वीकारना पड़ेगा कि उसकी मजबूरियां भी थीं, लेकिन हम नियंत्रण में रखने की कला समझते थे। हमारे उधर के मित्रों ने कहा कि एक सांप्रदायिक ताकत झारखंड में कैसे बैठी हुई है? इसको हटाना है। हटाना है तो उसके लिए जोड़-तोड किया गया। वह अतीत की बात है, लेकिन भारत की राजनीति का एक शर्मनाक पहलू शुरू हुआ जब निर्दलीय मुख्यमंत्री बना, पांच निर्दलीय मंत्री बने और दो प्रमुख मेजर दल, कांग्रेस पार्टी और आर.जे.डी. बाहर रहे। यह भारत की राजनीति की कैसी बड़ी विडंबना है कि जो पांचों हैं - आज पांचों एक साथ मुख्यमंत्री सहित जेल में हैं, मैं किसी का नाम लेकर उनका सम्मान नहीं करना चाहता हूं, ये हमारे लिए बड़े सवाल हैं, ये बड़े पीड़ादायक सवाल हैं। मैंने एक जगह एक शब्द पड़ा political entrepreneurship. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तीन-चार निर्दलीय एम.एल.ए. मिलिए, तोल-भाव करिए, अपनी हैसियत बताइए, पहले पीछे से सहयोग करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार का समर्थन देने की तुम्हारी मजबूरी है। यह पीड़ादायक अनुभव, जो हमें झारखंड में हुआ है, हमने उसको देखा है। उपसभापति जी, मैंने सुना है कि झारखंड का कर्ज 22,000 करोड़ रुपए है। शायद मंत्री जी बताएंगे। 22,000 करोड़ का कर्ज और 4,500 करोड़ का घोटाला, क्या अनुपात है? बहुत सुन्दर अनुपात है। उस सरकार को आप लोगों ने तेईस महीने समर्थन दिया। झेलना तो दूसरी बात है, समर्थन दिया और समर्थन का दावा यह जब मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई होती है तो वे ताल ठोककर बोलते हैं कि समय आने पर मैं सब दिल्ली वालों का नाम खोलूंगा।

(AKG/3H पर जारी)

AKG/3H/4.30

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : यह कौन सा मजाक हो रहा था? यह बात मैं कोई आरोप के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, भारत के लोकतंत्र के एक पीड़ादायक, शर्मनाक अध्याय की चर्चा कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) ...

श्री तारिक अनवर : वे पाँचों आपके मुंडा जी के मंत्रिमंडल में भी थे। जो चीफ मिनिस्टर हैं, वे भी आपके मंत्रिमंडल में थे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : तारिक साहब, आपकी सियासत की जमात का वहाँ कोई वजूद नहीं है, तो आप क्यों परेशान हैं? आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र की मजबूरी के कारण हमने उनका समर्थन लिया था, लेकिन हम उनको control करना जानते थे, माथे पर नहीं बिठाया करते थे। यह अन्तर था। जिस दिन हमें लगा कि अब ये बेरास्ते हो रहे हैं, हमने अपनी सरकार को गँवाना मुनासिब समझा, उनके साथ समझौता नहीं किया, यह हमारे और आपके बीच का अन्तर है। आप लोगों ने 23 महीने बिठाया। झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ 22 हजार करोड़ रुपए का घाटा है, वहाँ पर 4.5 हजार करोड़ रुपए की लूट हो रही है। लाइबेरिया में, दुनिया के कई नए देशों का नाम मैं सुन रहा हूँ, मैं भी वाजपेयी जी की सरकार में हिन्दुस्तान का कोयला, खान मंत्री हुआ हूँ, दुनिया में कहाँ-कहाँ माइंस हैं, हमें जानकारी रही है, लेकिन यहाँ-यहाँ माइंस हैं, यह तो मुझे भी नहीं मालूम था। यह तो कमाल की entrepreneurship हो रही थी। माननीय उपसभापति जी, कोई fake currency note नहीं आ रहा था, यह पैसा cash में आ रहा था। आज आप थे, जब प्रश्नोत्तर चल रहा था कि मुम्बई के यूनियन बैंक में 600 करोड़ रुपए जमा किए गए। वे पैसे बकायदा proper notes थे। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? कौन दे रहा था? एक-एक दिन में 48 mining lease sign हो रही है। ये mining lease कौन sign कर रहा था? अगर मुख्य मंत्री जी कर रहे थे, तो क्या उनके साथ ऑफिसर्स नहीं थे? क्या उसका प्रस्ताव नहीं बन रहा था, क्या उसकी टिप्पणी नहीं बन रही थी? उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, जो मंत्री जी के साये में खड़े थे और उनको इस पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने के लिए एक षडयंत्र के तहत कार्रवाई कर रहे थे? मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहूँगा कि 23 महीने तक एक गरीब राज्य की यह लूट दिल्ली के समर्थन के साथ

चल रही थी। वे चुप थे, वे शान्त थे और यह आकंठ भ्रष्टाचार चल रहा था। यह शर्म की बात है। तारिक साहब, क्षमा करिए, आपकी जमात के जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वे समर्थन नहीं किए होते, तो 23 महीने यह लूट नहीं चलती और हम मान लें कि यहाँ मालूम नहीं था। आज वहाँ इनकम टैक्स विभाग enquiry कर रहा है, वहाँ का vigilance कर रहा है, money laundering हो रही है और आपकी भारत सरकार की जितनी शाखाएँ हैं, खुफिया वगैरह, सब लगी हुई हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या 23 महीने तक ये एजेंसियाँ भारत सरकार को नहीं बता रही थीं कि झारखंड में क्या हो रहा है? क्या ये लोग जानते नहीं थे? अगर बता रही थीं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो मीणा साहब, यह जवाब आपकी सरकार को भी देना पड़ेगा कि इस सरकार को 23 महीने लूट करने क्यों दिया गया। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज आप अनुपूरक मांग के लिए आए हैं। आप चाह रहे हैं कि Contingency Fund को 150 करोड़ से 500 करोड़ किया जाए। जब पैसे खर्च हो रहे थे, लुट रहे थे, तो जो सरकार आपके समर्थन से चल रही थी, उसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे थे, इसकी जवाबदेही तो आपको लेनी पड़ेगी और संसद में यह सवाल हम उठाएंगे। उपसभापति जी, यह सवाल इसलिए उठाना बहुत जरूरी है कि मैंने जो आरम्भ से बात कही कि पीड़ा का सवाल यह है कि झारखंड हमारे बिहार का अंग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े। मैं जेपी मूवमेंट के समय झारखंड के इलाकों में बहुत घूमा हूँ। मैं वहाँ के अरमानों और अपेक्षाओं को जानता हूँ। वे एक अच्छा राज्य चाहते थे। ... (व्यवधान) ... हाँ, यह वाजपेयी जी की सरकार के समय हुआ था, यह तो लोग जानते हैं। आज वहाँ के पूर्व मुख्य मंत्री, जो जेल में हैं, वे मीडिया में ताल ठोंक कर बोलते हैं कि समय आने पर मैं सबका नाम खोलूँगा और दिल्ली के लोग खामोश हैं। क्या बात है? यह खामोशी भी बड़े कमाल की चीज है। कोई जवाब नहीं आया। तारिक साहब, आप भी चुप रहे। जब वे मीडिया में बार-बार बोल रहे थे कि मैं सबका नाम खोलूँगा कि मुझे दिल्ली में कौन लोग परेशान कर रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान भी चुप थी। आप तो उनके साथ हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, चूँकि आपने दो-तीन सवाल उठाए, तो मैं उम्मीद करता था कि आपकी ज़ुबान तो चलेगी। आपकी ज़ुबान भी खामोश रही और यह पीड़ा पूरे झारखंड को है।

(3जे/एससीएच पर जारी)

SCH/4.35/3j

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत): माननीय उपसभापति जी, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, जो उस सदन में चर्चा के दौरान दिए गए थे। उनको देख कर मुझे बहुत पीड़ा हुई है। इन्होंने खुद कहा है कि plane size 8,200 करोड़ रुपये का है। नवम्बर से लेकर अब तक खर्चा हुआ है - 2,056 करोड़ रुपया, यानी पूरे 5,950 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं, जो उन्होंने पहले ऐप्रूव किए थे। फिर बाकी पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब क्या है?

उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी कि केन्द्रीय योजना के लिए 1,355 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 244 करोड रुपये खर्च हुए हैं। गैर योजना मद के लिए 13,437 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 4,200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आपके पास इतने बड़े ऐलॉटिड एमाउंट हैं, एप्रूव्ड एमाउंट हैं और खर्चा इतना कम हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सप्लीमैंट्री चाहिए! माननीय उपसभापति जी, इस supplementary, complimentary में बहुत discrepancy है। मेरी समझ में कुछ बात नहीं आती है। मैंने पहले ही कहा है कि 'बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी'। मैं कितनी बातें निकालने की कोशिश करूं, लेकिन मंत्री जी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। यह जवाब भी आपको जरूर देना पड़ेगा कि आपको अकाल का आकलन क्यों नहीं था? आज आप कह रहे हैं कि आपको रुपये की जरूरत है, क्योंकि वहां अकाल पड़ा हुआ है। इस बार पूरे देश में कम वृष्टि हुई थी, परेशानियां थीं, झारखंड का नाम भी उसमें आया था। आपके सामने मैं सदन के उस सारे उत्तर को दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि low rain area में झारखंड का भी नाम था। इसका आकलन आपने पहले क्यों नहीं किया था? आज चुनाव के नतीजे निकलने के सात-आठ दिन पहले आपको इसकी चिंता हो रही है। यह बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीरता से हम इसका प्रतिकार करते हैं। इसलिए यह बात समझने की बहुत जरूरत है।

हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है? झारखंड में पूरे आठ महीने से आपका राज्य है। पहले आपका राज्य खम्भों के सहारे था, ऊपर में मधु

कोडा एंड कंपनी थे और नीचे में आप थे। लेकिन अब आठ महीने से आप खुद हैं। कितनी पीड़ा होती है क्योंकि लूट का कारोबार बड़ा रोचक चल रहा था।

उपसभापति जी, आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि राज्यपाल महोदय के दो-दो OSDs को गिरफ्तार करना पड़ा। क्या यह कहीं और हुआ है? मैं उन राज्यपाल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह कितने शर्म की बात है

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: वह इस हाउस के मैम्बर भी थे।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अब हाउस के मैम्बर थे या नहीं थे, उसमें मैं क्या जाऊं, लेकिन वह श्रीमान् महामहिम राज्यपाल जी, आपके द्वारा नियुक्त किए गए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने हम लोगों की सरकार को गिराने में क्या-क्या काम किया, इसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अपने राज्यपाल के OSD को गिरफ्तार करना पड़ा और उनकी enquiry करवानी पड़ी, उन पर raid करना पड़ा। हम लोगों ने मांग की थी कि उन राज्यपाल को हटाया जाए, तब राज्यपाल जी ने कहा कि मैं नहीं हटूंगा। फिर जब मामला कुछ वोट बैंक का आ गया, तो कहा गया कि भैया! तुम असम चले जाओ। यह क्या मतलब है? यह कौन सी शर्मिंदगी है कि मुख्यमंत्री अब जेल में हैं, उनके चारों मंत्री अब जेल में हैं और राज्यपाल के दोनों ओएसडीज़ के ऊपर raid है, वे भी अब जेल में हैं। सर, यह कौन सा शासन चल रहा था? यह बात मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि आज जो आप अनुपूरक मांग में अपनी राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए आप इस सदन की संस्तुति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ आंकड़े रखे हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह पूरा घालमेल, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है और आप अनुपूरक मांगों से अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे हैं। यह बहुत ज़बरदस्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसका हम प्रतिकार करना चाहते हैं।

सर, वैसे आपकी घंटी बजने से पहले ही मैं बैठ जाऊंगा। आप जानते हैं कि मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूं ...(व्यवधान) राजीव शुक्ल जी, आपको ध्यान रहे कि आप समय के बाद जाते हैं और मैं समय के अन्दर जाता हूं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा ...(व्यवधान) इसके लिए भी आप उन्हीं को ...(व्यवधान) ओहो...(व्यवधान)।

उपसभापति जी, मैं सिर्फ एक विषय पर और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने नरेगा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। झारखंड में नरेगा की स्थिति बहुत चिंताजनक है और जहां तक मुझे मालूम हुआ है, नरेगा के लिए 2,500 करोड़ रुपये का ऐलोकेशन था और उसमें से 1,000 करोड़ रुपया लौटा दिया गया, क्योंकि वह खर्च नहीं हो सका था ..(व्यवधान)

सुश्री मैबल रिबैलो: यह गलत है।

श्री उपसभापति: वह बोल रहे हैं न, आप बीच में मत बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप बैठिए न, आप इतनी उत्सुक और उतावली क्यों है? अभी आप झारखंड में नहीं गई हैं। अभी आपको समय लगेगा वहां एडजेस्ट करने में।

श्री उपसभापति: आप उनको जवाब मत दीजिए, अपनी बात बोलिए।

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री उपसभापति: आपका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उस वक्त पर आप बोल लीजिए।

3k/Psv पर आगे

-SCH/PSV-KS/3K/4.40

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं आपको बता रहा हूँ कि सितम्बर के महीने में राज्यपाल जी का एक बयान था, जो मीडिया में छपा था कि 'NREGA failed, 10 Arab lapsed'. अब आपके राज्यपाल जी अगर होम वर्क नहीं करते तो हम क्या करें? वहाँ अगर राष्ट्रपति शासन है तो आपका शासन है, क्योंकि वह केन्द्र का शासन है। इसलिए नरेगा के बारे में यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम चाहेंगे कि मंत्री जी, आपका शासन वहाँ चल रहा है, इसलिए आप ज़रा बताएँगे कि नरेगा में कितनी सफलता मिली है, कितने काड्र्स बने हैं, कितने लोगों को सहूलियत मिल रही है? क्योंकि नरेगा ऐसे कार्यक्रमों की सबसे बड़ी सफलता तब होगी, जब इन नक्सल-प्रभावित इलाकों में जो गरीब आदिवासी बन्धु हैं, जो कई बार महुआ के आधार पर अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, मैं गरीबी की ज़िल्लत को जानता हूँ, उनको इससे कितनी सहूलियत मिली है और पैसे का सदुपयोग हुआ कि

नहीं, यह हम जरूर जानना चाहेंगे? इसके साथ-ही-साथ यह भी जानना चाहेंगे कि नरेगा का खर्च किन-किन NGOs के माध्यम से हो रहा है? वे NGOs कितने प्रामाणिक हैं? क्या वह राशि लोगों तक पहुँच रही है? ये सवाल आज उठाने इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि आप अनुपूरक माँग लेकर आए हैं और Contingency Fund को आप डेढ़ सौ करोड़ से पाँच सौ करोड़ तक लेना चाहते हैं। मीणा जी, एक छोटी-सी, साधारण-सी बात होती है। आपका प्रशासकीय अनुभव भी है कि आगे का खर्चा पीछे का हिसाब देख कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप सदन के पास आए हैं कि हमारी राशि बढ़ाइए, तब हम तो इसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन, यह जरूरी है कि आप सदन के अन्दर यह बताइए कि आपने नरेगा जैसे जनोपयोगी कार्यक्रम में किस तरह का परफॉरमेंस किया है? यह हम जरूर जानना चाहेंगे।

उपसभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमें एक बात की बहुत पीड़ा है। वह पीड़ा यह है कि यह पूरी अनुपूरक माँग जल्दबाजी में लाई गई है। यह हम कहना चाहेंगे। हमें सरकर के पूरे इरादे पर संशय है। हम उस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं कि अभी चार-पाँच महीने पहले अगर हम लोगों ने झारखंड का बजट इसी हाउस से पास किया था, तो चार महीने के बाद इनका आकलन इस तरह से गड़बड़ क्यों हुआ कि आज उन्हें चुनाव के नतीजे आने के मात्र एक हफ्ते 9 दिन पहले अनुपूरक माँग लेकर आना पड़ा। यह संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, यह सांवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है तथा यह संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसलिए मैं इस पूरे अनुमान का और योजना का पूरा विरोध करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री उपसभापति: सुश्री मैबल रिबैलो।

सुश्री मैबल रिबैलो(झारखंड): सर, मेरे बड़े भाई रवि शंकर प्रसाद जी ने अभी ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: वह आपसे छोटे हैं...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: वह बड़े भाई नहीं हैं? ...(व्यवधान)... वह बड़े नहीं हैं, ऐसा आप बोलिए। ...(व्यवधान)... इसे एडमिट करिए ...(व्यवधान)... एडमिट करिए न? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बड़े हैं, ...(व्यवधान)... बड़े हैं, बोलिए। ...(व्यवधान)... ठीक है।

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, अभी इन्होंने supplementary budget पर बोला है। कई चीजें इन्होंने गलत तरीके से पेश की हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ...(व्यवधान)... हाँ, यह बड़े भाई होने के बावजूद ...(व्यवधान)... नरेगा की बात जो इन्होंने की है कि हजार करोड़ लैप्स हुए हैं, यह बिल्कुल गलत है। आप मंत्री जी से पूछिए ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: अपने गवर्नर साहब से कहिए कि वह मत बोला करें ...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: आप ही मंत्री जी से पूछिए। ऐसा कोई लैप्स नहीं होता है। ...(व्यवधान)... यह carry on होता है। यह यहाँ पर एक मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इनको पता नहीं है। RD Ministry कैसे चलाते हैं, नरेगा कैसे चलता है, इनको पता नहीं है। यह सुनते हुए मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ...(व्यवधान)... यह सुप्रीम कोर्ट के एक learned lawyer हैं, उसके बावजूद भी। ...(व्यवधान)... हाँ, इसमें जो भी कहें, ऐसा है चिल्ला-चिल्ला कर के बोल दिया, ताकि जनता सुने और मान ले। ...(व्यवधान)... यह इनका है।

श्री उपसभापति: आप भी चिल्लाइए मत। ...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: सर, इनको यह पता नहीं है कि जब यहाँ पर झारखंड बजट पेश किया गया था, तब महीनों किसी को सपना नहीं था कि rains will fail and all the 24 districts will be affected by drought. ऐसा कोई सपना था क्या? तब ऐसा कोई सपना नहीं था। इसलिए अभी यह supplementary budget लाने की जरूरत पड़ गई है। यह supplementary budget यहाँ से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का consent मिलेगा, तब तक वहाँ एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। इसलिए इसमें अगर आप इतने इच्छुक हैं, आपको इतना ओवर कॉंफिडेंस है कि आप वहाँ गवर्नमेंट बनाएँगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यह आपका सपना है। आप वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बना पाएँगे। वहाँ गवर्नमेंट कोई दूसरे बनाएँगे। वहाँ हम गवर्नमेंट बनाएँगे। तब आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपका सब ओवर कॉंफिडेंस खत्म हो जाएगा। ...(व्यवधान)... हाँ, हाँ। यह आठ ही दिनों का मामला है, यह मैं भी मानती हूँ।

सर, वहाँ इतना drought है। The whole month of June, वहाँ पर बरसात नहीं हुई है। झारखंड में केवल 7 परसेंट इरिगेशन है। झारखंड बिहार का अंग था। इन लोगों ने झारखंड को क्या बना कर के रखा था? चारागाह बना कर के रखा था। वहाँ केवल 7 परसेंट ही इरिगेशन है।

(3एल/डी0एस0 पर क्रमश:)

-psv/ds-tdb/4.45/3l

सुश्री मैबल रिबैलो (क्रमागत) : इसकी वजह से जब जून में बरसात नहीं आयी, तो झारखंड की जनता को इससे almost 60 per cent crop failure हुआ है। झारखंड में केवल एक क्रॉप होती है और वह है धान और वह हुई नहीं है। इससे लोग परेशान हैं। तीन महीने तक हमारी गवर्नमेंट ने.. (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, एक मिनट। अभी आपने कहा कि हमने उसे चारागाह बना रखा था..(व्यवधान)

सुश्री मैबल रिबैलो : ठीक है, हम yield कर रहे हैं, बोलिए..(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : यहाँ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। Joint बिहार में आजादी के 50 सालों में 47 साल कांग्रेस ने राज किया है। तो आप अपना होमवर्क ठीक किया कीजिए कि चारागाह किसने बनाया था। आप ऐसी बात मत बोल दीजिए कि आपको समस्या पैदा हो जाए। ..(व्यवधान)

सुश्री मैबल रिबैलो : ऐसा है सर, इसे मैं admit नहीं कर रही हूँ कि यह कांग्रेस ने किया है, इन्होंने नहीं किया है। वहाँ इनकी भी गवर्नमेंट थी। मुझे लगता है कि करीब 50000 करोड़ spent करके भी वहाँ डैम्स अधूरे पड़े हैं। अगर अभी भी उस डैम के लिए एक पैकेज मिले और वह डैम कम्प्लीट हो जाए - क्योंकि जहाँ डैम हैं, वहाँ कैनाल नहीं हैं, जहाँ कैनाल हैं, वहाँ डैम नहीं हैं और जहाँ डैम हैं, वहाँ sluice gate नहीं हैं। इस तरह सब काम अधूरा करके छोड़ दिया है। अगर यह सब कम्प्लीट हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैकेज दे और उसे कम्प्लीट करे तब झारखंड का irrigation potential 7 per cent से 22 per cent हो जाएगा। The irrigation potential will go up by almost 15 per cent. And what Jharkhand needs is irrigation and electricity. ये दो चीजें

अगर आप वहाँ की जनता को पर्याप्त रूप से दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब और हरियाणा को पैकेज देकर, पानी, बिजली और स्वामीनाथन जी की मदद मिलने से वहाँ के लोग दो-तीन फसल उगा कर संपन्न हुए हैं, वैसे ही झारखंड भी संपन्न हो सकता है। यह पैकेज बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो अधूरे पड़े स्कीम्स हैं, उनको कम्प्लीट करके वहाँ की जनता को पानी देना पड़ेगा। झारखंड की जनता बहुत मेहनती है, झारखंड की जनता खेती-बाड़ी जानती है और झारखंड में अच्छी जमीन और पर्याप्त धूप है। केवल बिजली, सिंचाई और पानी की वजह से झारखंड पिछड़ा हुआ है। आज झारखंड में देश का 40 प्रतिशत मिनरल बेल्ट होने के बावजूद 70 प्रतिशत जनता गरीब है, बीपीएल फैमिली की हैं। अभी इन्होंने कहा कि ये पैसे क्यों देने हैं, तो ये पैसे देने जरूरी हैं, नहीं तो लोग भूखे मरेंगे। सर, अभी हमें जनता को खाना खिलाने की जरूरत है। किसी ने भी यह सपना नहीं देखा था कि यह drought आएगा, बरसात failure होगा और लोग अनाज पैदा नहीं कर पाएँगे, इसकी वजह से जनता को परेशानी होगी। हम इसीलिए पैसा मांग रहे हैं मेरे बड़े भाई, थोड़ा सुन तो लो।

सर, वहाँ Twenty four districts are affected और देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य। यहाँ देश में हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ Rice Mission है, हमारे यहाँ Wheat Mission और Pulses Mission है, जबकि झारखंड एक single crop लेता है, वह भी धान का और Rice Mission में झारखंड के केवल पांच जिले added हैं। Nineteen districts are not added. All the twenty four districts should be added in the Rice Mission, Sir. Then, today, we are thinking of importing rice from Thailand. वह परेशानी देश को नहीं आएगी। Jharkhand will provide as much rice the country needs. The farmers of Jharkhand will produce it and provide it to the people of India. उसी प्रकार pulses के बारे में है। We are importing pulses from Myanmar and Australia. Jharkhand climate is ideal for growing pulses. Jharkhand can grow enough pulses provided we give Jharkhand proper support. Add all the 24 districts of Jharkhand in Pulses Mission and give them the support or whatever is needed. You

give them technical support, agricultural support, water and electricity, and they will produce pulses for the country. You need not import it from elsewhere. Similarly, oilseeds. Plenty of oilseeds can be produced there. Under the Horticulture Mission, Western Maharashtra has taken so much of money, and is producing so much of fruits there. Jharkhand is ideal for growing fruits and orchids, and we can have forward, backward linkages, and that can create plenty of jobs there. All these things which we are talking about, like Naxal and unemployment can be eliminated. But, somebody has got to give package and some capital investment should be there in Jharkhand. Only then jobs can be created; otherwise, what is happening is this. The rich man is becoming richer there and the poor person is becoming poorer. You see, the BPL people are still becoming poorer. This is not fair, Sir. That is why this money is needed. Sir, it is true that ever since the new Governor has come there, the present Governor has done a lot of things there for the people. First of all, he has given to the people the Public Distribution System.

(Contd. by 3m-kgg)

kgg/3m/5.50

MISS MABEL REBELLO (CONTD.): He has revised the Public Distribution System. He has started supplying the foodgrains at the ration shops and he has given almost one-third of the ration shops to women self-help groups to eliminate corruption from this PDS. Now, the PDS has started functioning quite well, I must say that.

Similarly, we have given BPL cards to something like 15 lakh families and almost 9 lakh Antyodaya families are given 35 kilos of foodgrains, either wheat or rice, free of cost for the last three months.

Similarly, primitive tribes also have been given grains free of cost. These are all the things which the Jharkhand Government has done for the last few months. There are 13,000 Anganwadis and they have started 6,000 more Anganwadis so that a lot of children of Jharkhand may get supplementary food. Similarly, Agriculture Department has given something like 47,000 quintals of wheat and gram seeds to the farmers and 3,000 quintals of vegetable seeds are given to the farmers. All that the farmers need is, I would again and again reiterate, water and electricity. The Government is trying to give them the seeds. Along with the seeds, they need water. The problem is of water and lack of electricity.

Sir, Kisans Credit Card has been given to a large number of farmers. Shri Ravi Shankar had been saying on NREGA. Sir, 1,29,500 schemes of NREGA are in vogue and are at various stages of completion. People are working and because of success of NREGA, the large number of migration that was to be there in Jharkhand has been stalled; I do not say that it is completely stalled; but, to a large extent, the migration is depleting. So, that is the success. Of course, NREGA needs to be improved. I know that there is corruption in NREGA; I know that the executives, the Block Development Officers, the DDAs are not functioning as desired. It needs to be improved to a large extent.

Sir, in the health sector also, earlier Jharkhand used to have the IMR rate as 72 in 2001. It has come down to 48. MMR rate was almost 400 and it has come down to 312. So, in the health sector also, in IMR and MMR, we have improved upon. So, things are improving. But, it is slow. The pace is not as desired, as we would like it to be.

Sir, the Central Government has also given Rs.6,540 tonnes of wheat and 3,270 tonnes of rice for three months for the people of APL families because they are also affected by this severe drought. The crops have utterly failed. So, even the people of above poverty-line have been helped.

Similarly, in regard to irrigation projects, 33 projects of medium irrigation projects are nearing completion. So, once these projects are completed, quite a lot of farmers would get water and they will produce more grains, more pulses and more oilseeds. Things will improve. Through this Supplementary Budget what they are asking is Rs.1,074 crores.

Sir, I am happy on one count and I am a little bit unhappy on another. They have not spent money on irrigation saying that the allotted money of Rs.90 crores for irrigation could not be spent because they could not acquire land. I do not palliate this. It is not to be tolerated. Similarly, on higher education; they could have spent Rs.90 crores on the IT sector, they have not spent. Similarly, on health sector, they have not spent Rs.35 crores. This way, where they should have spent, have not spent. But, I am happy that they have now allocated Rs.150 crores for bridges. The major problem in Jharkhand is rural connectivity. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, hardly 20 per cent roads have been connected.

(Contd. by kls/3n)

KLS/3N-4.55

MS. MABEL REBELLO (CONTD): Similarly, Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has a provision of constructing bridges only of 50 meters

length and beyond that PMGY does not sanction money. That money has to come from the State funds. Jharkhand having major rivers, which are beyond 50 metres, those bridges have to be constructed with the State funds. Earlier they had spent Rs.200 crores and now a provision of Rs.150 crores has been made for these roads. Once these bridges are connected, there will be rural connectivity for a large number of people. Otherwise, during rainy season a large number of people live almost in islands. This creates a lot of problems. Without rural connectivity, women cannot go to hospitals and a large number of people even die. There are snakebites, malaria, TB, and other such diseases. These areas are cut off for four months. That gives chance to the Naxalites to sit in those islands, form their strategy, and have their trainings and camps, Sir. With this sort of connectivity, Jharkhand will improve. Similarly, they have made provision for electrification, that is, upgradation of the Power Grid. The cables, the wirings, are all in bad shape. So, through this Appropriation Rs.193 crores have been allocated for electrification, that is, for Power Grid upgradation. With that, the electricity flow to the State will be better, Sir. Now with this Rajiv Gandhi Electrification various projects in various districts are under completion. So, with this type of allocation the flow of electricity will be better. That is a very good thing, Sir. There have been a lot of things happening in Jharkhand; it is not that things are all bad. All that we have to do is that there should be political will, the bureaucrats have to work and the politicians have to make the bureaucrats to work. What he said is true that Jharkhand has not spent the money. They have spent 40 per cent of the budget. I do not support all that. The money

needs to be spent; proper investment should be there particularly for irrigation projects and electricity generation. The neighbouring State Chhattisgarh is producing so much of electricity that they are selling it outside. While Jharkhand, having more coal than Chhattisgarh, has not been able to attain self-sufficiency in electricity which is not at all a good thing. So, a lot of things need to be done. This is a State, which requires help, this is a State, which has got a large number of poor, this is a State, which is affected by Naxals, Sir. There are lots of problems. This is a State, which does not have adequate bureaucracy. It does not have even smaller officers. The JPSC has not adequately selected people like teachers, small officers, clerks, LDCs, UDCs, Section Officers, etc. They are not there. So, the systems are not in place. Who started the State, Sir? When the State was first started, the first Chief Minister and the Government should have put the systems in place. They failed to put the systems in place and because of that today Jharkhand is in such a bad shape. So, let not Mr. Ravi Shankar Prasad say that they have nothing to do. So, they are part of the sin that has been committed against Jharkhandis and Jharkhand people. They are also responsible for the poverty, misery, and lack of development of Jharkhand. Let him admit that. Let him not wash his hands like this. It is not fair for them. They have ruled the State for almost three or four years out of nine years. So, they had failed and because of their failure for not putting the systems in place and not giving a good start, the State of Jharkhand has failed, Sir. Therefore, I request that this Appropriation Bill may be passed. Thank you.

(Ends)

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (WEST BENGAL): Sir, at this stage, there is no reason than to support both the Bills, that is, Jharkhand Appropriation Bill and the Jharkhand Contingency Fund. But I would like to mention two or three points. Now elections have been held, the new Government will come up. Perhaps this is the only State where elections have not been held in any of the local bodies after the amendment of the Constitution.

(Contd by 3o/SSS)

SSS/3O/5.00

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (CONTD.): This point was raised by us previously here also. So, I want to know from the Minister, when the elections of the local bodies in the State of Jharkhand will be held and what steps are going to be taken in that matter. Sir, we should realise that it is a State full of natural resources, abundant natural mineral properties, with half-fed people, starving people, with no irrigation facilities and it is full of corruption. The State has become practically a place of mafia raj and we should admit, whether we are sitting on this side or that side, that none of them can avert the responsibility of the state of affairs as far as corruption, mafia raj is concerned in the State of Jharkhand. Frequent looting of natural resources has become a common affair in the state of Jharkhand. When we compare Jharkhand with the rest of the country, sixty per cent of our cultivable land depends on -- *Allah ki varsha ke upar nirbar hai,* -- rain. What is the condition of Jharkhand State? Sir, I remember, when we discussed law and order situation, Contingency Fund was discussed here in this House. Jaswantji was here. I remember what he said. He said that it

is a horrible state of affairs in Jharkhand. When we go out we do not know whether we will return. Naxalites, Maoists raj is there. We also feel it from West Bengal, the bordering areas. He said -- and I remember -- that if we had understood this situation earlier, we would not have created the State of Jharkhand. He said this from that side, and, if we had realised this situation earlier we would not have supported this Bill for the creation of a separate State. The Minister is here. We hope that all of us will help the newly elected body, whoever comes into power. We hope that political support should not be there. Otherwise, it will be very difficult. The Prime Minister has said that it is the greatest danger and somebody from that side will support. We cannot do away with this Maoist menace. Jharkhand is facing this problem and that side openly stated here that all of us should realise this problem. Sir, actually, we remember that many of the corruption cases are pending. It would be better if the Minister supplies the list. Not only this, the previous Chief Minister is now in jail. Everybody tried to exploit him for their own political purposes. So, can the Minister supply the list showing their names, the affiliations against whom the corruption cases are pending? I would like to ask the Minister about that. Sir, we hope that the poor people of Jharkhand, the newly elected Government and with the support of all of us we will be able to run peacefully. With these few words, Sir, I support this Jharkhand Appropriation (No. 3) Bill 2009 and The Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill 2009.

(Ends)

(Followed by NBR/3P)

MP/3P/5.05

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, झारखंड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 और झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये तीनों राज्य आज से करीब 9 वर्ष पहले एक साथ बनाए गए थे। इसमें जो झारखंड राज्य था, उससे बड़ी उम्मीद थी। इसमें जो सम्पदा थी, जो खनिज पदार्थ थे, जो लौह अयस्क थे, उनसे बहुत संभावना थी और यह विश्वास था कि यह राज्य तेज़ी के साथ विकास करेगा। जब झारखंड राज्य बना, तो यह कहा गया कि सोना झारखंड में चला गया और बालू बिहार में रह गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि झारखंड का सोना लूटा जा रहा है और झारखंड का विकास रुक गया है। अभी मैडम रिबैलो इससे पहले बोल रही थीं। मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना। उनके भाषण से ऐसा लगा कि जब से झारखंड राज्य बना है, तब से वह लगातार विकास कर रहा है और विकास की दौड़ में देश के पैमाने पर वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति दूसरी है। आज झारखंड नक्सलियों और अपराधियों के कब्ज़े में है और उसका प्रमुख कारण है कि झारखंड राज्य की जब नींव पड़ी और इसमें जो राजनीतिक सत्ता रही, उसका जो बार-बार परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्रियों या सरकारों का जो कार्यकाल रहा, वह छोटा रहा, राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसके कारण आज झारखंड बहुत पीछे जा रहा है।

सर, आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी ने अभी नरेगा का ज़िक्र किया। यह सही है और मैं उनकी बातों से पूर्णतः अपने को सम्बद्ध करता हूं कि झारखंड राज्य में चाहे जो कारण रहे हों, चाहे राजनीतिक अस्थिरता रही हो और चाहे सरकारों की अल्प उम्र रही हो, झारखंड में नरेगा का सिस्टम पूरी तरह से flop है। आज भी झारखंड में, जहां अत्यधिक गरीबी है, 70 परसेंट लोग गरीब हैं। वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, रोगों से लड़ने के लिए वहां न डॉक्टर हैं, न दवाएं हैं। यह सही है कि नरेगा एक माध्यम था कि वहां जो गरीब लोग थे, जिनका पलायन देश के दूसरे राज्यों में होता है, नरेगा ने अगर सही ढंग से वहां काम किया होता, तो उस पलायन को रोका जा सकता था। रवि शंकर प्रसाद जी ने सही कहा कि नरेगा का पूरा का पूरा सिस्टम झारखंड में चाहे जिस कारण से हो, आज फेल हो गया है। वहां पर आज

मशीनों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से या बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से नरेगा में काम करवाया जा रहा है और नरेगा के धन को लूटने का काम किया जा रहा है। नरेगा की जो भावना थी और जिस भावना से उसको लागू किया गया था, वह वहां एकदम टूट रही है और उसमें खुलेआम लूट हो रही है। आज Maoist जैसे संगठन ने पूरे झारखंड को एक तरह से प्रभावित कर लिया है, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर लिया है। झारखंड के लोगों का सपना था कि जल, जंगल और ज़मीन पर उनका कब्ज़ा रहेगा, गरीबी दूर होगी, झारखंड का विकास होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी लेकिन आज झारखंड के बाहर के लोगों ने झारखंड की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। आज वहां की आदिवासी ज़मीनों को बाहर के लोग खरीद रहे हैं।

सर, आज झारखंड का एक प्रमुख मुद्दा domicile का भी है। Domicile नीति में स्थानीय लोगों के विकास और नौकरियों के संबंध में विशेष भागीदारी की बात है। बिना संरक्षण के आदिवासियों का विकास संभव नहीं हो सकता और न ही उनकी संस्कृति को बचाया जा सकता है। आदिवासियों को सरकार से संरक्षण ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

(3Q/GS पर क्रमश:)

GS-PK/5.10/3Q

श्री आर0सी0 सिंह (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, मैं झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 और झारखंड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 के ऊपर अपनी बात रख रहा हूं। मैं इनका समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। झारखंड राज्य का गठन 9 साल पहले हुआ और 9 साल में 8 सरकारें वहां पर बनीं। किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जो वर्तमान राज्यपाल महोदय की सरकार वहां पर चल रही है, इसके लिए उन्होंने सौ दिन में पौने दो सौ काम करने लक्ष्य रखा था । झारखंड सरकार ने 34 विभागों के 178 लक्ष्य तय किए थे, जिनमें 1,700 गांवों में बिजली, 16 लाख बीपीएल घरों में बिजली कनेक्शन और मैं बिजली के बारे में आपको बताता हूं कि पतरातु थर्मल पावर प्लांट को इम्प्रूव करने की बात थी, लेकिन 40 मेगावाट विद्युत और कम हो गई

है। ये कहां से विद्युत दे पाएंगे, इन्होंने इसका लक्ष्य रखा था। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो अधिनियम, "नरेगा" के माध्यम से 200 करोड़ रुपये खर्च करके 122.7 लाख लोगों को रोजगार की गारंटी करवाना था। जल संसाधन का विकास करना, 100 दिनों में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करना, नदी पर बांध बांधना, 1028320 नलकूपों को ठीक करवाना, जो वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। नीलाम्बर, पीताम्बर और कोल्हन विश्व विद्यालय का ढांचा ठीक करना, ये सारे के सारे लक्ष्य कागज पर ही रह गए, पैसे खर्च किए गए और दोनों हाथों से लूट की गई ।

सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आया राम गया राम की राजनीति श्री भजन लाल जी ने शुरू की थी, लेकिन मधु कोड़ा जी ने उसको फेल कर दिया। कहते हैं कि निर्दलीय विधायक या जो कोई भी होते हैं, ये सारे लोग सदलीय को समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को भी समर्थन देने के लिए मजबूर कर दिया और उनके पीछे हाथ बांधकर समर्थन देने के लिए दूसरे दल भी खड़े हो गए, जिनका रिकार्ड आज शायद इतिहास में दर्ज हो गया है और ये विश्व रिकार्ड कायम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों ने बीपीएल परिवारों से 16 करोड़ रुपये घूस में उगाह लिए। पूर्व मंत्री चन्द्रप्रकाश के एक आप्त सचिव के पास से निगरानी विभाग को 13 करोड़ रुपये के फिक्सड डिपॉजिट के दस्तावेज मिले हैं और इसमें मधु कोड़ा जी की बात क्या कहनी है, वह तो पूरी दुनिया में उजागर हो गए हैं। सर, वहां पर बाहर से पूंजी आ रही है और झारखंडवासियों को बेदखल किया जा रहा है। वहां पर विकास योजनाओं का अधूरापन अब भी है। उनका सपना था कि जल, जंगल, जमीन पर उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन वहां पर जंगल छीज चुके हैं, नदियां सूख चुकी हैं, पहाड़ छिन चुके हैं, गांव उजड़ रहे हैं और शहर नासूर की तरफ से फैल रहे हैं। झारखंड का आंदोलन राजनैतिक कम और अपनी संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। समाज में अभी भी प्रतिरोध शक्ति बची हुई है। झारखंड अपनी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है।

सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महान विरसां मुण्डा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे लोग आज भी वहां मौजूद हैं, जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहीं नाम दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। सर, हम जानते हैं कि जो आवंटन होता है, वह

पूरा खर्च नहीं होता है। जैसे कृषि विभाग में 2001-02 में जो आवंटन हुआ था, उसका 25 प्रतिशत ही खर्च हुआ। वर्ष 2004-05 में जो आवंटन हुआ था, उसका 33 प्रतिशत खर्च हुआ और 2006-07 में केवल 24 प्रतिशत खर्च हुआ। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में 2001-02 में 34 प्रतिशत खर्च हुआ, 2004-05 में 18 प्रतिशत खर्च हुआ और 2006-07 में 54 प्रतिशत खर्च हुआ। ग्रामीण विकास के लिए जो यहां से आवंटन किया गया था, उसका 2001-02 में 35 प्रतिशत खर्च हुआ, 2004-05 में 60 प्रतिशत खर्च हुआ और 2006-07 में 59 प्रतिशत खर्च हुआ। कल्याण विभाग के लिए जो आवंटन हुआ, उसमें से 2001-02 में 25 प्रतिशत खर्च हुआ, 2004-05 में 27 प्रतिशत खर्च हुआ और 2006-07 में 28 प्रतिशत खर्च हुआ। जिस रेश्यो से धन आवंटित किया जाता है, वह आम लोगों पर खर्च नहीं होता है।

(3आर पर जारी)

-PK/PB/LP/3r/5.15

श्री आर.सी.सिंह (क्रमागत) : वह जैसे का तैसा पड़ा रहता है। जो धन दिया जाता है,उसका समुचित उपयोग हो, इसकी एक व्यवस्था करनी चाहिए। अंततः मैंने कहा कि वहां उल गुलाम की शक्ति अभी भी बची हुई है और जब लोग मैदान में आएंगे तो अवस्था खराब हो सकती है। आप चाहे किसी भी आंदोलन का नाम दे दीजिए, वह उचित नहीं होगा, इसलिए उनके संपूर्ण विकास की बात कही जाए। जो धन की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री मंगल किसन : उपसभापति जी।

श्री उपसभापति : आप बात करेंगे? आपने विदड्रा कर लिया है। आप पहले बात कह चुके हैं।..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभापति जी, वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और पैसे का खर्च नहीं हुआ है, उसके विरोध में हम मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनेंगे, इसलिए हम सदन से बहिष्कार कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)..(व्यवधान)..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Mr. Deputy Chairman, Sir, five hon. Members have participated in the discussion on the Supplementary Budget for the State of Jharkhand and also on the Bill to increase the size of the Jharkhand Contingency Fund from Rs.150 crores to Rs. 500 crores. I thank them all for their valuable suggestions and contribution. Some of them have also shown their concern.

Sir, before coming to the specific issues, I would like to inform the House that the State Government has sought Supplementary Grants to the tune of Rs.1,074.03 crores, out of which, Rs.48 lakh is charged. The Non-Plan Demand is Rs.412.30 crores; of this, Rs.300 crores is to combat drought situation which is prevalent in all the 24 districts of the State; the other major components being election, roads and salary of the Education Department. The Plan Demand is for Rs.661.73 crores, out of which Rs.649 crores is for the State Plan and the remaining Rs.61.24 crores relates to the Central Schemes. The State Plan proposals in the Supplementary Budget are for railway projects, power sub-stations, *Mukhya Mantri Gram Setu Yojana*, *Swarna Jayanti Gram Swaraj Yojana*, etc. The Plan Demand is not creating any extra burden for the State. The amount is being obtained from surrenders and reallocations. For the Non-Plan also, Rs.300 crores is from the Calamity Fund and Rs.40.61 crores is from the State share of the University grant. There is a net burden of only Rs.71.69 crores on the State Exchequer to meet the Non-Plan commitments.

Sir, the Jharkhand Contingency Act entails the State to Rs.150 crores Contingency Fund and it is being enhanced to Rs.500 crores. Sir,

Ravi Shankarji has gone. He made certain observations. He said that it is not necessary to come to this House for this Contingency Fund. He is a lawyer. This is a legal requirement. Since the Parliament was not in Session and the circumstances, which were existing, rendered it necessary for a temporary enhancement of the ceiling of the Jharkhand Contingency Fund from Rs.150 crores to Rs.500 in the financial year. This Ordinance was issued, and as soon as the next Parliament Session began, it was our duty -- it is the constitutional obligation -- to bring it here, and there is no legal infirmity in it.

(Contd. by 3s/SKC)

3s/5.20/skc

SHRI NAMO NARAIN MEENA (Contd.): Again, Sir, some of them had mentioned that elections are on and asked why we had come up with this. Sir, we got permission from the Election Commission of India and they have given the permission. With their permission, we have brought these Supplementary Demands for Grants before the House.

Sir, some questions were raised about the NREGA. Under the NREGA, we had given job cards to 35 lakh households; 87 per cent households are covered. Again, 89 per cent card holders have bank accounts. 1,29,000 schemes were started and almost 57 per cent of the money which was allocated or earmarked for NREGA has been spent. I do not wish to go into details as to what action has been taken, but I would like to mention two or three points here -- free food grains are being made available to primitive tribes; BPL families and *Antyodaya* families are being given 34 kg of wheat and rice free of cost every

month, and Rs.193 crore have been reallocated for the Energy Department.

Sir, as the Members are aware, State Assembly elections are underway in Jharkhand. Four of the five phases have already been completed. We all look forward to a popular Government in the State, which will take forward the developmental works, so that the targets of the financial year are met. I do agree that less money was spent; only 30 per cent of the Plan money was spent, the reason being that initially, in April, May and June, there was an *acharsamhita*, Code of Conduct. Again, because of these elections, there is a code of conduct and so, the entire money could not be spent. Hopefully, in the remaining months the entire amount which is earmarked for the State will be spent.

Sir, with these words, I commend the Supplementary Demands and the Jharkhand Contingency Fund Bills to the House.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall first put the motion for consideration of The Jharkhand Appropriation (No. 3) Bill, 2009 to vote. The question is:

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2- 3 and the Schedule were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put The Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill, 2009 to vote. The question is:

That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

(Followed by gsp/3t)

-skc-GSP-SCH-3T-5.25

THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2009

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009. Mr. Minister, Prof. K.V. Thomas.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K. V. THOMAS): Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955 and to make provisions for validation of certain orders issued by the Central Government determining the price of levy sugar and actions taken under those orders and for matters connected therewith, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Arun Jaitley, not here. Shri Kalraj Mishra.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, अभी जो विधेयक लाया गया है, जो पहले अध्यादेश के रूप में घोषित किया गया था, आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009, इसमें जिस प्रकार के संशोधन हैं, उन संशोधनों को देखने के बाद यह लगता है कि भारत के गन्ना उत्पादक किसानों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार किया गया है और इस प्रकार की स्थिति निर्माण की गई है, जिससे लगता है कि सरकार पूर्ण रूप से मिल मालिकों को हर तरह से समर्थन देने के पक्ष में है। गन्ना उत्पादक किसान का हित जितना भी नुकसान की तरफ हो, उसकी चिन्ता नहीं की गई है, लेकिन मिल मालिक को फायदा हो, इस दिशा में प्रयत्न है।

पूरे विधेयक में इसी बात का जोर है, भले ही प्रारम्भ में, उसकी पृष्ठभूमि में विभिन्न मुकदमों का ज़िक्र किया गया है और मुकदमों के माध्यम से ही यह जताने की कोशिश की गई है कि जो लेवी शुगर है, उसका जो Statutory Minimum Price है, इसको इस ढंग से सुनिश्चित किया जाए, जिसके कारण मिल मालिक को फायदा हो। गन्ना उत्पादक किसान की इसमें पूरे तौर पर उपेक्षा की गई है। अध्यादेश के माध्यम से देश के सामने जो बात रखी गई है और आज जो कानून बनाने की बात कही जा रही है, उसमें पूरे देश में fair and remunerative price एक ही होगी, इस प्रकार की बात कही गई और जो भी इस संशोधन के अन्तर्गत धारा थी, जिसके आधार पर State Advisory Price भी सुनिश्चित करेगा और जो अन्तर होगा, SMP और SAP में, उस अन्तर को मिल मालिक और स्टेट, दोनों मिल कर पूरा करेंगे।

(3यू/पीएसवी पर जारी)

-SCH/PSV-SK/3U/5.30

श्री कलराज मिश्र(क्रमागत): इसमें परिवर्तन यह किया गया है कि पूरे देश में एक ही प्राइस होगी। अगर कोई राज्य सरकार इसे बढ़ाती है, तो इस अन्तर को उस राज्य सरकार को पूरा करना पड़ेगा। मान्यवर, इसके कारण किसानों का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि गन्ने की उत्पादकता देश में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की है। वहाँ की जलवायु, वहाँ के कृषि-सम्बन्धी संसाधन, वहाँ के फसल उत्पादन का सुनिश्चित अवसर, अवधि कब हो, आदि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो पूरे देश में अलग-अलग स्वरूप स्थापित करती हैं। इसलिए सब जगह समान रूप से गन्ने का उत्पादन होगा, ऐसा नहीं रहता है और उसी के आधार पर गन्ना मिलों में जब गन्ना जाता है तब उसकी रिकवरी जो होती है, वह अलग-अलग होती है। अभी प्रणब बाबू अपने एक जवाब में बोल रहे थे, तब कह रहे थे कि जहाँ कहीं 8.5 परसेंट की भी रिकवरी है, उसको भी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है और कहीं 9.5 परसेंट और उससे ज्यादा की रिकवरी है, जैसे 10 परसेंट या 11 परसेंट की रिकवरी है। वह गन्ना की गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए जो ज्यादा गुणवत्ता वाले गन्ना को विस्तृत रूप से करने वाले क्षेत्र हैं, कृषि-क्षेत्र हैं, वहाँ तो उन किसानों को लाभ होगा, लेकिन

जहाँ इस प्रकार की गुणवत्ता नहीं है, वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार का क्षेत्र हो, जहाँ रिकवरी बहुत कम है, वहाँ बड़ा नुकसान हो जाएगा तथा वहाँ का किसान सर्वाधिक परेशान होगा। मुझे लगता है कि इस संशोधन में इस बात का गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है।

महोदय, आदरणीय पवार जी बड़े योग्य मंत्री हैं। किसानों के बारे में उनकी एक अपनी दृष्टि है। पूरे देश-भर में कृषि उत्पादन क्षेत्र कौन-कौन-से हैं, गन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन-कौन-से हैं, उनकी जलवायु कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हर चीज के बारे में उनको जानकारी है। लेकिन, जानकारी होने के बावजूद भी यह जो अमेंडमेंट किया गया है, यह बड़ा खतरनाक amendment है। इसमें इन्होंने जो कहा कि खंड 3 बी के रूप में इसमें जोड़ा जाएगा। जो खंड तीन में है, जिसमें जहाँ SMP तय की जाएगी, वहीं यह भी प्रावधान है कि अलग से, SAP के हिसाब से भी, प्राइस सुनिश्चित की जा सकती है। स्टेट एडवाइजरी प्राइस, गन्ना में जो लागत लगती है, वह और लागत के साथ-ही-साथ किसानों को जो लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकता है, उसको ध्यान में रख कर SAP तय की जाती है। SMP जो तय की जाती है, उसमें जो लेवी सुगर है, उस लेवी सुगर का कम-से-कम कितना दाम सुनिश्चित किया जाए, उसका यह भी भाव रहता है कि उपभोक्ता को सस्ती दर पर चीनी मिले तथा चीनी मिल मालिकों को नुकसान भी न होने पाए। इसीलिए लेवी सुगर के आधार पर SMP तय करते हैं। गन्ना उत्पादन की लागत और किसानों को कैसे लाभ प्रदान हो सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए SAP तय होती है। इसलिए SMP और SAP में बहुत फर्क होता है। उत्तर प्रदेश में हम SAP तय करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि SAP और SMP का जो अंतर है, उसका कुछ वर्षों का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। उससे यह बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों तय करते हैं। 2001-2002 में SAP 95 रुपए थी और केन्द्र सरकार ने 62.05 रुपए तय किया था।

(3डब्ल्यू/डी0एस0 पर क्रमश:)

श्री कलराज मिश्र (क्रमागत) : इसमें 32.95 का अंतर है। वर्ष 2002-03 में एसएपी 95, एसएमपी 64.50 है और अंतर 30.50 है। इसी ढंग से 2004-05 में एसएपी 107, एसएमपी 74.50, 2005-06 में 115 एसएपी और एसएमपी 79.50, 2006-07 में एसएपी 125 और एसएमपी 80.25, 2007-08 में एसएपी 125 और एसएमपी 81.18, 2008-09 में एसएपी 140 और एसएमपी 81.18 और 2009-10 में 165 एसएपी और एसएमपी 107.76 था, लेकिन इसी 2009-10 में यह जो अध्यादेश के माध्यम से 129.84 की घोषणा की गई। अब 129.84 पूरे देश के लिए - और अगर इसमें एसएपी तय करते हैं तो राज्य सरकार को अलग से देना पड़ेगा। राज्य सरकार देने में सक्षम नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि उत्तर प्रदेश का किसान परेशान होगा। उसे गन्ने का सही दाम प्राप्त नहीं हो पाएगा और यह हालत होगी कि किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसीलिए क्लॉज़ 3 में 3(बी) करके जोड़ा जा रहा है, जिसमें साफ-साफ यह कहा गया है कि इसमें एसएपी तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। आप कोई additional price तय नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्राइस तय करते हैं तो यह उनको खुद देना पड़ेगा, राज्य को खुद देना पड़ेगा। इन्होंने 5(ए), जो 1974 के अमेंडमेंट के अंतर्गत था, जिसके अंदर प्रावधान था कि एसएपी तय की जाएगी और स्टेट-मिल मालिक, ये मिलकर गन्ना किसानों को दाम देंगे। उस फायदे को भी समाप्त कर दिया गया कि फायदे उसमें नहीं रहेंगे। इसलिए दो धाराओं को, एक क्लॉज़ का एडिशन और दूसरे क्लॉज़ का समापन, ये दोनो चीजें मिल कर गन्ना किसानों के लिए जबर्दस्त समस्या पैदा कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि चारों तरफ आंदोलन प्रारंभ हो गए। इधर, जिस तरीके से लेवी शुगर के आधार पर एसएमपी तय हो रही है, उसमें जिस ढंग से प्राइस राइज़ हुई है, शुगर की प्राइस राइज़ हुई है, अगर उसके आधार पर भी तय किया जाए, तब भी उसके अनुरूप गन्ना किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। अब चालीस रुपये किलो चीनी मिल रही है और गन्ना किसान को 129 रुपया आप देंगे! इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो यह गन्ना किसानों के साथ ज्यादती है। इतना ही नहीं, यह जो विधेयक आया है, अगर इसके खिलाफ आप कहीं किसी प्रकार का केस करना चाहें तो इस विधेयक में यह साफ है कि आप वह नहीं कर सकते हैं।

यह नहीं सुना जाएगा। कोई बात, किसी भी प्रकार का केस आप नहीं कर सकते हैं। मूल अधिनियिम की धारा 3 की उपधारा (3ग) के अधीन जारी किए गए विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन की गई कार्रवाई आदि का विधिमान्यकरण और उसमें जितना भी है, उसमें इन्होंने कहा है कि "किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई दावा या चुनौती इस आधार पर ग्रहण नहीं की जाएगी कि केन्द्रीय सरकार ने किसी विनिर्दिष्ट आदेश के अधीन उद्ग्रहीत चीनी की कीमत के अवधारण में मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3ग) में विनिर्दिष्ट कारकों में से किसी कारक पर विचार नहीं किया था।"

यह साफ तौर पर किसानों के साथ जबर्दस्त ज्यादती की जा रही है और यह ऐसे समय में की जा रही है, जब चीनी की आवश्यकता है। यह ऐसे समय में की जा रही है जब स्वयं कृषि मंत्री ने इस बात को बताया है कि चीनी की मांग 230 लाख टन है और चीनी का उत्पादन 160 लाख टन है। (3एक्स/एकेए पर क्रमशः)

aka-vkk/3x/5:40

श्री कलराज मिश्र (क्रमागत) : जिसमें 70 लाख टन का अंतर पड़ता है। इस समय डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उत्पादन कम है। जब पहले ही उत्पादन कम है और ऐसी स्थिति में जो यह कानून आप ला रहे हैं, तो फिर गन्ना किसान गन्ना बोने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो गन्ना किसानों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें 14.9 परसैंट गन्ने का उत्पादन कम हुआ है और गन्ना खेत में भी अब गन्ना किसान गन्ना बोने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे उसमें दूसरी फसल ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो गन्ना उत्पादन का क्षेत्र भी कम हो गया है, गन्ना उत्पादन भी कम हो रहा है और इस कानून के बन जाने के बाद तो बहुत निराशाजनक स्थिति निर्मित हो जाएगी क्योंकि गन्ना किसान गन्ना बोने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और उसके स्थान पर किसी दूसरी फसल के उत्पादन के लिए वे प्रयत्नशील होंगे। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो आगे चलकर बड़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का वैसे ही बकाया पड़ा है, 1500 करोड़ रुपए वैसे ही बकाया हैं और पिछली बार SMP और SAP का जो अंतर था, उस अंतर को भी नहीं दिया गया। यह सब मिलाकर

और इसका जो इंटरेस्ट बनता है, इन सबको मिलाकर 4000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का एरियर है। गन्ना किसान अनुभव करने लगे हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे चलकर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए, मैं चाहूंगा कि गन्ना किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रकार के जो कानून आ रहे हैं, जिनसे किसानों के बीच में संदेश जा रहा है कि यह जो संशोधन किया जा रहा है, यह मिल-मालिकों और गन्ना मिलों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, उनसे बचा जाए। पिछली बार भी यह अनुभव हुआ था कि गन्ना मिलों को पूरा गन्ना नहीं मिल पाया था और इस बार तो पूरा लगने लगा है कि किसान गन्ना मिलों को गन्ना नहीं दे रहे हैं, खेत में जला रहे हैं, लेकिन मिलों को गन्ना नहीं दे रहे हैं। क्रेशर के पास जा रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वहां गन्ना पेला जा रहा है, लेकिन मिलों को गन्ना नहीं दे रहे। इस संशोधन के कारण यह बड़ी दुर्दयी और विकट स्थिति का निर्माण हुआ है। मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि जो SAP थी, उसमें मिल मालिक और राज्य सरकार दोनों आपस में सामंजस्य बैठाते हुए गन्ना किसानों का पेमेंट करते थे, उसमें किसी तरह का झगड़ा नहीं होता था। न्यायालय में जाते थे, न्यायालय ने भी फैसला किया, न्यायालय ने भी स्टेट एडवाइज़री प्राइस को जस्टिफाई किया और उसके अनुसार पेमेंट भी होता रहा है। यह जो संशोधन लाया जा रहा है और संशोधन के जरिए कहने की जो कोशिश की जा रही है कि मिल-मालिक और गन्ना किसानों में सामंजस्य बैठेगा, झगड़े कम होंगे, बल्कि इससे तो और केसिज़ आगे बढ़ेंगे, इसके कारण विवाद और तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा और हालत ऐसी पैदा हो जाएगी कि गन्ने के लिए लोग तरसने लगेंगे और जिस तरह से चीनी की स्थिति का निर्माण हो रहा है, चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ उसका क्षरण होता चला जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो 3(b) क्लाज़ इसमें डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार अपना कोई मूल्य, गन्ना किसानों की लागत के आधार पर, तय करने की सोचे, वह नहीं तय कर पाए, इसको किया जा रहा है और 5(a) के माध्यम से जो यह अधिकार प्रदान किया गया है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार एक प्रकार का परामर्शदात्री मूल्य निर्धारित कर सकती है, राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा।

('3y/nb' पर जारी)

NB/MKS/3Y/5.45

श्री कलराज मिश्र (क्रमागत) : जब राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, तो गन्ने की दुर्दशा होगी। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और विचार करके इसको समाप्त करे, यही मैं आपके माध्यम से इस सदन में आग्रह करता हूं। मंत्री जी इस पर विचार करें और पूरे देश के किसानों को यह संदेश दें कि यह सरकार मिल मालिकों की नहीं है, यह सरकार गन्ना किसानों की है। अगर वे यह संदेश नहीं दे सकते हैं, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि यह सरकार गन्ना किसानों के जबर्दस्त विरोधी के रूप में काम कर रही है, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Kalraj Mishraji. Now, Shri Sudarsana Natchiappan

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support this Bill, but, at the same time, I have to bring forth the matter behind it.

Sir, as it is, we have helped the sugar mill owners. Many of the mills are owned by the cooperative sector in Maharashtra, Tamil Nadu and other places, but, basically, they are run by many big industrialists. They are having the benefit of bringing raw sugar from foreign countries. Many other benefits have also been given by various Governments. Then, they sell it in the open market. We brought another amendment to the Sugar Act for giving them interest-free loans. About five per cent interest was borne by the Government of India and seven per cent was taken away from the Sugar Fund. Thus, the sugar mill owners are getting funds to repay it to the agriculturists. Without any interest they are getting the capital. Now, we are giving them more opportunities to

have a good price when they sell it. There is no doubt, Sir, that the industry has to be protected because we are party to the various nearby countries, ASEAN countries and other countries. We are having an agreement so that the sugar supply could come from the South East Asian countries which are very much dependent on sugarcane. The market will be flooded with sugar and there will not be any deficit at all. But, at the same time, who are the sufferers actually? The preamble is like this. One part of it is the sugarcane growers; another one is the manufacturers of sugar, and, then, the consumers. Are we protecting the interest of these agriculturists and consumers? This is the question we have to answer. Very often, we are missing that. Already, we have made it plus twenty-five paise, per kilo, for the consumer to pay because we are bearing the interest charges paid to the manufacturers. We pay back to the agriculturists. The agriculturists are already suffering even though under the Essential Commodities Act, the price of sugar is fixed on the basis of by-products, the molasses and alcohol. How are they using it for producing electricity? These are all the calculations made according to the rules made in favour of the sugarcane growers. But to which extent that price is fixed is doubtful. We are not taking into consideration that one unit of electricity that the manufacturers of the sugar factories are selling at Rs.15/-. They can take away the other wastage, and through other process, they can produce electricity. But to that extent they were paying to the sugarcane growers. Therefore, the ultimate sufferers are sugarcane growers. We have to protect the interests of these growers because we know that the agriculturists are not getting proper protection in various fields. Even the banks which are

instructed to give more loans to the agriculturists are not giving. They are only dependent on the sugar factories.

(Contd. by TMV/3Z)

-MKS-TMV-NB/3Z/5.50

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (CONTD.): They are giving a lot of money to the sugar factories. But they are not paying the interest properly. Every burden is shifted to the sugarcane growers. Therefore, if you compare the price difference between what the sugar producers are getting and what the actual sugarcane growers are getting, the price which is coming to the hands of the sugarcane growers is less. On this aspect, there was an agitation throughout the country, especially, in Tamil Nadu and Uttar Pradesh. There was a huge agitation by the agriculturists and the sugarcane growers. So, they should also be heard and made a party to it, when you decide the price. But now we are lessening the burden of the State Governments because the agitation was in a way compromised by saying that the payment made by the State Government will be compensated. Therefore, there is no need for any worry on the part of the State Governments. But, at the same time, we have to worry about the consumers, as also the sugarcane growers. I would like to request the hon. Minister and the Government to think about this aspect and to protect the interests of these people who do not have any powerful lobby like the sugar manufacturers. They have a very strong lobby. They have got all scientific methods for analysing the issues and to fix the prices. They get every help on every aspect. But the poor agriculturists and the poor consumers do not have such a lobby. It is reflected when we go for seeking votes. Therefore, we have

to think about that. In a democratic country we have to consider all the three sectors together and fix the price.

Anyhow, I support this Bill. But I would like to request the Government to call all the three sectors, sit together and decide the price accordingly. Thank you. (Ends)

SHRI MATILAL SARKAR (TRIPURA): Sir, while speaking on this Bill which has come before us on account of the Ordinance, I would like to place some observations on the Bill. This is the Bill which had rocked this House and the other House in the beginning of the session. This is the Ordinance against which the farmers were agitating. When I make these references, definitely there is something wrong in the Ordinance.

Sir, I would like to highlight some of the points. In the Ordinance the SAP was replaced by the FRP ignoring the existence of SAP, that is, the State Advised Price. The State Advised Price was ignored. Moreover, it is stated that if the State Advised Price, that is, SAP, exceeds the FRP, the difference will be borne by the State, not by the mill owners. Thirdly, under the FRP, the sugarcane price was fixed at a very low rate. It was Rs.107 per quintal and now it is Rs.130 per quintal. It is far lower than the prevalent rate in the market. It is lower than the market rate. The reasons why the promulgation of this Ordinance was objected by the farmers and the State Governments are, firstly, there is a change in the policy of the Government. There is a change in the sugar policy. When a change is made, generally, it is customary, it is the convention, to consult the relevant sections. The

relevant sections mean, the Parliament, the State Government and the farmers' organisation. None of them was consulted.

(Contd. by 4A/VK)

VK/4A/5.55

SHRI MATILAL SARKAR (CONTD): It was not discussed with anybody. Nobody was invited to give his suggestions and opinion. I think there is something wrong in computing the SMP. In this Bill, some formula has been given for making payment to the producer. But I do not find in the Bill how the FRP will be calculated. Previously, there was no proper system for computing the SMP and now also there is no criterion for assessing the FRP. As I stated earlier, the Government wants to help the mill owners. The difference between the SAP and the FRP would be borne by the State Government, not by the mill owners. But the sugarcane farmers have not been taken into account. Their interest has not been taken care of while formulating the FRP and while deciding about paying the difference between the FRP and the SMP. It is due to the policy of the Government that the sugarcane farmers are withdrawing from the fields. I would like to quote some figures. In 2006-07, the production was 282 lakh tonnes and after two years, in 2008-09, the production was 195 lakh tonnes. It has gone down drastically. What are we doing? Why are the sugarcane farmers averse to sugarcane cultivation? This needs to be looked into. The reason is, when they sell the sugarcane produce to the mill owners, they do not get the payment on time. There is a rule that within 14 days they should get the payment. But not to speak of 14 days, they do not get the payment for months together. I would like to quote some figures.

Till 31st March, 2009, Rs. 1,225 crores was the arrear towards sugarcane farmers. It is nearly seven to eight per cent of the total cost. Nobody is bothered about the farmers who are not getting their dues. Nobody from the Government side is caring about them. The sugarcane farmers are not getting any support. So they are withdrawing from the fields. What is the acreage? How much is the area under sugarcane cultivation? It has come down from 37 lakh hectares to 25 lakh hectares. It is very serious that the sugarcane farmers are switching over to other cultivations because they are not getting their dues.

Lastly, our aim is to achieve self-dependence and self-reliance in foodgrains. One of the items is sugarcane. If we think deeply, if we study deeply, we can see that we are not successful in this area. We are already importing pulses, edible oil and wheat. So far as paddy is concerned, we have attained some sort of self-sufficiency. Now we are importing rice also.

(Contd. by 4B)

RG/6.00/4B

SHRI MATILAL SARKAR (contd.): And, in the sector of sugar, we had the capacity to export. We were the second largest producer of sugar in the world; and to export it. But, now, this time, we have come in the list of importers. We are importing sugar. So, what freedom are we attaining? The cultivators, whether in respect of wheat, pulses, rice or sugar, in every corner, they are in a fix. They are perplexed. They give their share of produce, but they do not get remunerative prices. Finally, I would like to say that trying to push the country from a position of self-dependence to the position of dependence on others will not be

tolerated by the patriotic people of the country. People want justice; farmers want justice. The bias towards the mill owners should stop, and the bias towards the sugarcane growers should be established. Otherwise, the people will come to the streets. They have no other option left. Sir, I have seen in newspapers that the Prime Minister himself has intervened in the matter. I do not know what intervention he has made. I would like to hear from the hon. Minister as to how the Government is going to solve the woes of the sugarcane farmers. If this is not done, I don't think it is going to be accepted by anyone. With these words, I conclude, Sir.

(Ends)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, this Amendment to the Essential Commodities Act was brought by an Ordinance, and the ostensible reason, as to why the Government brought it by an Ordinance, is that the Government felt the Validation Act was required, because of the judgement of the Supreme Court, some huge arrears had to be paid to the sugar mills. The fact of the matter was that the Supreme Court Judgement really pertained to only the four or five petitioners before the Court. It did not pertain to the entire industry. And the judgement, specifically, said that it pertained to those people only; the others have not come over. But there was an apprehension that the Government had was that the others might approach some other Court. Therefore, a figure of about Rs.14,000 crores was being mentioned, which the Government will have to pay. Now, to get over that liability, this Ordinance was promulgated, which has now come up before us. But, along with this Ordinance, after a

gap of just two or three days, the Sugarcane Control Order was also amended. Now, the Amendment of the Sugarcane Control Order clearly showed that the intention of the Government was otherwise. The Amendment to the Sugarcane Control Order did not have anything to do with the arrears of Rs.14,000 crores. But it only related to somehow eliminating the primacy of the State Advised Price, which the State Governments have been making, to ensure that the farmers' sugarcane is bought by the mills at some remunerative prices. Now, there was a protest in this House, and there was consultation. The Government agreed to re-look into the matter. I hope and we want an assurance from the hon. Minister that that part of the intention of the Government, which was brought about, eliminating the primacy of the State Advised Price, will be completely gone for good, that there will be no effort, either direct or indirect, to bring that back. Sir, having said this, sugar itself, and, sugarcane has a very important component in the Indian economy. We are the second largest growers of sugarcane after Brazil. About three per cent of the cultivated area in India is sugarcane, and in terms of the number of farmers, it is almost 50 million people who are involved as far as sugarcane cultivation is concerned. We manufacture, and also export, and domestically consume almost 15 per cent of the world's sugar.

(Continued by 4C)

4c/6.05/ks

SHRI ARUN JAITLEY (contd.): Our total investment in the sugar industry is about Rs.50,000 crores. Our annual turn over is about Rs.27,000 crores. And this includes the payment that is made to

farmers, etc. Now, there has been a big conflict -- which was apparent when this amendment came, and also when the Sugarcane Control Order came -- pertaining to the jurisdiction of the Central Government and the State Governments. There are about 20 States which have sugar mills. We have approximately, I am told, 516 sugar mills. Some are in the cooperative sector; some are in the private sector. Most of these mills are spread over 7-8 States, though 20 States have different sugarcane cultivation.

Now, sugarcane is an item which falls in the Concurrent List. It comes under List III, Entry 33. The Central Government has a power under the Essential Commodities Act; earlier, it was licensed and you required a license under the IDR Act for setting up a sugar mill; that licensing was waived off in 1998 and you didn't require a license thereafter.

But sugar remains partly controlled for two reasons. The first reason is that sugar is also distributed under the Public Distribution System to the weaker sections of the society. Therefore, the Essential Commodities Act implies -- and that is this amendment -- that the sugar, which State Governments have to purchase for distribution to poor people through the PDS, is to be priced by the Central Government and the States will all purchase it at that price. Now, that sugar, since it is meant for the poor people, obviously, has to be very reasonably priced; there cannot be a profit element in that. Therefore, we had a Statutory Minimum Price of sugarcane which the Central Government used to notify, which is the SMP and, on the basis of that SMP, the Central Government would fix the sugar prices, the States

would buy sugar, which is called the Levy Sugar, from the mills for distribution through the PDS and the rest of the sugar used to be sold in the open market. Now, a difficulty has arisen because it is on the Concurrent List and there is no licensing now. There is a policy that every sugar mill has an area of 15 kilometres around it, which is called its Cane Area. That Cane Area has to be fixed by the State Governments or the Cane Commissioner of every State. Therefore, you have to have a reasonable distance. The second part of control comes in the sugar industry because this Cane Area is fixed by the State Government; so, every mill has an interest in enriching the farmer so that he is able to produce more sugarcane, which goes to the benefit of the mill. But the difficulty now arises that the mill becomes a monopoly purchaser of the sugarcane of that farmer. So, the farmer can be pushed to distress if the mill refuses to buy sugar and if the mill refuses to pay him for the sugar because he has no other sources of selling his sugarcane since he is now bound by law to sell it only to this mill, not to anybody else. Now, it is because of this distress of the farmer that the Central Government fixes the prices under the Essential Commodities Act for the purposes of Levy Sugar alone, which is for the PDS, but State Governments separately fix a State Advised Price for the purposes of payment to the farmer because, otherwise, if the State does not fix the price, it remains a controlled commodity. Then, the mills would exploit the farmer because the farmer has no other option to sell except to the mill within whose cane area the farmer is located. Now, historically, the State Advised Price has always been 30 to 40 to 50 rupees more than the Central Government price. Now, the sugar mills

have a grievance as to why this price is higher; they feel they are being robbed of their profits. Sir, there is a good rationale behind this is a higher price. The higher price is for the reason -- and that is the error into which the Government fell when it notified the Sugarcane Control Order -- that the sugar which the State Governments buy for distribution under PDS, is pure and simple sugar; it has no other use except consumption by people. It is to be eaten by people. But from the sugarcane which a mill buys, it manufactures sugar; it manufactures *gud*; it manufactures *khandsari*; it is used for power generation; it is used for molasses; it is used for liquor distilleries; it is used for ethanol; it is used for organic chemicals. So, unlike the Central Government's Statutory Minimum Price, which is only for one purpose, that is, the sugar which is to be eaten, the State Advised Price looks at the various uses which the mills put it to and, therefore, it is higher and the farmer, therefore, will always be paid 40-50 rupees more for his produce.

(Contd. by 4d/tdb)

TDB/4D/6.10

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): Now, the mills have been agitating that 'we should not have to pay this extra'; and, therefore, they have been litigating for many years. Finally, the Supreme Court resolved this issue by saying, 'well the State-advised price is a sugarcane price for a different purpose. It can't be confused with the price fixed for the purposes of Essential Commodities Act for levy sugar, and, therefore, it is enforceable price.' The Constitution Bench of the Supreme Court by a majority opinion has decided this in favour of the State Governments, and, therefore, in favour of the farmers. Now, this entire scheme, which

the Food Ministry and the Agriculture Ministry brought out when seen collectively, seemed to upset this whole arrangement. Now, the ostensible purpose indicated was, 'suddenly we have to pay Rs.14,000 crores as arrears because the Supreme Court in another judgement has said that 'for levy sugar, don't give them statutory minimum price; statutory minimum price must have some nexus to the market price'. Sir, I am afraid, I am sorry to say that -- certainly, we can express a contrary view -- I don't think the Government pleaded its case effectively before the Supreme Court. If market price and profit are all to be read into the price of sugar which the Government has to fix for PDS distribution, then the whole purpose of the Essential Commodities Act will be defeated because then poor people will get it through the PDS system at a very high price. The whole object of the Essential Commodities Act is that the poor people must get it at a very low price. But the Supreme Court judgement curiously says, "No, look at the market price; look at the profit element; look at the various things, and then fix the sugar prices." I don't think so. Either the judgement seems to be somewhat erroneous or it was not effectively pleaded, as a result of which some Rs.14,000 crores of arrears, as what the Government now suspects, it is a liability, has come up. While we support the Government in that move -- after all it is the judgement of the Supreme Court, it is a law declared by the Supreme Court -- and we are one with the Government if the Government wants to retrospectively amend the law, change the basis of the judgement, with effect from 1974, and avoid over that liability of Rs.14,000 crores. But, we are not with the Government if in the garb of washing off this liability of Rs.14,000 crores,

it says that the State-advised price should now be eliminated. This amendment Bill did not say that. But, along with it came a Notification of amending the Sugarcane Control Order, which said, "There will be a fair and reasonable price, and if any State Government fixes a State advised price, then, the mills will not pay, but the State Government will pay." The effect of that is that no State Government will want to pay. As a result of which, the State Governments will not fix the State advised price. The mills will benefit; they will pocket the entire profit, and the mills will not pay the farmer that additional price. So, while we will be one with the Government -- why I wanted to intervene -- in this support, we want an assurance from the Government to this effect. Insofar as you want to wash off this Rs.14,000 crores liability of the mills which has been given as a result of this judgement with effect from 1974, we are one with the Government, we will support that amendment. But, we want an assurance that no effort will be made as a part of this new scheme to anyway dilute the concept of a State-advised price because that is the only relief that the sugarcane farmer today has. If that relief goes, then, the farmer will be reduced to distress and the profit of the sugar mills will keep on increasing.

With these words, Sir, we would like to have an assurance from the Government, and we will consequently support this legislation.

(Ends)

(Followed by 4e-kgg)

kgg/4e/6.15

DR. K. MALAISAMY (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much. I feel at home and very much elated for two reasons.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Because it is sugar, it is sweet!

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, sugar or sugar-coated?

DR. K. MALAISAMY: I could see Mr. Vice-Chairman, presiding over the proceedings, who has been nice, likeable and pleasant. That is one aspect.

THE VICE-CHAIRMAN: But, keep your time!

DR. K. MALAISAMY: Sir, my most important point is that I am speaking on a subject in which the farming community is interested, to which I belong. That is the most important part of it. Sir, before I come to the discussion, I was casually thinking of the farming community and made a sort of analysis on what their strength is, what their weakness is, what their opportunities are, what their stress is and what their threats are. Everybody could see that more than 60 per cent of the total population belongs to the farming community. This is the first point. Secondly, the entire country's food security depends on their contribution. Thirdly, they are in occupation being eco-friendly which the entire country, even the world at large, is very much interested. Sir, not only that, but also it is the largest segment in the voting bank.

With this background, when I look upon their weaknesses, they are manifold. They are not at all well-educated, well-informed and, as such, they are poor. In other words, they are most disorganised and ignorant of the famous mantra of Dr. Ambedkar: Organise-Educate-Agitate. They are totally ignorant of this. Another important weakness of this community is, some of my colleagues also said, that they lack licence, lobbying and employ pressure groups to get the things done.

On the weakness side, the next point is, their occupation depends on several ifs and buts, particularly depending on the vagaries of monsoon and seasonal eccentricities also; risky. On the weakness side, nextly, Sir, the demand and supply will never go together. They are not able to obtain due prices. Lastly, due to lack of infrastructure facilities, storage facilities, transport facilities, and marketing facilities, they are very much handicapped.

It all means that their threats are more than opportunities. In such a situation, when I come to the core of the Bill, after listening to the Leader of the Opposition, Shri Arun Jaitley, who was able to give the statistical data, historical background and the legal background, my job is pretty easy. I would not repeat the reasons; I am in full agreement with his appreciation of the legalities.

If you ask me whether I would support the Bill or oppose it, as far as I could see, I am willing to give conditional support. The condition which I am going to put is, if the Minister is able to give an assurance I will have no problem. On the other hand, if there is no assurance, I have to oppose it. There are two things which are mentioned by the Leader of the Opposition. Sir, without going into the details and background, I would like to know from the hon. Minister whether 5(a) of the Control Order, 1996 is going to be retained which will give two things, namely, the additional price and also the share of 50 per cent of the profit enjoyed by the manufacturer. The second point is the right of the State, on the State Advisory Price, which too is well explained by him. As far as I could see, any privilege or concession given to a person, the Government can only enhance it but cannot be withdrawn. The basic

norm any Government or authority should be the greatest happiness of the greatest number. Mr. Sudarsana Natchiappan also pointed out three sectors---agriculture sector meaning the farmer sector, the consumer sector and the manufacturer. Of all the three, if you ask me whose rights are to be protected first and foremost, I would say that it should be the farmer's. If at all there is the next choice, I would go by the consumer. Only thirdly, if possible only, the manufacturer should be protected. They know how to manage, how to get the things done.

What I would like to say is that if these two major things---retention of clause 5(a) and the State's power to fix the price---are safeguarded, then the other things are okay. In the absence of it I have to remain with the three mantras of Dr. Ambedkar. In fact, some of the organisations of the agriculturists and farmers came, met me, and briefed me. Sir, this time we are fairly organised, and we are willing to go to any extent. If any of our interest is going to be affected, we are not going to remain idle just like others. Not at all! This time we are going to wage a war. What I am trying to tell is that I am trying to give a caution to the hon. Minister that the protection of the interests of the farmers should be done at any cost failing which you are in trouble. Thank you.

(Ends)

(Followed by psv/4f)

PSV-KLS/4F/6.20

श्री गोविंदराव आदिक(महाराष्ट्र): महोदय, आपने मुझे यहाँ अपने विचार करने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं यहाँ आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सर, अगर इस संशोधन को देखा जाए, इस amendment को देखा जाए, तो मामला बहुत छोटा है, लेकिन मामला छोटा होते हुए भी उसका अर्थ बहुत बड़ा है और उसकी व्याप्ति भी बहुत बड़ी है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में यहाँ जिक्र किया है। सर्वप्रथम मैं आपकी अनुमति से इस संशोधन को समर्थन देते हुए केन्द्र सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह संशोधन करके सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसका जिक्र अभी-अभी विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने भी किया है। मामला थोड़े रकम का नहीं था, बल्कि 14 हजार करोड़ रुपए का मामला था। जो 14 हजार करोड़ रुपए सरकार की तिजोरी से private mill owners की तिजोरी में जाने थे, उनको रोकने का एक ऐतिहासिक काम इस amendment bill ने किया है। इसलिए मैं इस सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

यह अभिनंदन करते समय मैं एक और विषय के बारे में अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह जो सरकार है और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, श्री शरद पवार जी, वह खुद एक किसान हैं, एक sugar cane grower हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय किसानों के हित में किए हैं। अभी पिछले साल हमने देखा, दुनिया के इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने किया था। वह निर्णय किसानों को ऋण-मुक्त करने का था, जिसके लिए 70 हजार करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की। देश के सारे किसानों को ऋण-मुक्त करने का वादा किया और उसने वादा ही नहीं किया, उस पर अमल भी किया। इसके लिए मैं इस सरकार का खुलेआम अभिनंदन करना चाहता हूँ ...(व्यवधान)... UPA की Chairperson सोनिया गांधी जी, प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी और हमारे कृषि मंत्री, श्री शरद पवार जी, इन सभी ने मिलकर जिस इतिहास का निर्माण किया है, महोदय, इसकी कोई दूसरी मिसाल आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए मैं इनका इन दोनों कार्यों के

लिए अभिनंदन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा कि पहले कहा गया, बहुत सारे वक्ताओं ने जो कहा, उससे मुझे लगता है कि इनको यहाँ बहुत confusion हो रहा है।

(4जी/डी0एस0 पर क्रमश:)

-PSV/SSS-DS/4G/6.25

श्री गोविंदराव आदिक (क्रमागत) : यह जो बिल लाया गया है, जैसा जेटली साहब ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि ये दो अलग-अलग बातें हैं। शुगरकेन प्राइस, किसानों के लिए, गन्ना उत्पादकों के लिए तय करना एक अलग बात है और लेवी शुगर की प्राइस तय करना एक अलग बात है। यह जो Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill है, यह सिर्फ लेवी शुगर की प्राइस तय करने के लिए लाया गया बिल है। किसानों को गन्ने की जो कीमत देनी है, उसके लिए शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर है। शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर के तहत एसएमपी भी यह गवर्नमेंट तय करती है और उसके मुताबिक प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को और किसानों को कीमत देनी होती है, यह अभी तक का हमारा कानून है। सवाल केवल इतना ही है कि जो एसएमपी तय की जाती है, वह ठीक तरह से तय नहीं की जाती है। यह हमारी शिकायत है। अगर यह एसएमपी ठीक तरह से तय की जाए अथवा निश्चित की जाए और जितना खर्चा किसानों को गन्ना उत्पादन करने में आता है, उसका हिसाब करके, उसके ऊपर अगर - जैसे यहाँ हमने मालिकों के लिए प्रावधान किया है, वह देखने लायक है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी उसके बारे में जरूर खुलासा करें।

इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, उसमें लिखा है कि Reasonable return on the capital employed in the business of manufacturing of sugar. जब लेवी प्राइस तय करनी होगी, तब इसके ऊपर भी विचार करना होगा, लेकिन जो manufacturer है, उसका जो खर्चा आता है, उसका हिसाब करते समय, यह जो कहा है कि reasonable return, मतलब क्या है reasonable return का? Reasonable return का मतलब होता है, जैसा कि उन्होंने own explanation में दिया है, reasonable return on the capital employed means the return on the net fixed assets plus working capital of producer in relation to manufacturing of sugar including the

procurement of sugarcane at a fair and remunerative price determined under this section. सर, इसमें यह बात साफ है कि reasonable return जो तय की जाती है, reasonable return का मतलब साफ है कि उनका जो capital investment है, उसको भी यहाँ secure किया गया है। जो वे working capital लगाते हैं, उसके लिए भी उनको पूरा-पूरा मुआवजा मिलने वाला है, उसकी कीमत मिलने वाली है और profit मिलने वाला है। ये दो बातें ध्यान में रख कर उनको अगर आप reasonable return देने वाले हैं तो हम कहेंगे कि हमारे किसानों को, जो गन्ना उत्पादन करता है और आपको शुगर बनाने के लिए देता है, उसको भी reasonable price मिलनी चाहिए। आप जिन factors पर विचार reasonable return में manufacturer के लिए करते हैं, आपको शुगरकेन की प्राइस तय करते समय भी उन्हीं factors पर विचार करना चाहिए, जैसा कि उसमें profitability हो। (समय की घंटी) अगर manufacturer को काम करना है और इसमें profit भी include करना है तो किसानों को भी profit देने की जरूरत है। किसान क्यों नहीं profit प्राप्त कर सकते हैं? उनको भी profit मिलनी चाहिए और उनका जो उत्पादन का वास्तविक खर्चा आता है, वह खर्चा पकड़ कर जो कीमत होगी, वह कीमत fair and remunerative price में होनी चाहिए।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप यह खुलासा जरूर कीजिए कि यह fair and remunerative price का exactly मतलब क्या होगा? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपने manufacturer को जो reasonable return देने का वादा किया है, वैसे ही किसानों को आप reasonable return देने वाले हैं या नहीं? आप दोनों को एक न्याय दीजिए। अगर आप दोनों को एक न्याय देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Syed Azeez Pasha.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, it is 6.30 P.M now.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I think this morning we decided that we will sit up to 7.00 P.M.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, there are only two or three more speakers. We can go ahead.

SHRI VICE-CHAIRMAN: Okay.

SHRI S. S. AHLUWALIA: We can take it up tomorrow. We don't have business tomorrow. There is no business tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN: They are not agreeing.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, we have done two financial businesses today. Tomorrow we will take this up first. This will be first item tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN: In the morning it was decided that we will sit up to 7.00 P.M.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, last night it rained. It is very cold outside today. Why do you want to kill us? We will do it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN: What is the sense of the House?

(Followed by NBR/4H)

-SSS/NBR-AKA/4H/6.30.

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : कल पर लगाइए, कल करेंगे। ..(व्यवधान).. कल कुछ नहीं करना क्या? ..(व्यवधान).. कल पास नहीं करना क्या? कल क्या करना है? ..(व्यवधान)..Sir, we will do tomorrow...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMA: Ahluwaliaji, there is no consensus...(Interruptions)...They are not agreeing...(Interruptions)...What can I do?...(Interruptions)...They do not agree. What can I do? ...(Interruptions)...There is no consensus.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, listen to the Opposition also.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I always do that.

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is why I am saying...(Interruptions)...Sir, sometimes, you should also listen to the Opposition...(Interruptions)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, let us continue and finish the debate ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam Mabel, you cannot pass the Bill with your own strength...(Interruptions)...You need our help ...(Interruptions)... You need our support also...(Interruptions)...Please, keep this in mind ...(Interruptions)...Please, don't argue...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we can continue...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Rajiv Shukla, do you want to say anything?...(Interruptions)...Please, the suggestion from Shri Ahluwalia is that we should adjourn now. The decision taken in the morning was to sit up to 7.00 p.m. I would like to take the sense of the House ...(Interruptions)...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, when the decision was to sit up to 7 o' clock, we can sit up to 7 o' clock...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the decision in the BAC was that we sit up to 6 o' clock...(Interruptions)...That is the decision of the BAC ...(Interruptions)...There was no such decision that the House would sit up to 7 o' clock...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Then, what is the sense of the House?..(Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: Sir, we will sit up to 7 o' clock. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please, sit down...(Interruptions)...No, no. Sit down. There is no consensus...(Interruptions)...We will go ahead ...(Interruptions)...Please, Ahluwaliaji...(Interruptions)...There is no consensus.

SHRI V. HANU MANTHA RAO: Sir, we can sit up to 7 o' clock. ...(Interruptions)...

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : हनुमंत राव, मेरी आवाज बहुत ऊंची है, मेरे को आवाज मत सुनाओ। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN: There is no consensus ...(Interruptions)... Ahluwaliaji, please. There is no consensus ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, please listen to me ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Why are you insisting? ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am not insisting. Just listen to me. If you are interested to run the House with consensus, then, tomorrow onwards we will do that. It is up to you, carry on.

THE VICE-CHAIRMAN: I want your co-operation and proceed with the business. ...(Interruptions)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, the BAC takes a decision. Whenever there is some demand in the House, the person who is sitting in the Chair says, 'we cannot go beyond it, because it was the decision of the BAC.' Now, the BAC took a decision to sit up to 6 o' clock.

THE VICE-CHAIRMAN: It is 7.00 p.m.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir. It was 6 o' clock. ...(Interruptions)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Now, I am asking one question. Under which rule are you taking a decision that we sit beyond 6 o' clock? We know that it will not be over by 7 o' clock.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I will read the decision of the BAC which has already been communicated to this House. It is like this and I quote, "The Committee also recommended that the House may sit up to 6.00 p.m. and beyond as and when necessary for transaction of the Government Business."...(Interruptions)...

श्री सैयद अज़ीज़ पाशा : सर, 6 o' clock बोले हैं, छोड़ दीजिए। ..(व्यवधान).. 6 o' clock is there ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is up to 6 o' clock. ...(Interruptions)...We have gone beyond 6 o' clock. It is 6.30 p.m. ...(Interruptions)...It is over. ...(Interruptions)...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: If you take a decision, we will agree to sit even up to 12.00 p.m....(Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: Okay. Then, we will adjourn the House. ...(Interruptions)...

SPECIAL MENTIONS -- CONTD.

KLS/9U

NEED FOR IMPLEMENTATION OF NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS IN ASSAM

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, India has the second largest number of old persons in the world. In 1990, with the objective to provide ease and protection to the vulnerable elder people and to provide health care facilities to the elderly, the National Policy for Older Persons (NPOP) was announced by the Government of India.

As per the policy, the Government of India formed the National Council for Older Persons (NCOP). The Government also declared concession and facilities to senior citizens by different Ministries/Departments of the Government. Again, for the interest and benefit of the senior citizens, the maintenance and welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007 was introduced.

It is seen that, the maintenance and welfare of the Parents and Senior Citizen Act 2007 is yet to be implemented fully in Assam. On the other hand, the percentage of non-dependent elder persons is a very few. Therefore, the provisions for medical care of senior citizens of this Act very important for the State. As per Section 20, this Act specifically provided that there are earmarked facilities for geriatric patients in every district hospital duly headed by a medical officer with experience in geriatric care but the State has lack of such support for senior citizens. There is every need to establish an independent geriatric ward in every State Medical College and hospital in Assam. It is, therefore, urged that the Government of India take necessary steps for regular monitoring and review the implementation of the said Act, which is the need of the hour.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): The House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

*****

The House then adjourned at thirty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 16th December, 2009.